चिंतन

अर्थव्यवस्था पर संकट नहीं, चुनौतियां बरकरार

आर्थिकी
सतीश सिंह

भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती और लचीलापन साबित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों, खाड़ी संकट और व्यापारिक चुनौतियों के बीच यह प्रदर्शन न केवल उत्साहवर्धक है, बल्कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी बनाए रखता है। भारत का घरेलू उपभोग मजबूत हुआ है। बता दें कि 2025-26 वह साल रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। 50 फीसदी टैरिफ तक ट्रंप ने भारत पर लगाया, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन आंकड़ों से संतोष का भाव अवश्य पैदा होता है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चौथी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर का 12.8 प्रतिशत से घटकर 7.3 प्रतिशत पर आना बताता है कि उत्पादन गतिविधियों में अपेक्षित गति नहीं बनी हुई है। यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और औद्योगिक विस्तार का आधार यही क्षेत्र माना जाता है। यदि विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार कमजोर पड़ती है तो दीर्घकाल में इसका असर रोजगार और आय वृद्धि पर भी दिखाई दे सकता है। वर्ष 2026 की चुनौतियां और बड़ी हैं। तेल की बढ़ती कीमतें और इस बार कमजोर मानसून किसानों और लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। इससे जहां उत्पादन प्रभावित हो सकता है, वहीं सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के लिए कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस वित्त वर्ष में जीडीपी पूर्वानुमान में 30 बीपीएस की कटौती कर 6.9% से घटाकर 6.6% तक कर दिया है। यदि खाड़ी संकट जल्द हल नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह अनुमान और भी कम हो सकता है। इससे सरकार के सामने रोजगार सृजन, निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में संकट पैदा हो सकता है। हालांकि आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखकर संकेत दिया है कि सरकार पैनिक नहीं है और अर्थव्यवस्था दबाव में नहीं है, लेकिन कमजोर मानसून और अर्थव्यवस्था के लिए कई चुनौतियां बरकरार हैं। दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान यह संकेत देता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, मांग में उतार-चढ़ाव और निवेश संबंधी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सरकार और उद्योग जगत दोनों को विकास की गति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। कुल मिलाकर मौजूदा आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी संकट में नहीं है और उसकी बुनियाद मजबूत बनी हुई है, लेकिन केवल ऊंची विकास दर ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार, आय, निवेश और जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार दिखाई दे। इसलिए उपलब्धियों का स्वागत करते हुए चुनौतियों के प्रति सजग रहना ही समय की मांग है।

मुश्किलों के बीच सुधार के भी संकेत

सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि, जीएसटी संग्रह में स्थिरता और कंपनियों के बेहतर मुनाफे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन दोनों स्तरों पर गति बनी हुई है। फिर भी यह सुधार पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं है। घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर मौजूद चुनौतियां ताकीद करती हैं कि विकास की मौजूदा रफ्तार को स्थायी बनाने के लिए सतर्क नीति, संतुलित खर्च और लागत नियंत्रण जरूरी है। मई में भारत के सेवा क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल के 58 .8 से बढ़कर मई में 59 .8 पर पहुंच गया, जो पिछले 6 महीनों का उच्चतम स्तर है।

वैश्विक अनिश्चितताओं, महंगाई के दबाव, आपूर्ति शृंखला की बाधाओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि, जीएसटी संग्रह में स्थिरता और कंपनियों के बेहतर मुनाफे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन दोनों स्तरों पर गति बनी हुई है। फिर भी यह सुधार पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं है।

घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर मौजूद चुनौतियां ताकीद करती हैं कि विकास की मौजूदा रफ्तार को स्थायी बनाने के लिए सतर्क नीति, संतुलित खर्च और लागत नियंत्रण जरूरी है। मई में भारत के सेवा क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल के 58.8 से बढ़कर मई में 59.8 पर पहुंच गया, जो पिछले 6 महीनों का उच्चतम स्तर है। पीएमआई में 50 से ऊपर का स्तर विस्तार का संकेत है। यह आंकड़ा बताता है कि सेवा क्षेत्र में कारोबार, मांग और उत्पादन की गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। यह वृद्धि केवल घरेलू मांग तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की विदेशी मांग में भी सुधार दिखा। अप्रैल में आई गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज होना सकारात्मक संकेत है। सेवा क्षेत्र की मजबूती कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बड़ा योगदान है और रोजगार सृजन से लेकर निर्यात आय तक इसके असर व्यापक हैं। मई में माल ढुलाई, डिजिटल समाधान, ई-कॉमर्स, मनोरंजन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं की मांग बढ़ी। इसका सीधा असर कंपनियों की कारोबारी गतिविधियों पर पड़ा और कई कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि भी की। रोजगार के मोर्चे पर यह संकेत आश्वस्त करने वाला है, क्योंकि विकास तभी व्यापक माना जाता है जब उसका लाभ रोजगार और आय वृद्धि के रूप में आम लोगों तक पहुंचे। हालांकि, रोजगार वृद्धि में मामूली वृद्धि देखी गई है, क्योंकि 7 प्रतिशत से कम कंपनियों ने नई भर्ती की सूचना दी, जबकि अधिकांश कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि रोजगार सृजन का रुझान सकारात्मक जरूर है, पर उसे संतोषजनक नहीं माना सकता। भारत जैसे बड़े श्रम-प्रधान देश में केवल सेवा क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों की भर्ती पर्याप्त नहीं है। रोजगार वृद्धि को टिकाऊ बनाने के लिए विनिर्माण, निर्माण, कृषि-आधारित उद्योगों और छोटे उद्यमों में भी मांग और निवेश का विस्तार जरूरी है। औद्योगिक मोर्चे पर भी कुछ बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रही, जबकि मार्च में यह 3.2 प्रतिशत थी। इस सुधार में सबसे बड़ा योगदान विनिर्माण क्षेत्र का रहा, जिसकी वृद्धि दर अप्रैल में 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। बिजली और गैस क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि उत्पादन गतिविधियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में सुधार और पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि दर का 16 प्रतिशत तक पहुंचना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। पूंजीगत वस्तुओं की

मांग बढ़ना इस बात का संकेत है कि कंपनियां भविष्य की मांग को लेकर कुछ हद तक आश्वस्त हैं और वे विस्तार की तैयारी कर रही हैं। फिर भी, मौजूदा सकारात्मक संकेत को स्थायी नहीं माना जा सकता है। एक-दो महीनों के बेहतर आंकड़े से किसी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। राजकोषीय मोर्चे पर भी कुछ सकारात्मक संकेत हैं। वित्त वर्ष 2026 में कई मंत्रालयों और विभागों का खर्च संशोधित अनुमान से कम रहा, जिससे कुल व्यय में कमी आई और राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान से घट गया। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से यह अच्छा संकेत है, क्योंकि नियंत्रित घाटा सरकार को भविष्य में विकासोन्मुख खर्च के लिए अधिक गुंजाइश दे सकता है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि भी मांग और आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता का संकेत देती है। जीएसटी संग्रह का बढ़ना यह बताता है कि खपत और लेन-देन का दायरा बना हुआ है। लेकिन जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर को भी महंगाई और अनुपालन सुधार के संदर्भ में देखना चाहिए। अगर संग्रह में वृद्धि वास्तविक खपत और उत्पादन वृद्धि से आ रही है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ संकेत है; पर यदि इसका बड़ा हिस्सा कीमतों की वृद्धि से जुड़ा है, तो आम उपभोक्ता पर दबाव भी बढ़ सकता है। कॉर्पोरेट जगत के नतीजे भी अर्थव्यवस्था की मिश्रित लेकिन आशावादी तस्वीर पेश करते हैं। बैंकों ने मजबूत ऋण वृद्धि और बेहतर मार्जिन के सहारे अच्छे परिणाम दिए। ऑटोमोबाइल कंपनियों को मांग और वॉल्यूम का लाभ मिला। वहीं तेल, धातु और कुछ सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन मिश्रित रहा। इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में सुधार का स्वरूप समान नहीं है। कुछ क्षेत्र तेज बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्र लागत, कीमत और वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित हैं। सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और लागत दबाव की है। सेवा क्षेत्र की कंपनियों ने खाद्य पदार्थों, ईंधन, गैस, मजदूरी और कच्चे माल पर अधिक खर्च की बात कही है। पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों की अनिश्चितता, वैश्विक व्यापार नीतियों में उतार-चढ़ाव और मौसम संबंधी जोखिम से महंगाई में और भी इजाफ़ा हो सकता है। खाद्य महंगाई का सीधा असर आम परिवारों की रसोई और उपभोग क्षमता पर पड़ता है। यदि मानसून कमजोर रहता है या अल नीनो जैसी जलवायु परिस्थितियां कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं, तो खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। निर्यात क्षेत्र भी चिंता का विषय है। रुपये में कमजोरी के बावजूद भारत का माल निर्यात अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा। सामान्यतः कमजोर रुपया निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है, लेकिन जब वैश्विक मांग ही कमजोर हो तो इसका लाभ सीमित रह जाता है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती, व्यापारिक संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक तनाव भारतीय निर्यातकों के लिए बाधा बन सकते हैं। ऐसे में केवल मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर रहने के बजाय उत्पादकता, गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और बाजार विविधीकरण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। निष्कर्षतः भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल कठिनाइयों के बीच सुधार के संकेत दे रही है। सेवा क्षेत्र की मजबूती, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, पूंजीगत वस्तुओं की मांग, बेहतर कॉर्पोरेट नतीजे और राजकोषीय घाटे में कमी सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों को आत्मसंतोष का आधार नहीं बनाया जा सकता। महंगाई, कमजोर वैश्विक मांग, निर्यात की सुस्ती, मौसम संबंधी जोखिम और लागत दबाव अभी भी गंभीर चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह विकास की गति को बनाए रखते हुए महंगाई पर नियंत्रण रखे, निवेश को प्रोत्साहित करे, रोजगार को व्यापक बनाए और बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे।

(लेखक वरिष्ठ आर्थिक स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मुद्दा
रवि शंकर

पेट्रोल और डीजल जीएसटी से बाहर क्यों

देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर मध्यम वर्ग और रोज कमाने-खाने वाले लोगों में इसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे तेल के आयात पर असर पड़ा है। इसी वजह से तेल कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। बता दें कि पिछले 15 दिनों में यह चौथी बार है जब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों, यात्रियों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ वाहन चालकों की ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। वही देश के कई हिस्सों में इस समय कृषि कार्य, फसल परिवहन और आगामी बुवाई की तैयारियां चल रही हैं, जहां डीजल का व्यापक उपयोग होता है। ऐसे समय में डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही है। खेती की लागत बढ़ने से पहले से आर्थिक दबाव झेल रहा किसान और अधिक कर्ज के बोझ तले दबेगा। वर्तमान में देश के कई राज्यों और शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ईंधन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और लोगों को सीधी राहत मिलेगी। दरअसल, पेट्रोल की असल कीमत और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत में बड़ा अंतर टैक्स की वजह से है। मौजूदा समय में दिल्ली में बिकने वाले पेट्रोल की असली (बेस) कीमत सिर्फ 66.29 रुपये प्रति लीटर है। लेकिन इस पर केंद्र सरकार 11.90 रुपये प्रति लीटर का भारी-भरकम उत्पाद शुल्क वसूलती है। इसके बाद राज्य सरकार (दिल्ली सरकार) इस पर 16.03 रुपये का वैट लगा देती है। इसके अलावा, पेट्रोल पंप डीलर को प्रति लीटर 4.42 रुपये का कमीशन मिलता है। इन सभी शुल्कों को मिलाकर एक लीटर पेट्रोल के लिए उपभोक्ता को 100 रुपये से ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। यानी, लगभग 28 से 30 रुपये सिर्फ टैक्स के रूप में जनता की जेब से जा रहे हैं। वर्तमान समय में पेट्रोल पर वास्तविक मूल्य के मुकाबले करीब 42 प्रतिशत और डीजल पर लगभग 32 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है। अलग-अलग राज्यों में वैट की दरें अलग होने के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तेलंगाना में पेट्रोल सबसे महंगा है क्योंकि वहां पेट्रोल पर करीब 35.2 प्रतिशत वैट लगाया जाता है। वहीं अंडमान-निकोबार में पेट्रोल और डीजल पर केवल एक प्रतिशत वैट होने के कारण वहां ईंधन सबसे सस्ता बताया गया है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें अपने मौजूदा टैक्स (एक्साइज और वैट) को हटाकर ईंधन को जीएसटी के तहत लाती हैं, तो कीमतों में ऐतिहासिक कटौती हो सकती है। मान लीजिए कि डीलर का कमीशन जस का तस रहता है और तेल पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है, तो 66.29 रुपये के मूल दाम पर केवल 11.93 रुपये का टैक्स बनेगा। इस नए गणित के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत घटकर 78.22 रुपये प्रति लीटर रह जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि ग्राहकों को प्रति लीटर लगभग 22 रुपये की भारी बचत होगी। गौरतलब है कि 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था, तो वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी और कहा गया था कि देश में हर चीज पर एक समान टैक्स होगा और एक समान रेट होगा, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर सभी राज्य मनमानी करते हुए अपने अपने हिसाब से वैट वसूल रहे हैं। इसके कारण हर राज्य में पेट्रोल-डीजल की दरें अलग-अलग हैं। इससे वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर भी कुठाराघात हो रहा है। ये उत्पाद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। राज्यों को डर है कि जीएसटी के तहत इन उत्पादों को लाने से उनकी कर नीति, मूल्य निर्धारण और खपत को प्रभावित करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। कई राज्यों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जीएसटी में शामिल होने पर वे इस स्वायत्तता को खो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्यों की सहमति और कर दर पर एकरूपता जरूरी है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का फैसला केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति पर निर्भर करेगा, क्योंकि इससे राज्यों की टैक्स आय पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे टैक्स से होने वाली बड़ी कमाई प्रभावित होगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सत्य के प्रति जागने में ही है 'जीवन की महत्ता'

संकलित
दर्शन

प्रत्येक व्यक्ति का इस जगत में आना एक संयोग है और यह संयोग परमात्मा की कृपा की देन है, लेकिन संसार में सभी के आने का संयोग कुछ पाने के लिए है, खोने के लिए नहीं। इसलिए कि खोना आसान है, परंतु पाना बहुत ही कठिन है। संसार में प्रायः लोग सोने वाले हैं, जागने वाले कम। जागने वाले ही कुछ पाते हैं और सोने वाले सब कुछ खो देते हैं। जागने वाले ही इस संसार में जीवित हैं और सोने वाले मृत। सच्चाई के लिए जागना ही है, जड़ता का त्याग। जड़ता के त्याग के बिना पशुता की स्थिति से उबरना संभव नहीं है। जड़ता सुषुप्ति की अवस्था है और जड़ता का त्याग जागृतावस्था। जागृतावस्था में जीवन के उत्थान, विकास, महानता प्राप्ति का संयोग है और सुषुप्तावस्था में मृत्यु, पतन, अवनति, निंदा, दुखभरी स्थिति है। जागने में भलाई है और सोने में बुराई है। यह पतन की ओर ले जाने वाला है। व्यक्ति जन्म के समय न कुछ लेकर आता और न ही मृत्यु के समय कुछ लेकर जाता है। झूठ बोलकर की गई सारी कमाई यहीं रह जाती हैं, लेकिन सत्य की कमाई सदा साथ रहती है। त्याग, प्रेम, सत्य, जिम्मेदारी के प्रति जागना ही जीवन में सत्कर्म है और यह सत्कर्म ही पुण्य की कमाई है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। परमात्मा तो सिर्फ सत्य मार्ग पर चलने वाले का साथ देता है और कुमार्गगामी को दंड भी देता है। सत्य के प्रति सजगता ही चेतना का ऊर्ध्वमुखी होना होता है। इसके विपरीत असत्य के प्रति चेतना की जागृति विनाश, पतन का मूल है।

ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है

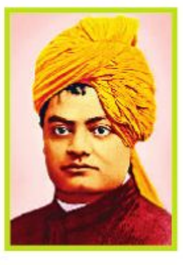

संकलित
प्रेरणा

एक बार स्वामी विवेकानद जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा- स्वामीजी मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा-लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को स्वामीजी ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने युवक से कहा- भाई! थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो। उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। कुत्ते को सैर कराने के बाद, जब एक युवक आश्रम में पहुंचा तो वह देखा कि युवक का चेहरा तेज है लेकिन उसका छोटा कुत्ता थक के जोर-जोर से हांफ रहा था। स्वामीजी ने पूछा- भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो। क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक ने कहा- स्वामीजी, मैं धीरे-धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता अशांत था। सभी जानवरों के पीछे दौड़ता था, इसीलिए बहुत थक गया था। तब विवेकानंद ने कहा- भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है! तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उससे दूर चलते हो। अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो और तुम जो चाहते हो वह दूर हो जाता है। युवक ने विवेकानंद के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया। अतः अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और भटकाने वाली सोच से दूरी बनाओ।

अंतर्मन

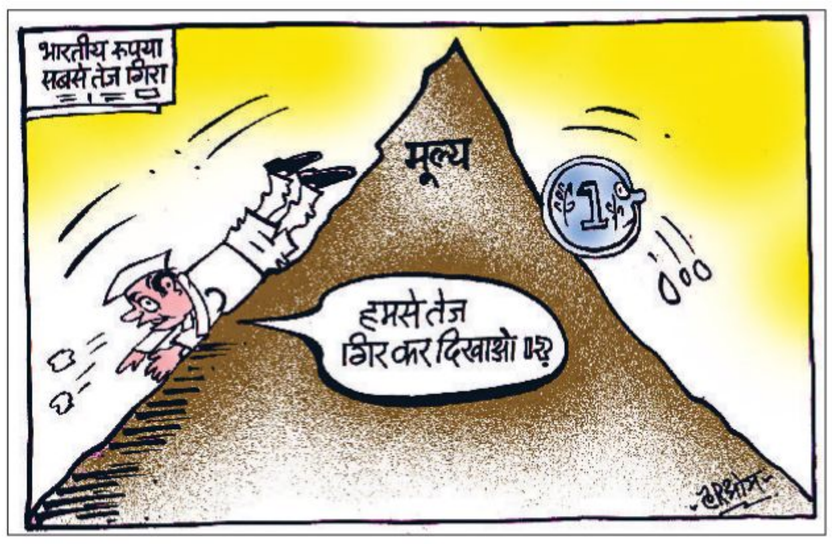

आज की पाती

पर्यावरण संरक्षण : आज का संकल्प, कल का भविष्य

धरती केवल मिट्टी, जल, वायु और पेड़ों का समूह नहीं है। यह मानव सभ्यता की जननी है, जीवन की धड़कन है और आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी धरोहर है। जब भी सुबह का सूरज पर्वतों की चोटियों को सुनहरी आभा से भर देता है, जब नदियों का निर्मल जल कल-कल करता हुआ बहता है, जब खेतों में हरियाली लहराती है और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में संगीत घोल देता है, तब प्रकृति अपनी सुंदरता का परिचय देती है। किंतु आज यही प्रकृति मानव की अंधाधुंध महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण कराह रही है। बढ़ता प्रदूषण, कटते जंगल, सूखती नदियां, पिघलते हिमनद, बढ़ता तापमान और असंतुलित मौसम मानव को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि अभी नहीं संभले, तो आने वाला भविष्य अत्यंत भयावह हो सकता है। - चेतन वर्मा, धमतरी

ट्रेंड

विकास गति मजबूत

भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा उल्लेखनीय गति पकड़ रही है। एयरटेल ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की घोषणा की है।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नमो ऑक्सीजन पार्क

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की गरिमामयी उपस्थिति में, मेगा वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया गया और दिल्लीवासियों को 18 नमो ऑक्सीजन पार्क समर्पित किए गए दिल्ली के सभी निवासियों से आग्रह है कि वे 'मां के नाम एक पेड़' अभियान में शामिल हों।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई

अगर ड्रग माफिया ने अपनी हरकतें नहीं सुधारीं, तो वे धूल में मिल जाएंगे। हमारी सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को सख्ती से लागू करके ड्रग तस्करों के नेटवर्क पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं।
-सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम, हिमाचल प्रदेश

सड़कों पर उतरें

अखबारों में खबरें लीक करना अरबों-खरबों का कारोबार है। इस रैकेट में बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सड़कों पर उतर कर सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, यह रैकेट नहीं रुकेगा।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने तीन कॉटेज किराए पर देकर पैसा कमाया

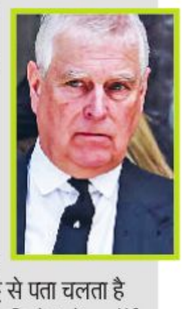

ब्रिटेन की सार्वजनिक व्यय पर निगरानी रखने वाली संस्था की शुक्रवार को जारी शाही परिवार की संपत्तियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रिंस एंड्रयू ने शाही संपदा में तीन कॉटेज किराये पर देकर पैसा कमाया, जहां वह दो दशक तक बिना किराए के रहे थे। इसमें यह भी बताया गया है कि उनकी बेटिया, प्रिंसेस बीट्राइस और प्रिंसेस यूजनी, किराए वाली महल की संपत्ति में रहती हैं, जिसका भुगतान उनके पिता के बड़े भाई महाराजा चार्ल्स तृतीय करते हैं। 'नेशनल ऑडिट ऑफिस' की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को विंडसर कैसल के पास अपने घर, रॉयल लॉज एस्टेट में कॉटेज को 20 साल से अधिक समय तक किराए पर देने से आय प्राप्त हुई। साल 2003 में किए गए रॉयल लॉज के एक पट्टे से पता चलता है कि उन्होंने संपत्ति के लिए सिर्फ एक मामूली रकम अदा दी, जिसे /"पेपरकॉर्न रेंट/" के नाम से जाना जाता है। इस परिसर में 30 कमरों वाली एक हवेली और आठ कॉटेज शामिल हैं जिनमें से तीन को किसी और को किराये पर देने की अनुमति थी। रिपोर्ट में आय की रिपोर्ट शामिल नहीं की गई थी। संसद की लोक लेखा समिति की पूर्व प्रमुख और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेबर पार्टी की सदस्य मारग्रेट होज ने इस चूक को चिंताजनक बताया।

ऑफ बीट

एआई में अत्यधिक पानी का इस्तेमाल हो सकता है

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक नई रिपोर्ट ने गंभीर चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक एआई से जुड़ी प्रणालियां दुनिया की कुल बिजली खपत का लगभग तीन प्रतिशत हिस्सा उपयोग कर सकती हैं, जबकि डेटा केंद्रों की शीतलन जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी वैश्विक आबादी की वार्षिक पेयजल आवश्यकता से भी अधिक हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई की बढ़ती क्षमता और लोकप्रियता के साथ उसके पर्यावरणीय प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि एआई मॉडल समय के साथ अधिक दक्ष और कम ऊर्जा खपत वाले हो जाएंगे, जिससे उनकी पर्यावरणीय लागत घटेगी। हालांकि, रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यह धारणा भ्रामक हो सकती है। रिपोर्ट में 'जेवॉन्स पैराडॉक्स' का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी तकनीक की दक्षता बढ़ने पर संसाधनों की कुल खपत कम होने के बजाय बढ़ सकती है। यह सिद्धांत 19वीं सदी के अर्थशास्त्री विलियम स्टेनली जेवॉन्स के अवलोकन पर आधारित है, जिन्होंने पाया था कि कोयले के उपयोग की दक्षता बढ़ने के बावजूद उसकी कुल मांग और खपत में वृद्धि हुई थी।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है।
मगर प्रयास छोड़ देने पर आप की असफलता सुनिश्चित है।
– बेवेरली सिल्स

अनदेखी की आग

कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वह गलती बनी रहती है या उससे सबक लेकर भविष्य में सावधानी बरतने और बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता। दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल में दो दिन पहले आग लगने से इक्कीस लोगों की जान चली गई। इसके अलावा, बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से कई जगहों पर रिहाइशी इमारतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। जहां तक मालवीय नगर की घटना का सवाल है, तो यह संभव है कि वहां अचानक लगी आग पूरी इमारत में फैल गई। मगर इतने लोगों के मारे जाने के बाद अब जो तथ्य उजागर हो रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि इस हादसे की समूची भूमिका पहले से तैयार थी और इसमें इमारत के मालिक से लेकर सरकार के संबंधित महकमों के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी थी।

सवाल है कि अगर होटल के पास दिल्ली अग्निशमन विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिर छह कमरों के लाइसेंस पर अगर पच्चीस कमरे अवैध रूप से बना कर कारोबार संचालित किया जा रहा था, तो यह किसकी अनदेखी से संभव हुआ? धोखाधड़ी करके इमारत के भूतल पर एक पूरी रेस्तरां चलाई जा रही थी, तो क्या यह कोई छिपी गतिविधि थी? जिस इमारत में अलग-अलग कारणों से हर समय खासी संख्या में लोगों के मौजूद होने की स्थिति थी, वहां आग लगने या अन्य किसी आपात स्थिति में बचने के लिए बाहर निकलने का रास्ता बाधित क्यों था? इलेक्ट्रानिक लाक प्रणाली से जोखिम की आशंका होने के बावजूद मुख्य दरवाजे के खुलने-बंद होने की डिजिटल व्यवस्था की अनुमति किसने दी थी? सच यह है कि इमारत में जो हादसा सामने आया, वह सिर्फ कमाई की अदम्य भूख में सुरक्षा इंतजामों के अनिवार्य पहलू को लेकर एक आपराधिक लापरवाही और सरकार के संबंधित महकमों की ओर से की गई अफसोसनाक अनदेखी का नतीजा है।

दरअसल, नियमों को ताक पर रख कर चलाई जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र के संचालक तभी ऐसा कर पाते हैं, जब पुलिस या अनिवार्य व्यवस्थागत इंतजामों की समय-समय पर जांच और निगरानी करने वाले अधिकारी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने की छूट देते हैं। इसके पीछे अवैध लेनदेन पर आधारित सांठगांठ हो सकती है! विडंबना यह है कि जो लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उन्हें इस बात की शायद कोई फिक्र नहीं होती कि उनकी ऐसी हरकतों का अंजाम कितना त्रासद हो सकता है। अगर कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तो सरकार और पुलिस की ओर से आनन-फानन में फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त सक्रियता दिखती है। मगर ऐसे हादसों की जांच के नतीजे, कानूनी कार्रवाई और सजा की हालत यह है कि वह शायद ही किसी सबक के लिए उदाहरण साबित होती है। जरूरत इस बात की है कि खासतौर पर ज्यादा लोगों के जमा होने वाली इमारतों में आग लगने या किसी भी अन्य वजह से जोखिम पैदा होने की आशंका वाली जगहों के सुरक्षा इंतजामों को लेकर कोई समझौता न हो। साथ ही नियमों की अनदेखी करने या उन्हें ताक पर रख कर गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ उचित सख्ती बरती जाए।

हिंसा का सिलसिला

मणिपुर में सरकार के तमाम दावों के बावजूद हिंसा की घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। सामुदायिक संघर्ष, उग्रवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता और सुरक्षाबलों की उदासीनता से राज्य में कानून व्यवस्था फिर से पटरी से उतरती प्रतीत हो रही है। ऐसे में शांति कायम करने की दिशा में राजनीतिक इच्छाशक्ति, गंभीरता और संवेदनशीलता का अभाव भी साफ नजर आता है। यही वजह है कि राज्य में उग्रवादियों के लक्षित हमले, आमजन को बंधक बनाने, निर्दोष लोगों की हत्या करने, आगजनी और इन वारदात के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। शुक्रवार को भी कांगपोकपी जिले में एक गांव पर सशस्त्र हमलावरों ने धावा बोल दिया और गोलीबारी में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि आखिर हिंसा की यह चिंगारी अंदर ही अंदर क्यों सुलगती जा रही है? दरअसल, यह सिर्फ कानून-व्यवस्था की ही समस्या नहीं है, बल्कि आम लोगों में पनप रहा अविश्वास और असुरक्षा की भावना भी इसकी बड़ी वजह है।

गौरतलब है कि मणिपुर बीते तीन साल से भी अधिक समय से जातीय हिंसा का दंश झेल रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच राज्य और केंद्र सरकारों की ओर से हालात पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए। हालांकि, पिछले कुछ समय में राज्य में हिंसक घटनाओं में कमी देखी गई, लेकिन इन पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। राज्य सरकार का दावा है कि हिंसक वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। यह बात सच है कि केवल सामाजिक मतभेद इतने लंबे समय तक हिंसा को जीवित नहीं रख सकते। असली समस्या तब पैदा होती है जब लोगों का सरकार और प्रशासन पर भरोसा टूटने लगता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राज्य में उग्रवादी समूहों पर कड़ी नजर रखी जाए, हिंसक घटनाओं में तत्काल कार्रवाई की जाए और आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए सरकार स्थायी समाधान तलाशने का प्रयास करे।

विकास की चमक में गुम बेघर लोग

जब दुनिया तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और शहरी विस्तार का दावा कर रही है, तब विकास की चमक के पीछे एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जिसके सिर पर छत तक नहीं है।

देवेंद्रराज सुथार

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने ऐसी वैश्विक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो तेजी से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप लेती जा रही है। इसके अनुसार विश्व की लगभग चालीस फीसद आबादी, यानी लगभग 3.4 अरब लोग सुरक्षित, पर्याप्त और किफायती आवास से वंचित हैं। इनमें से एक अरब से अधिक लोग कच्ची बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ियों अथवा अत्यंत खराब आवासीय परिस्थितियों में जीवनयापन के लिए विवश हैं। यह स्थिति तब है जब दुनिया तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और शहरी विस्तार का दावा कर रही है। स्पष्ट है कि विकास की चमक के पीछे एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके सिर पर छत तक नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की 'विश्व शहर रिपोर्ट 2026' का विषय वैश्विक आवास संकट- कार्रवाई के मार्ग है। यह विषय केवल शहरी नियोजन का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है। आवास का संकट अब केवल गरीब देशों तक सीमित नहीं है। विकसित देशों में भी घरों की कीमतों, बढ़ते किराए और सीमित आवास उपलब्धता ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इसलिए आज आवास को केवल एक संपत्ति या आर्थिक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में देखने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। भारत विश्व की सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी शहरों में निवास करेगी। वर्तमान में भी करोड़ों लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की संभावनाओं की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मगर शहरी अवसंरचना और आवासीय योजनाएं तेजी से बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में एक ओर गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियों और अस्थायी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। एक सच यह भी है कि कई लोग अपने लिए घर खरीदने की स्थिति में भी नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर मकान की कीमत और आय का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में जहां यह अनुपात 9.3 था, वहीं 2023 में यह बढ़ कर 11.2 हो गया। मध्य और दक्षिण एशिया में यह आंकड़ा 16.8 तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ यह है कि औसत आय वाले व्यक्ति के लिए घर खरीदना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है। भारतीय महानगरों में स्थिति और भी गंभीर है।

मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में संपत्ति की कीमतें सामान्य आय वाले परिवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। जमीन की बढ़ती कीमतों, निर्माण लागत और निवेश आधारित 'रियल एस्टेट माडल' ने आवास को बुनियादी आवश्यकता से अधिक निवेश का माध्यम बना दिया है। आवासीय असमानता का प्रभाव केवल घर खरीदने तक सीमित नहीं है। विश्व के लगभग 44 फीसद परिवार अपनी आय का तीस फीसद से अधिक हिस्सा आवास पर खर्च कर रहे हैं। यह स्थिति परिवारों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। जब आय का बड़ा हिस्सा किराये या गृह ऋण की किस्तों में खर्च हो जाता है, तब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च सीमित हो जाता है। इससे गरीबी का दुश्चक्र और मजबूत होता है। भारत में भी महानगरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्यवर्गीय परिवार इसी समस्या का सामना कर रहे हैं।

> **अनुमानों के अनुसार 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी शहरों में निवास करेगी। वर्तमान में भी करोड़ों लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की संभावनाओं की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मगर शहरी अवसंरचना और आवासीय योजनाएं तेजी से बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में एक ओर गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, तो दूसरी ओर लाखों लोग झुग्गी-झोपड़ियों और अस्थायी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। एक सच यह भी है कि समाज का एक वर्ग अपने लिए घर खरीदने की स्थिति में भी नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर मकान की कीमत और आय का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।**

भारतीय शहरों में किफायती आवास की उपलब्धता तेजी से घट रही है।

गौरतलब है कि देश के आठ प्रमुख शहरों में किफायती आवास परियोजनाओं की हिस्सेदारी 2018 में 52 फीसद थी, जो 2025 तक घट कर केवल 17 फीसद रह गई। इसके पीछे मुख्य कारण जमीन-जायदाद बाजार का उच्च आय वर्ग की ओर झुकाव है। निजी भवन निर्माता अधिक लाभ कमाने के लिए महंगी आवास परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। नतीजा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लिए आवास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। यह स्थिति सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। भारत के अधिकांश बड़े शहरों में लाखों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सीवर, स्वास्थ्य सेवाएं और भूमि स्वामित्व का अभाव होता है। यहां रहने वाले लोग लगातार बेदखली, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का सामना करते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद ये नागरिक अक्सर नीतिगत प्राथमिकताओं से बाहर रह जाते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इसके अलावा, 'क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी' योजना ने मध्य और निम्न आय वर्ग को गृह ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। किफायती किराए वाले आवास परिसर, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना तथा विभिन्न राज्य स्तरीय योजनाएं भी आवासीय सुविधाओं के विस्तार में योगदान दे रही हैं। हालांकि कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। कई बार आवास निर्माण तो हो जाता है, लेकिन रोजगार केंद्रों से दूरी, परिवहन सुविधाओं की कमी और सामाजिक अवसंरचना के अभाव के कारण लोग वहां बसना नहीं चाहते। इसलिए आवास नीति को केवल घर निर्माण तक सीमित न रख कर समग्र शहरी विकास से जोड़ना आवश्यक है। आवास वित्त की समस्या भी गंभीर है।

यथास्थान उन्नयन, सामुदायिक भागीदारी, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक प्रभावी रणनीति सिद्ध हो सकती है। अहमदाबाद की स्लम नेटवर्किंग परियोजना जैसे उदाहरण बताते हैं कि समुदाय की भागीदारी से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। भविष्य की आवास नीति में जलवायु परिवर्तन को केंद्रीय स्थान देना होगा। ऊर्जा-कुशल भवन, हरित निर्माण सामग्री, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और आपदा-प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना समय की मांग है। इससे न केवल पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, बल्कि दीर्घकाल में आवास की लागत भी कम हो सकती है। आवास का प्रश्न केवल ईंट, सीमेंट और भूमि का प्रश्न नहीं है। यह मानव गरिमा और सामाजिक समानता का प्रश्न है।

एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर व्यक्ति को केवल आश्रय ही नहीं देता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अवसरों तक पहुंच भी सुनिश्चित करता है। यदि किसी समाज में करोड़ों लोग आवासीय असुरक्षा में जीवन बिताने को विवश हैं, तो उस समाज के विकास को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। शहरीकरण को केवल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। यदि शहरों को भविष्य के विकास इंजन के रूप में स्थापित करना है, तो उन्हें अधिक समावेशी, न्यायसंगत और रहने योग्य बनाना होगा। भारत के लिए भी यह समय है कि वह आवास को कल्याणकारी कार्यक्रम की सीमा से बाहर निकाल कर विकास नीति के केंद्र में स्थापित करे, क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकसित राष्ट्र की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि उसके प्रत्येक नागरिक के सिर पर सुरक्षित, सम्मानजनक और किफायती छत उपलब्ध है।

समय के घाव

राजेंद्र मोहन शर्मा

घाव तो वक्त की धूल तले दब जाते हैं, लेकिन समय खुद जो घाव करता है, चाहे वह किसी प्रियजन के बिछड़ने का हो, ढलती उम्र का हो, या हाथ से छूटे हुए सुनहरे अवसरों का, सत्ता या ताकत छूटने का, उसे वह कभी पुराना नहीं होने देता। जब भी हम थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं, वह यादों की गलियों से कोई पुराना कांटा उठाकर फिर से चुभा देता है। यह उसका 'तस्दीक' कराने का तरीका है। बाकी सारे घाव तो किसी न किसी तरह ढक जाते हैं, उन पर वक्त की गर्द जम जाती है, अपनों की झूठी-सच्ची हमदर्दी का लेप लग जाता है और धीरे-धीरे उन्हें पूरी तरह से भरने का एक मुकम्मल भरम भी हो जाता है। हम इंसान उस ढके हुए जख्म की खाल को देखकर मन ही मन तसल्ली की एक लंबी सांस लेते हैं और खुद को गुमराह करते रहते हैं कि चलो, बुरा दौर बीत गया, अब रास्ते सीधे हैं। लेकिन समय जो घाव देता है, वह किसी मरहम की बिसात नहीं मानता। समय अपने दिए जख्मों को हमेशा हरा रखता है। जब भी हमारी जिंदगी अपनी आपाधापी में थोड़ा-सा संभलने की कोशिश करती है, वह चुपके से उन्हें हरा कर देगा।

समय कोई शांत बहती हुई नदी नहीं है, जो किनारों को सहलाकर गुजर जाए। वह एक बेहद शातिर, सजग और बेरहम शिकारी है। जब हम अतीत के मलबे से निकलकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश में मुस्कुराने को हों, जब लगे कि हम वक्त की मार से बहुत आगे निकल आए हैं, ठीक उसी दौरान हमारे निकट से गुजरते पल पुरानी, भूली-बिसरी राहों से चुन-चुनकर नुकीले और जहरीले कांटे बटोर लाता है। वह हमारे कानों के बेहद पास आकर अपनी सर्द सांसों के साथ फुसफुसाता है कि मैंने जो घाव दिए हैं, तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें भरने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हर कोशिश मेरी मुट्ठी में है।

ऊपरी तौर पर जमी हुई वह ठंडी परत हमें कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या शायद कुछ सालों के लिए एक दिखावे की तसल्ली तो दे सकती है, हमें यह झांसा दे सकती है कि अब सब शांत है, लेकिन वह भीतर की आदिम आग को कभी बुझा नहीं सकती। वह सिर्फ एक अस्थायी आवरण है, एक कमजोर पर्दा है। जैसे ही स्मृतियों की कोई हल्की-सी सरसराहट होती है, या जिंदगी की राह में कोई नया अप्रत्याशित झटका लगता है, वह ऊपरी परत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह जाती है। भीतर से खौलता हुआ, लाल-तप्त, पिघला हुआ लावा फिर से पूरी शिद्दत के साथ बाहर उबल आता है और हम इंसान को एक ही झटके में अहसास हो जाता है कि हम जहां से चले थे, आज भी ठीक उसी जगह बेबस खड़े हैं।

अगर इस कड़वाहट को जीवन के यथार्थ पर कसकर देखा जाए, तो समय हमें इतने रूपों में तोड़ता है कि उनका कोई अंत नहीं है। जब वह हमारे किसी बेहद अजीज को, हमारी धड़कन के सबसे करीब रहने वाले इंसान को हमसे हमेशा-हमेशा के लिए छीन लेता है, तो वह जो खालीपन छोड़ जाता है, उसकी भरपाई कोई ताकत नहीं कर सकती। साल पर साल गुजरते जाते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, लोग हमारे चेहरे को देखकर झूठा दिलासा देते हैं कि अब तो हमें इसकी आदत हो गई होगी, लेकिन सच सिर्फ हमारा अकेलापन जानता है कि वह दर्द वक्त के साथ कम होने के बजाय और ज्यादा गाढ़ा और गहरा होता चला गया है। उम्र के एक आखिरी पड़ाव पर आकर जब हम थककर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समय के हाथों छूटे हुए बड़े फैसले, गलतियां और खोए हुए सुनहरे अवसर एक स्थायी और कभी न मिटने वाली टीस बन जाते हैं।

समय के ये न भरने वाले घाव ही वास्तव में हमें हमारी अंतिम सांस तक 'मनुष्य' बनाए रखते हैं। अगर समय के दिए सारे जख्म पूरी तरह भर जाते, हम सब कुछ भूलकर पूरी तरह बेफिक्र और चैन से सो जाते, तो हम एक संवेदनशील और जीवंत प्राणी न रहकर पत्थर की एक बेजान मूरत बन जाते। यह कसक, यह लगातार सालने वाली टीस और भीतर चौबीसों घंटे सुलगता हुआ लावा ही हमारी जिंदा चेतना के सबसे बड़े प्रमाण हैं। समय का असल मकसद सिर्फ हमें दर्द देना नहीं है, बल्कि उस दर्द के बहाने हमें हर सुबह यह याद दिलाना भी है कि इस पूरी कायनात में कुछ भी स्थायी नहीं है। न हमारी ये छोटी-छोटी खुशियां, न हमारा झूठा अहंकार, न हमारा यह अस्थायी साम्राज्य और न ही हमारा चाहा हुआ चैन। वह एक निष्ठुर और कठोर उस्ताद की तरह जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे पुराने जख्मों की खाल को अपने नाखूनों से कुरेदकर हमें हमारी असली औकात और इस पूरी जिंदगी की नश्वरता का तीखा पाठ पढ़ाता रहता है। हम इंसान के पास समय के इस बिछाए हुए जाल और उसके इस निर्मम चक्रव्यूह के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है।

रास्ता बस इतना ही रह जाता है कि हम इस डरावनी हकीकत को पूरी शिद्दत के साथ गले लगा लें। जब हम यह पूरी तरह मान लेते हैं कि समय के दिए ये गहरे घाव अब कभी नहीं भरेंगे, तो हम उन्हें जबरदस्ती भरने की वह नाकाम और थका देने वाली व्यर्थ कोशिशें हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। हम उस दहकते हुए लावे के साथ, उस उठती हुई कसक के साथ और उस मद्धम दर्द के साथ ही अपनी सांसों का तालमेल बिठाकर जीना सीख लेते हैं। हमारे भीतर छिपी हुई जिजीविषा उस असहनीय दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल और ताकत बना लेती है। घाव भरे न भरे, पर उस दर्द की भट्टी में जलकर जो व्यक्तित्व कुंदन की तरह निखरता है, वही समय के इस अंतहीन अट्टहास को सहने का माद्दा रखता है। समय रोज नए घाव देता रहेगा, भीतर का लावा सुलगता रहेगा और हम इंसान इसी कड़वी हकीकत के साए में मुस्कुराते हुए अपनी सांसों का सफर पूरा करते रहेंगे।

दुनिया मेरे आगे

> **समय के न भरने वाले घाव ही वास्तव में हमें हमारी अंतिम सांस तक 'मनुष्य' बनाए रखते हैं। अगर समय के दिए सारे जख्म पूरी तरह भर जाते, हम सब कुछ भूलकर पूरी तरह बेफिक्र और चैन से सो जाते, तो हम एक संवेदनशील और जीवंत प्राणी न रहकर पत्थर की एक बेजान मूरत बन जाते।**

कानून से बेखौफ

'लापरवाही की लपटें' (संपादकीय, 4 जून) पढ़ा। इसमें सही कहा गया है कि सख्त कानूनों के बावजूद जमीनी स्तर पर भवन निर्माताओं में नियमों के पालन का कोई डर नहीं है। दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में एक इमारत में आग लगने से कई लोगों की असमय मौत बहुत दुखद हादसा है। इस घटना के लिए भवन मालिक तो जिम्मेदार है ही, इलाके के संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मगर इससे पहले उसको भी कोई गड़बड़ी क्यों नहीं दिखी? खबरों के अनुसार होटल के पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था। इमारत की बनावट को देखते हुए सुरक्षा नियमों के तहत उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल भी नहीं सकता था। होटल प्रबंधक ने आग लगने की स्थिति में बचाव के क्या उपाय किए थे, यह तो जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा।

– युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

टूटती उम्मीदें

'बदलाव के बजाय' (संपादकीय 2 जून) पढ़ा। पश्चिम बंगाल में चुनाव पूर्व और बाद में हिंसक घटनाओं का इतिहास रहा है। इन चुनावों में लोगों ने बदलाव के लिए भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, तो उनमें यह उम्मीद जगी कि राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मगर पिछले दिनों जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा सांसद कल्याण बनर्जी हिंसा के शिकार हुए, यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। सरकार को इन घटनाओं को लेकर सख्ती बरतनी चाहिए। गौरतलब है कि चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री ने राज्य में 'बदले के बजाय बदलाव' और 'भय नहीं भविष्य' की बात करने की नसीहत दी थी। बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

चिंता के सबब

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पेट्रोल-डीजल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए चिंता का कारण बन गई हैं। अमेरिका-ईरान तनाव तथा अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक संकटों के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर आयात-निर्भर देशों पर पड़ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर दिखाई देना स्वाभाविक है। महंगाई बढ़ने से परिवहन, कृषि, उद्योग और घरेलू खर्च सभी प्रभावित होते हैं। उर्वरकों, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम नागरिकों का बजट बिगड़ता है। सरकार के सामने भी आर्थिक संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती होती है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

समर्पण का अभाव

आज पूरी दुनिया जिस मुकाम पर खड़ी है, वह जीने के लिए कोई सुकून भरा वातावरण नहीं दे रही है। मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया है। हरे-भरे वनों को तहस-नहस किया जा रहा है। सीमेंट की सड़कें बन रही हैं। यह विकास के नाम पर छलावा है। चारों ओर सीमेंट के जंगल उग आए हैं। इससे पर्यावरण में असंतुलन दिखाई दे रहा है। इस समय भीषण गर्मी जिस तरह से अपने तेवर दिखा रही है, वह आने वाले समय में और भी मुश्किलें खड़ी करेगी। बारिश के दिन भी अनिश्चित हो गए हैं। कभी अत्यधिक, तो कभी बेहद कम। सर्दी के मौसम में भी कोई संतुलन नहीं है। पर्यावरण के प्रति चिंता तो दिखती है, मगर उसे बचाने का वह समर्पण किसी में नहीं दिखता है। यह स्थिति निराशाजनक है।

– हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

दैनिक जागरण

छल से कुछ प्राप्त करना परमात्मा के विधान का अपमान है

कर्नाटक में कलह

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन होते ही मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने जिस तरह पसंदीदा विभाग न मिलने से खफा होकर त्यागपत्र दे दिया, उससे नवगठित सरकार के सामने सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति बन गई है। रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन मंत्रालय दिया गया था, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आया। उनका कहना है कि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग वाला मंत्रालय चाहिए। किसी सरकार में कौन मंत्री बने और उसे कौन सा विभाग मिले, यह तय करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन शायद रामलिंगा रेड्डी को इसकी परवाह नहीं। उन्हें मलाईदार समझे जाने वाला बेंगलुरु विकास विभाग चाहिए। उन्होंने जिस तरह मनचाहे विभाग की मांग करने के स्थान पर सीधे त्यागपत्र दे दिया, उससे यही पता चलता है कि वे यह मान बैठे थे कि उन्हें वही विभाग मिलेगा, जो उनकी प्राथमिकता में है। यदि अन्य मंत्री भी ऐसी ही चाहत रखने लगें तो फिर डीके शिवकुमार के लिए सरकार चलाना कठिन ही होगा। वैसे उनके सामने समस्या केवल रामलिंगा रेड्डी ने ही खड़ी नहीं की। एक अन्य मंत्री जमीर अहमद भी अपने मंत्रालय से नाखुश हैं। उनके समर्थक उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और मंत्री भी अपने विभागों से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया और कई मंत्री ऐसे हैं, जो बड़े नेताओं के सगे-संबंधी हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के बेटे भी शामिल हैं।

कर्नाटक में नई सरकार बनते ही जो कुछ देखने को मिल रहा है, वह मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की समस्या बढ़ाने वाला ही नहीं, पार्टी में गुटबाजी को नए सिरे से उभारने वाला भी है। कर्नाटक का मामला कुछ-कुछ पंजाब की याद दिला रहा है। वहां भी कांग्रेस नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हटाते ही गुटबाजी चरम पर पहुंच गई थी और फिर ऐसी स्थिति बनी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। फिलहाल कहना कठिन है कि कर्नाटक में क्या होगा, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में दो वर्ष शेष रह गए हैं, तब कलह के बीच नई सरकार के लिए ऐसा कुछ कर पाना कठिन होगा, जिससे कर्नाटक की समस्याओं का समाधान हो और कांग्रेस को मजबूती मिले। कर्नाटक का घटनाक्रम पार्टी नेतृत्व की भी मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह कांग्रेस शासित एक प्रमुख राज्य है और यह किसी से छिपा नहीं कि यहां भाजपा उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। यह शुभ संकेत नहीं कि जब कर्नाटक की जनता को एक सक्षम सरकार चाहिए, तब डीके शिवकुमार सरकार की शुरुआत कलह से हो रही है।

अब संपर्क पथ ध्वस्त

सड़क संपर्क के मामले में बिहार ने रिकार्ड कायम किया है। पुल-पुलियों का निर्माण हुआ है। सफर आसान हुआ है। लोगों का जनजीवन निश्चित रूप से आसान हुआ है। व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन, हाल के दिनों में पुल-पुलियों और संपर्क सड़कों की बदहाली की सूचनाएं आ रही हैं, वह निर्माण की गुणवत्ता पर सीधे संदेह पैदा कर रही हैं।

सच यह है कि निर्माण कार्यों का प्रथम लक्ष्य मुनाफा कमाना हो गया है

विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के ध्वस्त होने की सूचना पुरानी नहीं हुई है। बक्सर से एक नई सूचना आ गई। बक्सर रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में निर्मित रोड ओवरब्रिज के संपर्क पथ का एक हिस्सा शुक्रवार को धंस गया। इसे महज 15 दिन पहले ही सामान्य यातायात के लिए खोला गया था। राज्य सरकार कह रही है कि यह रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ। संपर्क पथ का निर्माण ठीक से हो नहीं पाया था। अब अगली कार्रवाई जांच के नाम पर होगी। लेकिन, बिना जांच किए यह तो कहा ही जा सकता है कि जो कुछ हुआ, वह लापरवाही के कारण हुआ। जांच लंबी चलेगी। कुछ लोग दंडित भी किए जाएंगे। भरोसा रखिए कि इसके बाद भी यह सिलसिला बंद नहीं होगा। सच यह है कि निर्माण का प्रथम लक्ष्य मुनाफा कमाना हो गया है। मुनाफे के हिस्सेदार वे भी होते हैं, जिनपर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में सड़क और पुल ढहेंगे ही।

जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौती

प्रकाश सिंह

मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 हटाने एवं माओवाद खत्म करने में जो प्रतिबद्धता दिखाई, वह घुसपैठ से निपटने में भी दिखानी होगी

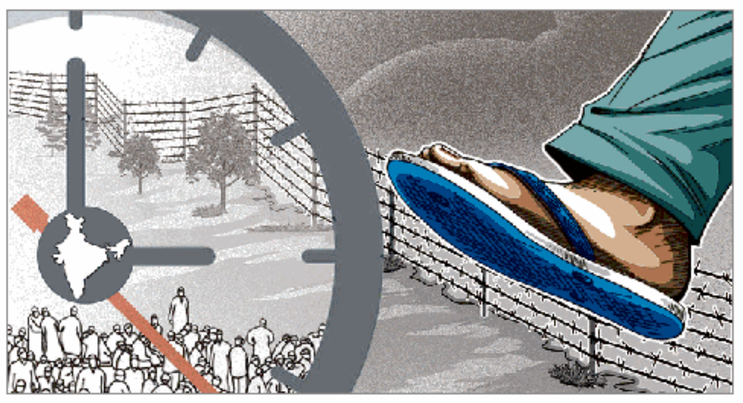

अवधेश राजपूत

देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण एवं उससे होने वाले प्रभाव के अध्ययन हेतु भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी घुसपैठ एवं कुछ सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों की जनसंख्या में असाधारण परिवर्तन के परीक्षण पश्चात प्रशासनिक एवं कानूनी ढांचे तथा नीतियों में परिवर्तन हेतु आवश्यक संस्तुति करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता वाली कमेटी के गठन की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ एवं अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी परिवर्तन से देश की शांति व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में ऐसे जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं, जो सामान्य नहीं हैं। ये अवैध घुसपैठ, अनियमित आवागमन और प्रशासनिक ढिलाई के कारण हुए हैं। यह परिवर्तन विशेष तौर से सीमावर्ती इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने गत वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, 'एक साजिश के तहत जनसंख्या को बदला जा रहा है। घुसपैठिये देश के युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, बहनों और बेटियों को निशाना बना रहे हैं, भोले भाले आदिवासियों को गुमराह कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर कार्रवाई हेतु ही उपरोक्त कमेटी का गठन किया गया है।

भारत में घुसपैठ की कहानी बड़ी लंबी है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो ऐसी आशा थी कि सांप्रदायिक सौहार्द होगा और बांग्लादेश सरकार आर्थिक क्षेत्र में ऐसे कदम उठाएगी कि किसी को अपना देश छोड़कर जीविकोपार्जन के लिए कहीं और न जाना पड़े, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक कारणों से भारी संख्या में लोग में घुसपैठ करते रहे और अनुमान है कि इनमें से 70 प्रतिशत मुसलमान थे। हिंदू मुख्य रूप से वहां प्रताड़ित होने के कारण भारत पलायन कर रहे थे। बांग्लादेश चुनाव आयोग के अभिलेखों को देखने से कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। 1991 में बांग्लादेश में कुल 6,21,81,745 वोटर थे, परंतु इस सूची से 1995 में 61,65,567 लोगों के नाम काटने पड़े, क्योंकि उनका कहीं अता-पता नहीं था। 1996 में फिर 1,20,000 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने पड़े, क्योंकि उनका भी कुछ पता नहीं चला। इतनी बड़ी संख्या में लोग हवा में नहीं गायब हो रहे थे। ये सब धीरे-धीरे भारत में घुसपैठ कर रहे थे। बांग्लादेश का बुद्धिजीवी वर्ग इस घुसपैठ का बराबर समर्थन कर रहा था।

असम के राज्यपाल रहते लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने आठ नवंबर, 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि असम में जिस तरह घुसपैठ हो रही है, उसे देखते हुए हो सकता है कि असम के सीमावर्ती मुस्लिम बहुल क्षेत्र को बांग्लादेश में मिला दिया जाए। बांग्लादेश में कुछ लोग 'ग्रेटर बांग्लादेश' की बात भी करने लगे थे।

कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स का गठन किया था। उनमें से एक माधव गोडबोले के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2000 में प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट लिखा है कि घुसपैठियों की संख्या एक करोड़ 50 लाख है। टास्क फोर्स के अनुसार तब प्रतिवर्ष करीब तीन लाख बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे थे। टास्क फोर्स ने सभी दलों को इस समस्या से निपटने में उदासीन बताते हुए लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में इस समस्या का संज्ञान लेते हुए इसे 'जनसांख्यिकी आक्रमण' कहा। इस तरह समय-समय पर चेतावनी मिलती रही, पर सरकारों के कान में जूं नहीं रेंगी और समय बीतने के साथ समस्या और गंभीर होती गई।

आज शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां बांग्लादेशी कुछ न कुछ संख्या में न हों। बंगाल और असम में तो इनकी बाढ़ है। 1951 में बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 51,18,269 थी, 2011 में यह संख्या बढ़कर 2,46,54,825 हो गई। यानी 381.7 प्रतिशत की वृद्धि। असम में 1951 में मुस्लिम जनसंख्या 19,95,936 थी, 2011 में यह उछलकर 1,06,79,345 हो गई। यानी 435.1 प्रतिशत की वृद्धि। आंकड़ों के अनुसार 1971 के बाद से हर दशक में मुस्लिम आबादी 80 से 85 प्रतिशत बढ़ी है। म्यांमार से भारी संख्या में रोहिंग्या भी घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में उच्च स्तरीय समिति का गठन सही दिशा में एक कदम है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने तक घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई को रोक नहीं जा सकता। भारत सरकार को तुरंत सभी राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि वे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें अग्रिम कार्रवाई तक होल्डिंग सेंटर्स में रखें। डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट एकदम सही नीति है। इस कार्रवाई से भी मुश्किल से 20-25 प्रतिशत बांग्लादेशियों की ही पहचान हो पाएगी। शेष के लिए भारत सरकार घोषणा करे कि घुसपैठिये स्वेच्छा से सामने आएं। उन्हें दो साल का पहचान पत्र/वर्क परमिट दिया जाए। इस आश्वासन के साथ कि वे भारत में रोजी-रोटी कमा सकते हैं, परंतु उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा और वे कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। दो साल बाद वर्क परमिट को बढ़ाने/समाप्त करने पर इस आधार पर विचार किया जाए कि उनका आचरण कैसा रहा।

मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने और माओवाद की समस्या को समाप्त करने में जो प्रतिबद्धता दिखाई, वह घुसपैठ की समस्या से निपटने में भी दिखानी होगी। अगर ऐसा होता है तो जिस आर्थिक, सामाजिक, और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की ओर समय-समय पर हमें आगाह किया गया था, उसका बहुत हद तक निराकरण हो सकेगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बीएसएफ के महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

सस्ती साबित की जाती लोगों की जान

पीयूष पांडे

दिल्ली के होटल में आग में फिर से वही लापरवाहियां सामने आईं, जो लगभग हर अग्निकांड के बाद सामने आती हैं

तबाही लाता नियम-कानूनों का उल्लंघन। प्रेट्र

वर्ष 2009 की बात है। ब्रिटेन के आक्सफोर्ड में 16 साल के एक स्कूली छात्र ने आत्महत्या की कोशिश से कुछ मिनट पहले फेसबुक पर लिखा, ''मैं अब बहुत दूर जा रहा हूं।'' अमेरिका में बैठी उसकी फेसबुक मित्र ने इस संदेश को पढ़ा तो उसने तत्काल अपनी मां को बताया। मां ने आनन-फानन में मैरीलैंड पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने व्हाइट हाउस के स्पेशल एजेंट से संपर्क साधा और उसने फौरन वाशिंगटन में ब्रिटिश दूतावास के अधिकारियों से। उन्होंने ब्रिटेन की मेट्रोपालिटन पुलिस से संपर्क किया और चंद मिनट बाद छात्र के घर का पता लगाकर पुलिस उसके घर जा पहुंची। जब तक वह घर के भीतर दाखिल हुई, छात्र नींद की बहुत अधिक गोलियां खा चुका था। वह बेहोश पड़ा था। पुलिसकर्मियों ने कुछ ही पलों में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान बच गई।

उक्त किस्सा बताता है कि यूरोप-अमेरिका में इंसान का जीवन कितना अनमोल है और सिर्फ एक जिंदगी बचाने के लिए कैसे एजेंसियां जमीन-आकाश एक कर देती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग से 21 लोगों की मौत ने एक बार फिर यह बात साबित की। प्रारंभिक जांच में फिर वही लापरवाहियां सामने आई हैं, जो लगभग हर अग्निकांड के बाद सामने आती हैं। उदाहरण के लिए होटल के पास सिर्फ छह कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे बनाए गए। होटल के पास अनिवार्य फायर एनओसी तक नहीं थी। इमारत में प्रवेश और निकास का सिर्फ एक दरवाजा था और कोई आपातकालीन द्वार नहीं था। इस हादसे में कई विदेशी भी मारे गए हैं।

विडंबना यह कि किसी हादसे से सीख नहीं ली जाती। बीते साल दिसंबर में गोवा नाइटक्लब में अग्निकांड हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। वह हादसा हाल के वर्षों का सबसे बड़ा "सिस्टम फेलियर" केस माना जाता है। इस अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच में सामने आया था कि क्लब अवैध निर्माण पर चल रहा था, फायर एनओसी नहीं थी, पर्याप्त आपातकालीन निकासी द्वार नहीं थे, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था और फायर अलार्म सिस्टम तक नहीं था। रिपोर्ट के ये निष्कर्ष इस तरह के लगभग हर अग्निकांड के बाद सामने आते हैं, जो साफ तौर पर नियामकीय विफलता दिखाते हैं। आग की घटनाओं के संदर्भ में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में लोग आग से कम, आग लगने से पहले की गई अनदेखी से ज्यादा मरते हैं। भारत में कई मामलों में मौत यहां कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का एक नियमित परिणाम है। दिल्ली के जनकपुरी में एक युवक सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिर जाता है। घंटों तक मदद नहीं मिलती और उसकी मौत हो जाती है। नोएडा में एक इंजीनियर की कार खुले नाले में जा गिरती है। उसकी मौत के बाद सुरक्षा प्रबंधों तथा प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक इमारत के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन छात्र डूबकर मर जाते हैं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन प्रशासनिक विफलता की कहानी वही रहती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2020 के बीच खुले गड्ढों और मैनहोल में गिरकर 5,393 लोगों की मौत हुई। यानी औसतन हर दिन दो भारतीय ऐसी मौत मरते हैं, जो पूरी तरह रोकी जा सकती थीं। भारत में हर बड़े हादसे के बाद एक तयशुदा पटकथा चलती है। जांच के आदेश दिए जाते हैं। मुआवजे की घोषणा होती है। कुछ अधिकारियों का तबादला होता है। फिर अगला हादसा हो जाता है। दुखद यह है कि भारत में मौतें अक्सर किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं होतीं। वे कई संस्थाओं की संयुक्त विफलता से होती हैं। ठेकेदार लापरवाह होता है, विभाग आंखें मूंद लेता है, निरीक्षण औपचारिकता बन जाता है और राजनीतिक व्यवस्था केवल हादसे के बाद सक्रिय होती है। परिणामस्वरूप नागरिक मरता है और तंत्र सिर्फ प्रेस कांफ्रेंस करता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव नहीं है। उसकी पहचान यह होती है कि वह अपने नागरिकों को कितनी सुरक्षा देता है।

भारत में नागरिकों को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उस जगह से दूरी बनाएं। कई जगह वे खुद भी कानून का उल्लंघन करने से नहीं हिचकते। देश में हर साल लगभग 1.8 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। इनमें से करीब 30 हजार लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं, क्योंकि वे हेलमेट नहीं पहने होते। देश की विशाल आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद संवेदनहीनता का कारण भी। बड़ी आबादी ने जान की कीमत को इतना कम कर दिया है कि न नागरिकों को और न सिस्टम को समझ आता है कि जीवन अनमोल है। एक विकसित समाज की नैतिकता का बड़ा पैमाना यह भी है कि वह अपने सबसे साधारण नागरिक की जान को कितनी अहमियत देता है। दुर्भाग्य से भारत बार-बार यह संदेश दे रहा है कि यहां मौत सस्ती है और जवाबदेही उससे भी सस्ती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संवेदनशीलता

संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। इसका अर्थ है कि दूसरों को सुखी देखकर हमें भी प्रसन्नता हो तथा दूसरों को दुखी देखकर हमारा हृदय द्रवित हो उठे और मन में करुणा के भाव जागृत हों। कहा गया है कि यदि आप पीड़ा को अनुभव करते हैं तो आप जीवित हैं और यदि आप दूसरों की पीड़ा का दर्द अनुभव करते हैं तो आप सचमुच इंसान हैं।

संवेदनशीलता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। इसे हमें अपने हर छोटे-बड़े कार्य में उतारना होता है, चाहे वह वार्तालाप हो, व्यवहार हो या हमारी दैनिक आदतें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनकी संवेदनशीलता उनके व्यवहार से स्पष्ट झलकती है। वे किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी या क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच-समझकर और परिस्थिति को समझते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत, जिन लोगों में संवेदनशीलता की कमी होती है, वे अक्सर बिना सोचे-विचारे बोलते रहते हैं, जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।

संवेदनशीलता के दो प्रमुख रूप देखे जा सकते हैं। पहला, किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करना और उसकी सहायता के लिए आगे आना। दूसरा, किसी से वार्तालाप करते समय कठोर शब्दों के स्थान पर विनम्र, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना। जब हम संवेदनशीलता को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तभी सच्चे अर्थों में अच्छे और संवेदनशील इंसान कहलाने योग्य बनते हैं। संवेदनशीलता केवल लोगों के प्रति हमारे व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वस्तुओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी दिखाई देती है। हम वस्तुओं को कितनी सावधानी और व्यवस्थित ढंग से रखते हैं अथवा लापरवाहीपूर्वक इधर-उधर फेंक देते हैं, यह भी हमारी संवेदनशीलता का परिचायक है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

राजधानी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

डा. रमेश ठाकुर

दिल्ली की पहचान विकास, सुरक्षा और सुशासन से होनी चाहिए, न कि बार-बार होने वाले अग्निकांडों से

मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दिल्ली में आग की घटनाएं कब रुकेंगी? आए दिन किसी न किसी इलाके से आग लगने की खबर आती है और हर बार कुछ निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक गहरे संकट का संकेत है। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मुंडका, विवेक विहार, पालम, पहाड़गंज, मंडावली और चांदनी चौक जैसी अनेक घटनाओं ने राजधानी को झकझोर दिया है। विवेक विहार स्थित अस्पताल में लगी आग में नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जबकि पालम में एक ही परिवार के कई सदस्य जिंदा जल गए थे। इन घटनाओं के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता।

इन हादसों के पीछे सबसे बड़ा कारण अवैध और अनियोजित निर्माण है। अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और होटल निर्धारित मानकों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे हैं। जहां सीमित कमरों की अनुमति होती है, वहां कई गुना अधिक निर्माण कर लिया जाता है। अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार और सुरक्षा व्यवस्था जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि संबंधित विभागों की उदासीनता और भ्रष्टाचार भी ऐसी स्थितियों को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में हर महीने सैकड़ों अग्निकांड दर्ज किए जाते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की अधिक खपत, शार्ट सर्किट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण घटनाएं और बढ़ जाती हैं। इसके बावजूद न तो भवन स्वामियों में जागरूकता दिखाई देती है और न ही प्रशासन पर्याप्त कठोरता से नियमों का पालन सुनिश्चित कर पाता है।

हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच समिति बनती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है और मुआवजे की घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और व्यवस्था अगले हादसे का इंतजार करने लगती है। यही कारण है कि जनता का विश्वास लगातार कमजोर हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि अग्नि सुरक्षा को केवल औपचारिकता न समझा जाए। सभी व्यावसायिक और आवासीय भवनों का नियमित सुरक्षा आडिट हो, अग्निशमन विभाग को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाए तथा नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नागरिकों में भी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। दिल्ली की पहचान विकास, सुरक्षा और सुशासन से होनी चाहिए, न कि बार-बार होने वाले अग्निकांडों से। मालवीय नगर जैसी त्रासदियां की अनदेखी भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

ममता का बुरा वक्त

'मूल से उखड़ती तृणमूल' शीर्षक से युक्त संपादकीय में तृणमूल कांग्रेस के अधोपतन का विश्लेषण पढ़ा। जिसमें स्पष्ट किया गया कि परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग ने 'तृणमूल' को उसके 'मूल' से उखाड़ दिया। पार्टी नेताओं के भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण और राज्य में बढ़ती अराजकता के कारण इस बार ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेताओं से प्रताड़ित डरे-सहमे जनमानस को जब सुरक्षित माहौल में वोट डालने का अवसर मिला तो उसने ममता बनर्जी के कुशासन का हिसाब चुकता करते हुए भारी बहुमत के साथ बंगाल की कमान भाजपा को सौंप दी। ममता बनर्जी के हाथ से राज्य की सत्ता खिसकते ही उन्हें न केवल जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, अपितु उनके लिए तृणमूल कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को एकजुट रखना भी मुश्किल हो गया। राज्य की सत्ता गंवाने के बाद पार्टी में इतना बड़ा विघटन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। विपक्षी नेता के रूप में अब विधानसभा के अंदर और बाहर उनकी दबंगई नहीं चल पाएगी। एक राजनीतिक दल की मुखिया के रूप में ममता बनर्जी का यह सबसे बुरा वक्त है, जब उनके पास न सत्ता है और न ही पार्टी की हनक। वर्तमान में वह बुरी तरह से टूटी-बिखरी तृणमूल कांग्रेस की हताश नेता हैं।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

छात्रों पर मानसिक दबाव

नीट की परीक्षा निरस्त होने से हताश और दोबारा देने में असमर्थता जताते हुए एक छात्रा द्वारा आत्महत्या और जांच के आदेश। लेकिन आखिर हर बार गलती होने के बाद ही व्यवस्था क्यों जागती है? जांच हमेशा हादसे के बाद ही क्यों होती है? सबसे हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद अचानक सारी कमियां सामने आने लगती हैं। तब पता चलता है कि कहीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा था, कहीं अवैध निर्माण किया गया था, कहीं इमारत जर्जर थी, कहीं पुल में पहले से दरारें थीं। क्या हमारी व्यवस्था अब इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उसे खतरे की नहीं, मौतों की सूचना चाहिए? क्या किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का मरना जरूरी हो गया है? एक तरफ करोड़ों रुपये की नई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं। नए अस्पताल, नए मेडिकल कालेज, नई इमारतें और नए विकास के वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर पहले से खड़ी इमारतों में लोग सुरक्षित नहीं हैं, अगर पुलों की मजबूती पर भरोसा नहीं है तो यह विकास किस काम का।

निकिता जोशी, कानपुर

मेलबाक्स

जैसा कदम अत्यंत निराशाजनक और दुखदाई है। यह हमारी परीक्षा प्रणाली की विफलता, सरकारी मुलाजिमों से लेकर आम आदमी का भ्रष्टाचार में संलिप्त होना और सरकार का गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण है। चंद लोग पैसों के लालच में अपना ईमान और जमीर बेच, नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर प्रश्न पत्र बेच लाखों अभ्यार्थियों के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। छात्रों की न जाने कितने वर्षों की मेहनत लगी होती है परीक्षा की तैयारी में और माता-पिता का बच्चों की कोचिंग और किताबों पर अथाह पैसा। जिसे कुछ लोग चंद पलों में पेपर लीक कर बर्बाद कर देते हैं। किसी भी अभ्यार्थी के लिए दोबारा से परीक्षा में बैठना और उसे अच्छे रैंक और नंबरों से पास करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, साथ ही मानसिक और भावनात्मक दबाव भी है। सरकार को प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने और पेपर लीक करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रविधान करना चाहिए।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

विकास या दिखावा

कभी पुल गिरता है, कभी होटल में आग लग जाती है। कभी कोई इमारत लोगों के ऊपर ढह जाती है, तो कभी एक खुला नाला किसी छात्र का भविष्य निगल लेता है। हर हादसे में सिर्फ कुछ लोग नहीं मरते, उनके साथ मर जाते हैं कई सपने, कई उम्मीदें और कई परिवारों की खुशियां। और फिर शुरू होता है वही पुराना सिलसिला-शोक संदेश, मुआवजे की घोषणाएं

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशनलि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

60 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है भारत, अपनी कुल खपत का। वर्ष 2024-25 में लगभग 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य लगभग 1.61 लाख करोड़ रुपये था।

आजकल

दलहन व खाद्य तेलों के उत्पादन पर जोर

वैश्विक हालात, विशेषकर अमेरिका-इजरायल और ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत में आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। डालर की तुलना में रुपया निरंतर कमजोर होने और निर्यात की तुलना में आयात कई गुना बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ा है। इसलिए आयात की जानी वस्तुओं के उपयोग को कम करने की सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। दलहन और खाद्य तेलों का भी देश बड़ी मात्रा में आयात करता है। ऐसे में हमें ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जिससे देश में इनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके

ज्ञानेश मिश्र
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल

प्रतीकात्मक

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिलाकर व्यापार घाटा लगभग 119.3 अरब डालर दर्ज किया गया। इस दौरान देश का कुल आयात 979.4 अरब डालर रहा, जबकि निर्यात 860.09 अरब डालर तक पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह व्यापार घाटा 94 अरब डालर से अधिक था, जो कि वर्ष 2025-26 में और बढ़ गया। यदि केवल वस्तुओं के व्यापार की बात करें, तो घाटा और भी अधिक रहा। व्यापार घाटा बढ़ने का मुख्य कारण सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात में तेजी आना रहा है। देश में पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर और उसके बाद पेट्रोल, डीजल व सीएनजी की कीमतें धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो गई हैं। इससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी और भाड़ा बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी।

देश में गेहूं और चावल का उत्पादन पिछले वर्षों में काफी बढ़ा है और वर्तमान में इनकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआइ) तथा निजी क्षेत्र के पास गेहूं का अच्छा भंडार उपलब्ध है।

दलहल व खाद्य तेल का आयात : भारत में चावल का उत्पादन भी काफी मात्रा में होता है तथा भारत इसका निर्यात भी करता है। फिलहाल देश में गेहूं और चावल की कीमतें स्थिर हैं और निकट भविष्य में इनमें बड़ी तेजी की संभावना भी कम दिखाई देती है। परंतु भारत अपनी कुल खपत का 60 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात किया, जिसकी कीमत 1.61 लाख करोड़ रुपये थी। वहीं 2025-26 में यह आयात बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

भारत में आयातित खाद्य तेलों- पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर कुल प्रभावी आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत, जिसमें 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क और अन्य उपकर हैं, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों पर मूल आयात शुल्क 32.5 प्रतिशत है, जो कि अन्य उपकर को मिलाकर कुल प्रभावी आयात शुल्क 35.75 प्रतिशत है। कुछ समय पूर्व कच्चे खाद्य तेल पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि अन्य उपकरों को मिलाकर 16.5 प्रतिशत पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में आयातित खाद्य तेलों के घरेलू बिक्री करने पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी भी लागू होता है, जबकि दालों में जीरो प्रतिशत है। पांच प्रतिशत जीएसटी से आयातित खाद्य तेलों व देश में निर्मित खाद्य तेल की कीमतें और बढ़ जाती हैं, इसलिए देश में तिलहन व खाद्य तेल में जीएसटी जीरो प्रतिशत होना चाहिए।

नेपाल से शुल्क मुक्त आयात : भारत में कुल खाद्य तेल के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा पाम आयल का है, जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। सोयाबीन आयल दक्षिण अमेरिकी देशों- अर्जेंटीना और ब्राजील से आता है। सूरजमुखी का तेल रूस और यूक्रेन से आता है। खाद्य तेल में खासकर सोया व अन्य खाद्य तेल भी इन सभी देशों से नेपाल में आने के उपरांत रिफाइंड, प्रोसेस व रीपैक होकर भारत आते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि नेपाल और भारत के बीच आयात व निर्यात होने पर 'साफ्टा' के तहत जीरो शुल्क है, इसलिए नेपाल से आने वाले खाद्य तेल पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता है। इसलिए नेपाल से काफी मात्रा में रिफाइंड, प्रोसेस व रीपैक होकर खाद्य तेल भारत में आता है। आयात शुल्क नहीं होने के कारण वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में नेपाल से खाद्य तेल का आयात दो गुना हो गया है। नेपाल से आयातित होने वाले खाद्य तेलों पर आयात शुल्क न होने के कारण भारत के तेल उद्योग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लिहाजा भारत के तेल उद्योग ने नेपाल से शुल्क-मुक्त आयात पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है।

तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता से मजबूत होगी आर्थिकी

पिछले कुछ समय से रुपये की तुलना में डालर की कीमत बढ़ने के कारण भारत में आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। विदेश से आने वाला पाम, सोया और सूरजमुखी तेल लगातार महंगा हो रहा है। आयातित तेल महंगा होने का असर देश में उत्पादित सरसों के तेल पर भी दिखाई दे रहा है, जिसकी कीमतों में भी तेजी आई है। इसी प्रकार दालों के आयात की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत अपनी कुल दाल खपत का 20 से 25 प्रतिशत आयात करता है। भारत मुख्य रूप से अरहर, चना, उड़द, मसूर और मटर का आयात करता है। पिछले दो वर्षों में कनाडा से मसूर, आस्ट्रेलिया से चना, म्यांमार और मलेशिया से उड़द व अरहर तथा तंजानिया और मोजांबिक जैसे अफ्रीकी देशों से अरहर का आयात हुआ है। वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 73 लाख टन दालों का रिकार्ड आयात किया, जिसकी कीमत लगभग 43 हजार करोड़ रुपये रही। वहीं वर्ष 2025-26 में लगभग 60 लाख टन दालों का आयात किया गया, जिसकी कीमत करीब 31 हजार करोड़ रुपये थी।

भारत में दालों का आयात बढ़ने का एक प्रमुख कारण आयात शुल्क में दी गई छूट भी है। अरहर और उड़द पर वर्तमान में शून्य प्रतिशत आयात शुल्क लागू है। इसके अलावा, दिसंबर 2023 से एक नवंबर 2025 तक पीली मटर पर भी शून्य प्रतिशत आयात शुल्क लागू था। बाद में इस पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। चना और मसूर पर अभी केवल 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू है। यदि इन सभी दालों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए, तो आयात में कमी लाई जा सकती है।

वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए दालों में 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने और खाद्य तेलों पर पूर्व में लागू 20 प्रतिशत मूल आयात शुल्क पुनः लागू करने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हालांकि इससे कुछ महंगाई अवश्य बढ़ेगी। साथ ही, भारत सरकार को दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयास और तेज करने होंगे। वैसे भारत सरकार ने दलहन व तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार द्वारा दलहन (दालों) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। इसी तरह तिलहन आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास और तेज करने होंगे।

वर्ष 2024-25 में देश ने खाद्य तेल और दालों का लगभग 2.04 लाख करोड़ रुपये का आयात किया। वहीं वर्ष 2025-26 में भी दलहन व खाद्य तेल का आयात लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये का रहा। यदि इस आयात को नियंत्रित किया जाए, तो डालर के रूप में विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों में भारी आयात के कारण देश में दलहन की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बिक रही थीं, जिससे दलहन उत्पादक राज्यों के किसान दलहन की बोआई कम करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तिलहन की बात की जाए, तो पिछले वर्ष कुछ समय के लिए तिलहन में सरसों व मूंगफली आदि की कीमतें एमएसपी के आसपास रही हैं और वर्तमान में सरसों की कीमत एमएसपी से अधिक है, क्योंकि इस समय खाद्य तेल के आयात में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए देश में तिलहन का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित बीज व खाद आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है।

भारत सरकार को दलहन और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर इनके आयात को नियंत्रित करने का निर्णय जल्द लेना चाहिए। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और वे अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। भारत सरकार तिलहन व खाद्य तेल में लागू पांच प्रतिशत जीएसटी को शून्य करे, जिससे देश के तेल उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार पहले से ही एमएसपी पर निर्धारित मात्रा में दलहन व तिलहन की खरीद करके किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

दलहन और तिलहन उत्पादक राज्यों के किसानों को विशेष प्रोत्साहन देना होगा। किसानों को प्रोत्साहन राशि, गुणवत्तापूर्ण बीज तथा पर्याप्त उर्वरक आसानी से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकार को दाल और खाद्य तेल के प्रतिवर्ष लगभग दो लाख करोड़ रुपये के आयात को नियंत्रित करने, खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, देश को दलहन एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों को प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने जैसे विषयों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। साथ ही, कृषि विशेषज्ञों, किसानों, दाल उद्योग से जुड़े व्यापारियों तथा मंडी के व्यापारी प्रतिनिधियों की एक समिति बनाकर हर तीन माह में सुझाव भी लिए जाने चाहिए। समय रहते सही कदम उठाए गए, तो इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और भारत आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकेगा। (ज्ञानेश मिश्र)

खरी-खरी

बचाव गैंग भी हैंग

राजेंद्र कुमार सिंह

कुछ दिन पहले पेपर लीक प्रकरण ने देश के नौजवानों, खासकर जेन जी को इस कदर झकझोर दिया कि बचाव पक्ष का पूरा गैंग ही हैंग हो गया। जो लोग कल तक हर सवाल का जवाब जेब में लेकर घूमते थे, वे अचानक नेटवर्क से बाहर दिखाई देने लगे। देश में इन दिनों एक नई जंग छिड़ी हुई है। यह जंग धीरे-धीरे ऐसा रंग बदल रही है कि समझदारों की अक्ल भी ठिकाने लग रही है। दोनों पक्ष अपने-अपने मोर्चे पर डटे हैं, लेकिन बचाव पक्ष तो मानो बरसाती मेढक की तरह मौका मिलते ही टर्राने लगता है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, उसके समर्थन में तराने तुरंत निकल पड़ते हैं।

पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा के अंकों को लेकर जब छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश बढ़ रहा था, तब यही बचाव ब्रिगेड चैन की बंसी बजा रही थी। लेकिन जैसे ही मामला सरकार की छवि पर असर डालने लगा, टीवी मीडिया के कुछ लोग सक्रिय हो उठे। उन्होंने छात्रों की पीड़ा पर चर्चा करने के बजाय उन्हें ही कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कोई उन्हें देशद्रोही बताने लगा, तो कोई उनकी जायज मांगों को राजनीति का रंग देने लगा।

पत्रकारिता के नाम पर यह ऐसा तमाशा था जिसमें खबर कम और चाटुकारिता ज्यादा दिखाई दे रही थी। लगता था मानो कुछ लोगों ने सत्ता की कृपा-दृष्टि पाने के लिए अपनी कलम को गिरवी रख दिया हो। नतीजा यह हुआ कि पत्रकारिता की खाट खड़ी होने लगी और उनके आकाओं का भी माथा ठनक गया। आगे क्या होगा, यह कहना कठिन है, लेकिन इतना तय है कि सरकार की ढुलमुल नीति जनता को भारी पड़ रही है। समस्या का समाधान निकालने के बजाय उसे आगे सरकाने की पुरानी आदत अब जनता को रास नहीं आ रही।

इस्तीफा देना शायद अब राजनीतिक शब्दकोश का अप्रचलित शब्द बन चुका है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। जनता सवाल पूछ रही है, छात्र जवाब मांग रहे हैं और आंदोलन बिना ठोस निष्कर्ष के थमता नहीं दिख रहा। बचाव गैंग चाहे जितना बचाव कर ले, फिलहाल तो वही ज्यादा हैंग होता नजर आ रहा है।

X पोस्ट

एक ऐसे समय जब भाजपा में घुसने के लिए नेताओं की लंबी लाइन लगी हो, अन्नामलाई ने बाहर का रास्ता ले लिया। हालांकि भाजपा और उससे पहले जनसंघ का यह इतिहास है कि इससे अलग होकर कोई नेता पनप नहीं सका। कल्याण सिंह, शंकर सिंह वाघेला, उमा भारती आदि की एक लंबी फेहरिस्त है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

शोध बताते हैं कि नकारात्मक समाचार सकारात्मक समाचारों की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक तेजी से फैलते हैं। ब्लूमबर्ग ने भारत के सोना बेचने की अपनी झूठी खबर को वापस ले लिया है, लेकिन अब तक वह व्यापक रूप से फैल चुकी होगी। गढ़ी गई या कृत्रिम रूप से निर्मित नैरेटिव से सावधान रहने की आवश्यकता है।
प्रो. शमिका रवि@ShamikaRavi

दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार हो गया, लेकिन वे सारे अधिकारी/बाबू/नेता कब गिरफ्तार होंगे, जिनकी जेबें गर्म कर, सारे नियम तोड़ कर वह होटल चल रहा था? जब तक ऐसे मामलों में इस देश के भ्रष्ट अधिकारी/बाबू/नेता गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बंद नहीं होंगी।
ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सूर्य कुमार यादव को टी-20 टीम की कप्तानी से हटाना सही है?

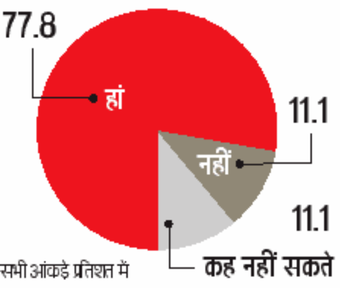

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या आरबीआइ का रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

खेड़ा बाबू आपको बढ़िया मिला इनाम,
नाम न होगा क्या भला जो होंगे बदनाम!
जो होंगे बदनाम बोलकर झूठ दिखाओ,
राज्यसभा की सीट आप घर बैठे पाओ।
उल्टा-सीधा बोल रोज जो करे बखेड़ा,
पाए वही इनाम पा गए जैसे खेड़ा!!
-ओम प्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

राबड़ी देवी के आवास पर क्यों मचा शोर

अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर फिल्मी संवाद चल रहा है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि वह सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल सरकारी आवास पर कब्जा नहीं कर सकता है। यह संपत्ति किसी की बपौती नहीं है। राबड़ी देवी के समर्थक और राजद नेता सूची जारी कर रहे हैं। इनमें उन लोगों के नाम हैं, जो मंत्री नहीं हैं। सांसद हैं। पूर्व विधायक हैं। वे उन आवासों में रह रहे हैं, जिनका निर्माण राज्य के मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए किया गया है।

सरकार की ओर से भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह सफाई दे रही हैं कि राजद की सूची में जिन्हें अवैध कब्जेदार बताया जा रहा है, वे सब बाजार दर पर किराया देकर सरकारी आवासों में रह रहे हैं। सरकारी भवनों के आवंटन के नियम में किराया भी एक आधार है। हां, यह सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह किसे किराया पर आवास देगी। ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी सरकारी कार्यालय में जाए और किराया का भुगतान कर मंत्री वाले आवास में रहने लगे। कुल मिलाकर बात यहां आकर ठहरती है कि सरकार जिसे चाहे, उसे ही किराये पर मंत्री वाला आवास मिल सकता है।

प्रश्न यह भी नहीं है कि राबड़ी देवी के पास राजधानी पटना में रहने का कोई और ठिकाना है या नहीं। उन्हें वर्तमान आवास के बदले दूसरा आवास आवंटित किया गया है। वह आवास छोटा नहीं है। प्रश्न यह भी नहीं है कि राज्य सरकार अगर राबड़ी देवी को वर्तमान आवास में रहने देगी तो राज्य का बहुत नुकसान हो जाएगा। असली मामला राजनीति का है। सरकार ने राबड़ी देवी वाला आवास भाजपा कोटे के मंत्री नंदकिशोर राम के नाम आवंटित कर दिया है। भाजपा कह रही है कि देखिए, राबड़ी देवी किस तरह अनुसूचित जाति की विरोधी हैं। अनुसूचित जाति के मंत्री के नाम पर आवंटित किए गए आवास को खाली नहीं कर रही हैं।

पटना स्थित राबड़ी देवी का आवास, जो आजकल कई कारणों से चर्चा में है। फाइल

उधर राजद की राजनीति यह है कि सरकार जबरदस्ती आवास खाली कराए। उनके सामान को सड़क पर फेक दे। तब कहा जाएगा कि सरकार महिला विरोधी है। पिछड़ा विरोधी है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का सम्मान करना नहीं जानती है। आम लोग तमाशा देख रहे हैं। बीच-बीच में ये खबरें भी आ रही हैं कि सरकार जबरदस्त ढंग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। बिना वैकल्पिक प्रबंध के गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। यह रुचिपूर्ण विषय नहीं है। अधिक रुचि इसमें है कि राबड़ी देवी आवास खाली करती हैं या नहीं।

वस्तुतः सरकारी आवासों पर विवाद कोई नया विषय नहीं है। बचपन की अपनी गरीबी का बखान करते-करते आंसू निकाल लेने वाले लोग जब जन प्रतिनिधि बनकर पटना पहुंचते हैं तो उनकी पहली खोज एक भव्य सरकारी आवास की होती है। अब तो सरकार ने विधानसभा क्षेत्र संख्या के आधार पर आवास का निर्माण और आवंटन कर दिया है। इससे पहले तो नव निर्वाचित विधायक और उनके समर्थक परिणाम की घोषणा होते ही पटना पहुंच कर किसी भव्य आवास पर कब्जा जमाने का प्रयास करते थे। देखा यह जाता था कि वह आवास किसी पराजित विधायक या मंत्री का हो। खैर यह परिपाटी बंद हो गई है। लेकिन, भव्य और सुसज्जित आवास की भूख नहीं गई है। सरकार ने उन लोगों का भी सम्मान किया है, जो कभी मंत्री थे और अब केवल विधायक रह गए हैं। इनके लिए मांग के आधार पर दोहरे आवास की व्यवस्था की गई है। एक तो इन्हें विधायक के नाम पर मुफ्त मिलेगा। दूसरे के लिए इन्हें भुगतान करना होगा। डेढ़ दर्जन से अधिक विधायकों को पूर्व मंत्रियों के नाते यह सुविधा मिली हुई है।

दोष इन जन प्रतिनिधियों का भी नहीं है। लालू प्रसाद मार्च, 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। अपनी मां से मिलने गांव गए। उनकी सीधी सरल मां समझ नहीं पाईं कि उनका बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है। लालू प्रसाद का गांव फुलवरिया, गोपालगंज जिले में है। इसी जिले में हथुआ राज भी है। लालू प्रसाद ने अपनी मां को मुख्यमंत्री पद की महत्ता समझाने की गरज से कहा कि वे हथुआ महाराज से भी बड़े ओहदे पर चले गए हैं। मां हथुआ महाराज के प्रताप को समझती थीं। वह अपने पुत्र के प्रताप को समझ गईं। लालू प्रसाद बिंदास प्रकृति के हैं। लेकिन, सभी जन प्रतिनिधि ऐसे नहीं हैं कि अपने मन के राजा को सब जनता के बीच प्रकट कर सकें। राजा हैं तो राज प्रासाद भी चाहिए। अपवाद को छोड़ दें तो ज्यादा जन प्रतिनिधि इसी मनोभाव के हैं।

मंथन

स्वर्ण आयात रोकने की कवायद

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, इस वर्ष की पहली तिमाही में भारत ने 150 टन सोने का आयात किया। विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए भारत को स्वर्ण आयात रोकना होगा

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रतीकात्मक

भारत में लोगों का सोने की खरीद के प्रति आकर्षण कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्षों से देश के लोग आभूषणों के रूप में सोने की भारी खरीद करते रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की अपील से कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद प्रधानमंत्री आभूषणों की खरीद पर अंकुश लगाने की अपील कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमें समझना होगा कि पिछले लगभग दो दशकों से देश में आभूषणों के रूप में सोने की खरीद में भारी कमी आई है, फिर भी देश में सोने का आयात बढ़ता जा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों को देखना और समझना पड़ेगा।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में कुल सोने का आयात 150 टन रहा, लेकिन आभूषणों के लिए सोने की मांग केवल 66 टन ही थी। पूर्व में विश्व स्तर पर आभूषण के लिए सोने की मांग 50 प्रतिशत से ज्यादा होती थी, लेकिन यह घटते हुए वर्ष 2025 तक मात्र 31 प्रतिशत ही रह गई। वर्ष 2025 में पहली बार निवेश के लिए सोने की मांग 2175 टन तक पहुंच गई जो आभूषणों हेतु सोने की मांग से भी ज्यादा थी। यानी देश और विश्व में सोने की मांग इसलिए नहीं बढ़ रही कि स्वर्ण आभूषणों की मांग बढ़ रही है, बल्कि लोग सोने को निवेश के रूप में भी रखना चाहते हैं। यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश बड़े देशों के केंद्रीय बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में सोने का अनुपात बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर 2025 से लेकर अब तक आरबीआइ के पास विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 13.92 प्रतिशत से बढ़कर 16.85 प्रतिशत हो चुका है।

यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि हाल ही में कुछ ऐसे समाचार भी आए कि आरबीआइ ने अपना काफी सोना बेच दिया है, लेकिन तीन जून को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार आरबीआइ के पास सोने के भंडार 880.52 टन पर कायम है। वस्तुतः पिछले लंबे समय से देश में सोना बड़ी मात्रा में आयात होता रहा है। लेकिन इस संदर्भ में खास बात यह है कि जीडीपी में वृद्धि के साथ सोने का आयात भी बढ़ता रहा है। 1991 के बाद सोने के आयात की प्रवृत्ति बढ़ी है।

वर्ष 1992 में सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए आयात स्कीम लागू की और 1993 में बैंकों और नामित एजेंसियों के माध्यम से सोने का आधिकारिक आयात होना शुरू हो गया। इसके चलते तस्करी में भारी गिरावट आई और अब आधिकारिक आयात काफी बड़ी मात्रा में बढ़ गया। 1993 से 1994 के बीच दो सौ टन सोने का आयात हुआ और 1995 से 1997 के बीच यह चार सौ से पांच सौ टन तक पहुंच गया। और उसके बाद सोने का आयात सामान्यतः छह सौ से नौ सौ टन वार्षिक तक रहा, जबकि कई वर्षों में तो यह एक हजार टन तक पहुंच गया। बढ़ते आयातों के मद्देनजर 2012-13 तक आते-आते सोने पर आयात नियंत्रण वापस आए और न केवल आयात शुल्क बढ़ाया गया, बल्कि बैंकों पर सोने के आयात को लेकर कई नियंत्रण लगा दिए गए। आयातकों पर यह शर्त लगाई गई कि अपने कुल सोने के आयात का उन्हें कम से कम 20 प्रतिशत पुनर्निर्यात करना होगा। कोरोना के दौरान थोड़े समय के लिए सोने का आयात थमा, लेकिन उसके उपरांत उसमें और ज्यादा तेजी आ गई। 2021 के बाद सोने का आयात तो बढ़ ही रहा था, लेकिन 2024 में आयात शुल्क घटाए जाने के बाद 2025-26 तक यह 72 अरब डालर तक पहुंच गया। हालांकि मात्रा की दृष्टि से 2025-26 में 2024-25 की तुलना में कम सोने का आयात हुआ, लेकिन सोने की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के चलते डालर में सोने का आयात पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो गया।

लीक से हटकर विचार : समझा जा सकता है कि सोने के बढ़ते आयातों के चलते आज भारत के विदेशी मुद्रा भंडारों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। सोने का आयात ज्यादातर निवेश के लिए होने लगा है, इसलिए जरूरी है कि लोग निवेश के लिए कुछ अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करें। पूर्व में भौतिक रूप से ही सोना खरीदे जाने की संभावना होती थी, लेकिन अब उसके काफी विकल्प शुरू हो चुके हैं। ईटीएफ उसमें से एक है। देश में विभिन्न प्रकार के ईटीएफ का कुल पूंजीगत मूल्य 1.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आज जो भी सोने में निवेश करना चाहे, वो ईटीएफ में पैसा लगा सकता है, और सोने में मूल्य वृद्धि का लाभ ले सकता है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) ने चार मई 2026 को एक नए ट्रेडिंग सेगमेंट के तौर पर इलेक्ट्रानिक गोल्ड रसीद की शुरुआत की है। यह भारत के विशाल और परंपरा-आधारित सोने के बाजार को आधुनिक बनाने और औपचारिक रूप देने की दिशा में एक अहम कदम है। स्टाक मार्केट में इस प्रकार के उत्पाद आने के कारण अब भौतिक सोने की खरीद कर निवेश करने के दूसरे विकल्प सामने आ रहे हैं, जिससे सोने के आयात की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो सकती है। वैसे लीक से हटकर कुछ नए प्रकार की व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है, ताकि लोग भौतिक सोने की खरीद से बचें और उन विकल्पों में निवेश करें, ताकि सोने के मूल्य में वृद्धि का लाभ भी उठाया जा सके, और इसके आयात पर अंकुश भी लग सके।

बिजनेस

एमजी ने 470 से अधिक स्थानों पर चार्जर लगाए

मुंबई: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 'एमजी चार्ज' पहल के तहत देशभर में 470 से अधिक स्थानों पर 1,000 सामुदायिक चार्जर स्थापित किए हैं। कंपनी का दावा है कि इसके साथ ही वह इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सामुदायिक चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने वाली देश की पहली मूल उपकरण विनिर्माता बन गई है। कंपनी के अनुसार, ये चार्जर आवासीय सोसायटी, अस्पतालों, शैक्षणिक परिसरों, होटल और औद्योगिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। (प्रेट्र)

कंपनी इस साल अपने चेन्नई संयंत्र में तैयार दो नए माडल पेश करेगी। इसमें उसका आम लोगों के लिए पहला किफायती इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल होगा।

– तरुण गर्ग, एमडी और सीईओ, हुंडई मोटर इंडिया

सेंसेक्स	74,243.34 ▼ 116.67	निफ्टी	23,366.70 ▼ 49.85	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,59,900 ▼ ₹ 400	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,60,700 ▼ ₹ 5,000	$ डालर	₹ 95.18 ▼ ₹ 0.56	क्रूड प्रति बैरल	$ 94.93

आरबीआइ ने रेपो रेट स्थिर रखा, महंगाई के अनुमान को बढ़ा 4 .7% किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पिछले दो वर्षों से सस्ते ब्याज दरों का जारी दौर अब अंत की तरफ बढ़ चला है। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। हालांकि, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पश्चिम एशिया संघर्ष, ऊर्जा कीमतों में उछाल और कमजोर मानसून की आशंका को लेकर महंगाई बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

सालाना महंगाई लक्ष्य को बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया गया है। जानकार अब अगस्त, 2026 में ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका जता रहे हैं। पिछले वर्ष आरबीआइ ने रेपो रेट में 125 आधार अंकों (1.25 प्रतिशत) की कटौती की थी, जिससे होम लोन, आटो लोन की दरें काफी कम हुई हैं। आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा खिंचने, सप्लाई चेन बाधित होने और तेल की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई दबाव बढ़ेगा। इससे लोगों की खरीद क्षमता घटेगी। एमपीसी की राय है कि संघर्ष की अवधि, उसकी तीव्रता, सप्लाई चेन पर प्रभाव और दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर उम्मीद (अल-नीनो के साथ) महंगाई व विकास दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं। महंगाई का जोखिम बढ़ गया है, लेकिन एमपीसी ने स्पष्टता आने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया है। हम डाटा पर निर्भर रहेंगे और सामान्य मूल्य स्तर में आपूर्ति पक्ष के दबाव तथा महंगाई अपेक्षाओं पर नजर रखेंगे। फिलहाल तटस्थ रहने की नीति पर कायम रहने का फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के असर का हवाला देते हुए ही आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की आर्थिक विकास दर अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल में हुई एमपीसी बैठक के दौरान 6.9 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष शुरू होने से पहले आरबीआइ ने 7.1 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था। साफ है कि विकास दर में तेजी बने रहने की संभावनाएं कमजोर होती जा रही हैं।

- **वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश के आर्थिक विकास दर अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत किया**
- **ऊर्जा कीमतों में उछाल और कमजोर मानसून की आशंका के चलते महंगाई बढ़ने के संकेत दिए**
- **पश्चिम एशिया संघर्ष और अल-नीनो महंगाई और विकास दोनों के लिए पैदा कर रहे गंभीर जोखिम**

मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान लिए फैसलों की जानकारी देते आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ● प्रेट्र

आगे चलकर ऊर्जा और अन्य इनपुट की कीमतों में वृद्धि, सप्लाई व्यवधान आर्थिक गतिविधियों पर बोझ डालेंगे। आयात विविधीकरण से सप्लाई सुधरेगी, लेकिन लागत बढ़ेगी। पूरा प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि मौजूदा संघर्ष कब समाप्त होता है और उत्पादों और कच्चे माल की आपूर्ति कब तक सामान्य होती है। ऊर्जा की ऊंची कीमतों का खुदरा उत्पादों की कीमतों पर असर पहले ही दिखने लगा है। कमजोर मानसून कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर असर डालेगा।

-संजय मल्होत्रा, आरबीआइ गवर्नर

पूंजीगत व्यय इकोनमी को देगा सहारा

आरबीआइ ने कहा कि सेवा क्षेत्र की निरंतर गति, जीएसटी तर्कसंगतीकरण का प्रभाव, स्थिर रोजगार स्थिति, शहरी खपत, मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय और बैंक-गैर बैंक से क्रेडिट फ्लो विकास को सहारा देंगे। कारपोरेट सेक्टर की तरफ से उनकी क्षमता के उपयोग का स्तर भी ऊंचा बना है और कारपोरेट निवेश की स्थिति सकारात्मक हैं। सरकार ने एमएसएमई, निर्यात क्षेत्र, घरेलू गैस-कच्चा तेल उत्पादन बढ़ाने और आयात विविधीकरण के उपाय किए हैं जिससे पश्चिम एशिया के झटकों से निपटने में मदद मिलेगी। आरबीआइ ने अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3, तीसरी तिमाही में 6.5 और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

आरबीआइ के फैसलों से रुपया, डालर के मुकाबले 56 पैसे मजबूत

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा की तरलता (लिक्विडिटी) को मजबूत करने के उपायों के एलान के बाद रुपया डालर के मुकाबले 56 पैसे मजबूत होकर 95.18 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आरबीआइ द्वारा किए गए एलानों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। गुरुवार को रुपया दो पैसे बढ़कर डालर के मुकाबले 95.74 पर बंद हुआ था।

रुपया 95.72 पर खुला, फिर दिन के दौरान 94.89 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा और अंत में 95.18 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 56 पैसे की बढ़त दर्शाता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार के मुताबिक, आरबीआइ के विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपायों के बाद रुपये में दो अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। परमार ने कहा, 'डालर में नरमी और क्रूड की घटती कीमतों ने रुपये के बढ़ने में मदद की।

पालिमर नोट लाने पर अभी फैसला नहीं

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पालिमर नोट लाने के संबंध में अभी तक किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है और यह विचार अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि बैंक फिलहाल इस तरह के कदम की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। मल्होत्रा ने कहा कि इस संबंध में मीडिया में छपी रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

एक नजर में

1,800 करोड़ का आइपीओ लाएगा पारस हेल्थकेयर

नई दिल्ली: पारस हेल्थ ब्रांड के तहत अस्पताल चलाने वाले पारस हेल्थकेयर लिमिटेड ने आइपीओ के जरिये 1,800 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए सेबी में दस्तावेज जमा किए हैं। प्रस्तावित आइपीओ में 500 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि मौजूदा शेयरधारक 1,300 करोड़ रुपये तक के अपने शेयर बेचेंगे। शेयर बेचने वालों में प्रमोटर धर्मिंदर कुमार नागर और अन्य निवेशक हैं। (प्रेट्र)

चांदी 5,000 घटी, सोना 400 रुपये सस्ता हुआ

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 400 रुपये घटकर 1,59,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रखते हुए चांदी की कीमत 5,000 रुपये घटकर 2,60,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में चांदी का भाव 2,65,700 रुपये प्रति किलोग्राम था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोने की कीमत घटकर 4,470.79 डालर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत एक प्रतिशत से अधिक गिरकर 72.89 डालर प्रति औंस हो गई। (प्रेट्र)

ब्रजेश सिंह ने केनरा बैंक के एमडी का पदभार संभाला

नई दिल्ली: ब्रजेश कुमार सिंह ने केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पदभार संभाल लिया है। वह 30 अप्रैल, 2029 तक इस पद पर रहेंगे। ब्रजेश सिंह इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के साथ फाइनेंस में एमबीए किया है। उनके नेतृत्व में केनरा बैंक डिजिटल ट्रांसफार्मेशन को तेज करने, वित्तीय समावेश को बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर अपना फोकस जारी रखेगा। (बि)

ब्रजेश कुमार सिंह

विदेशी निवेश लाने पर आरबीआइ का जोर

एफपीआइ के लिए सरकारी बांड में निवेश की सारी बाधाएं हटाईं, रुपये को स्थिर करने में मिलेगी मदद

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) के शेयर बाजार से लगातार निकासी और रुपये के कमजोर होने के दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार और आरबीआइ ने एक साथ बड़े कदम उठाए हैं। पहले, वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों को सरकारी बांड्स (जी-सेक) में निवेश पर पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) और ब्याज आय पर विद्होल्डिंग टैक्स पूरी तरह समाप्त करने का फैसला किया तो वहीं आरबीआइ ने एफपीआइ के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की राह आसान करते हुए उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से जारी बांड्स में ज्यादा निवेश करने की सहूलियत देने का सर्कुलर जारी कर दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से आने वाले दो वर्षों में 40-50 अरब डालर का विदेशी निवेश सरकारी बांड में आ सकता है। यह रुपये को स्थिर करने और पूंजीगत खाते में घाटे (देश में विदेशी मुद्रा की आय व विदेशी मुद्रा व्यय का अंतर) की स्थिति से निपटने में मदद करेगा।

आरबीआइ ने अपने सर्कुलर में जनरल रूट के तहत एफपीआइ निवेश पर लगी तीन प्रमुख बाधाएं, शार्ट-टर्म लिमिट, सिक्योरिटी-वाइज लिमिट और कंसन्ट्रेशन लिमिट पूरी तरह हटा दी हैं। जनरल और लांग-टर्म श्रेणियों को भी मिला दिया गया है। केंद्र सरकार के बांड्स और राज्य सारकारों के बांड्स के लिए अलग-अलग कुल सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा 15, 30 और 40 वर्ष के नए सरकारी प्रतिभूतियों, पर्यावरण हितकारी परियोजनाओं के लिए सरकारी की तरफ से जारी होने वाले बांड्स (5 से 40 वर्ष अवधि के) और तीन मौजूदा बांड्स को फुली एक्सीसेबल रूट (एफएआर यानी बिना किसी बाधा के) वाले वर्ग में शामिल कर लिया गया है। यहा एफआइआइ के लिए निवेश और निकासी की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा आरबीआइ ने गैर निवासी भारतीयों (एनआरआइ) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआइ) के लिए सूचीबद्ध इक्विटी के उत्पादों में निवेश सीमा भी बढ़ा दी है। इसके लिए प्रतिभूति नियामक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा विदेश में रहने वाले अब सभी भारतीयों (पीआरओआइ) के लिए है, जिससे भारतीय शेयर बाजारों तक उनकी पहुंच व्यापक हो गई है।

- **अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए सूचीबद्ध इक्विटी के उत्पादों में निवेश सीमा बढ़ाई**
- **प्रतिभूति नियामक सेबी में पंजीकरण की नहीं होगी जरूरत, शेयर बाजार तक पहुंच होगी आसान**

सरकारी बांड्स में विदेशी संस्थागत निवेश अब पूरी तरह से होगा टैक्स-फ्री

सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) के सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में किए गए निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को समाप्त करने का फैसला किया है। इस संबंध में शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया गया। सरकार ने दीर्घकालिक एवं स्थिर पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर हटाने का फैसला किया है, क्योंकि इन माध्यमों की अवधि लंबी होती है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अब तक स्थानीय शेयर बाजार से भारी 2.6 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। इसकी वजह वैश्विक अनिश्चितता रही है। केवल जून के पहले तीन दिन में ही विदेशी निवेशकों ने शेयरों से करीब 34,000 करोड़ रुपये निकाले, जिससे रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। विदेशी निवेशकों ने हालांकि पूर्ण पहुंच मार्ग (एफएआर) के तहत ऋण बाजार में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

वर्ष 2013 के बाद देश में डालर आकर्षित करने का यह सबसे व्यापक उपाय है। डालर के मुकाबले रुपये का रुख अब कच्चे तेल की कीमतों से तय होगा। अगर क्रूड लगातार 100 डालरप्रति बैरल से नीचे रहता है रुपया 94-94.5 के स्तर पर टिका रहेगा।

-अनिंद्य बनर्जी, कोटक सिक्योरिटीज

बताई गई ब्याज दर से ज्यादा पर भुगतान करना मंजूर नहीं : गवर्नर

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि पहले से बताई गई ब्याज दर से ज्यादा दर पर भुगतान करना उन्हें मंजूर नहीं है। हालांकि, गवर्नर ने इस दौरान किसी बैंक का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसे आरोप हैं कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने बड़ी जमा हासिल करने के लिए अतिरिक्त रकम दी और उसके मार्केटिंग खर्च के तौर पर दिखाया। उन्होंने कहा कि जमा हासिल करने के लिए बैंकों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन जमा जुटाते समय पारदर्शी रवैया अपनाएं।

माइथोस से जुड़े साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार: आरबीआइ ने कहा कि वह माइथोस प्लेटफार्म से जुड़े साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने नियामकीय संस्थाओं को जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। माइथोस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा सिस्टम है, जिसे एंथ्रोपिक ने साफ्टवेयर की कमियों और उभरते साइबर खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया है। कंपनी ने अप्रैल में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उसने कहा था कि इस माडल को आम इस्तेमाल के लिए जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना रोक-टोक के इसके गलत इस्तेमाल की आशंका है।

मुद्रा भंडार 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त

आरबीआइ गवर्नर ने शुक्रवार को कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 682.3 अरब डालर के अच्छे स्तर पर है और यह लगभग 11 महीनों के आयात खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मल्होत्रा ने कहा, 'हालांकि, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कई अन्य साधन भी हैं।

जुलाई मध्य तक अमेरिका से ट्रेड डील : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बताया कि भारत व अमेरिका के बीच अगले माह के मध्य तक व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। गत दो से चार जून तक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर नई दिल्ली में होने वाली वार्ता सकारात्कम रही। उन्होंने बताया कि गत बुधवार की शाम को अमेरिका के वार्ताकारों से उनकी मुलाकात भी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भारत से जल्द ही व्यापार समझौता हो जाएगा।

अभी अमेरिका में वहां के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी देशों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लग रहा है जिसकी अवधि आगामी 24 जुलाई को समाप्त हो रही है। इससे पहले अपने व्यापार कानून के सेक्शन 301 के तहत अमेरिका सभी देशों पर फिर से शुल्क लगाने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि अमेरिका भारत पर 301 के तहत 12.5 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि अमेरिका भारत पर शुल्क लगाने के लिए अभी इस प्रकार के कई और प्रस्ताव ला सकता है। ताकि भारत व्यापार समझौते के लिए पहले से प्रस्तावित 18 प्रतिशत की दर को स्वीकार ले। इन सबके बीच अगले महीने अमेरिका के व्यापार मंत्रालय के शीर्ष प्रतिनिधि भारत आ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर भारत को अमेरिका में प्रतिद्वंद्वी देशों पर शुल्क के मामले में बढ़त मिलती है तो समझौते में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो भारत इसे नकार भी सकता है।

अगले पांच साल में 30 अरब डालर के मछली निर्यात का लक्ष्य

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न देशों के साथ हो रहे व्यापार समझौते को देखते हुए अगले पांच साल में मछली का निर्यात 30 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत 8.5 अरब डालर का मछली निर्यात करता है। 170 अरब डालर के वैश्विक मछली निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत है। हालांकि मछली निर्यात में पिछले 10 सालों में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को विशाखापट्नम में मछली निर्यात बढ़ाने को लेकर रोडमैप तैयार करने के कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि आंध्रप्रदेश व अन्य समुद्री राज्य मछली निर्यात में आगे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार 93.8 करोड़ डालर बढ़ा

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने शुक्रवार को बताया कि 28 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 93.8 करोड़ डालर बढ़कर 682.321 अरब डालर हो गया। इससे पहले सप्ताह में यह भंडार 7.511 अरब डालर घटकर 681.384 अरब डालर रह गया था।

इस साल 27 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में यह भंडार 728.494 अरब डालर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से कई सप्ताह तक इसमें गिरावट आई, क्योंकि रुपये पर दबाव बना और आरबीआइ को डालर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देना पड़ा। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 28 मई को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा संपत्ति 3.116 अरब डालर बढ़कर 546.148 अरब डालर हो गई।

आरबीआइ अनुमानों से ज्यादा रहेगी वृद्धि दर

नई दिल्ली, एएनआइ: विश्व बैंक में भारत के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा का मानना है कि भारत की वृद्धि दर आरबीआइ के अनुमानों से ज्यादा रहेगी। आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धि अनुमान को 6.7 से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। इस पर मिश्रा का कहना है कि आरबीआइ का अनुमान बहुत ज्यादा सावधानी से भरा है और असल अर्थव्यवस्था सरकारी अनुमानों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मिश्रा ने कहा कि अंदरूनी आकलन से पता चलता है कि फरवरी-मार्च में इकोनमी आठ प्रतिशत की दर से बढ़ी।

महंगाई का दबाव लगातार नहीं बने रहने का हवाला देते हुए मिश्रा ने ब्याज दरों और मौद्रिक नीति में बदलाव नहीं करने के आरबीआइ के फैसले को भी समझाया। उन्होंने कहा कि तेल की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई में होने वाली अस्थायी बढ़ोतरी के लिए रेपो रेट में वृद्धि की जरूरत नहीं है, जब तक कि अगले साल कच्चे तेल की कीमत लगातार 130 डालर प्रति बैरल के स्तर को पार न कर जाए। मिश्रा ने करेंसी मार्केट में घबराहट को संभालने के लिए दरों में वृद्धि के इस्तेमाल को एक बेकार और महंगा उपाय बताया। उन्होंने कहा, 'करेंसी मार्केट में घबराहट को रोकने के लिए दरों में बढ़ोतरी करना 15वां विकल्प है, न कि पहला, क्योंकि वृद्धि के नजरिये से वे बहुत महंगे होते हैं। सच कहूं तो वे अक्सर काम नहीं करते। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आरबीआइ ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।' मिश्रा ने कहा कि बड़े वित्तीय बदलावों की उम्मीद करना या नामिनल जीडीपी वृद्धि का सही अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी।

नीलकंठ मिश्रा ●

- **विश्व बैंक में भारत के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक ने कहा-अनुमान से बेहतर प्रदर्शन कर रही इकोनमी**
- **महंगाई में होने वाली अस्थायी बढ़ोतरी के लिए रेपो रेट में वृद्धि की जरूरत को बेकार की कवायद बताया**

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

देश में लांच हुआ ई85 ईंधन, पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता मिलेगा नया फ्यूल

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ई85 फ्यूल को लांच कर दिया है। यह एक उच्च एथनाल मिश्रण है, जिसे फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सामान् पेट्रोल के मुकाबले 20 रुपये सस्ता मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक इंडियन आयल पेट्रोल पंप पर इस ईंधन को लांच किया। इसकी शुरुआत देशभर के 48 पंपों से होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार दिसंबर 2026 तक इसे 500 आउटलेट तक और दिसंबर 2027 तक लगभग 5,000 आउटलेट तक बढ़ाने की योजना बना रही है। ई85 में 80-85 प्रतिशत एथनाल और 14-19 प्रतिशत पेट्रोल होता है। इसका इस्तेमाल उन फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में किया जा सकता है जो ई20 से ई100 तक के एथनाल मिश्रण पर चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि ई85 इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से 2030-31 तक देश का कुल एथनाल मिश्रण स्तर 26 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। कहा कि सरकार ने ई85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल से 20 रुपये प्रति लीटर कम रखी है। इसका मकसद एथनाल का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना है। अगर सभी नए दोपहिया व यात्री गाड़ियों में से आधे फ्लेक्स फ्यूल पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो सालाना एथनाल की मांग 312 करोड़ लीटर बढ़ सकती है।

- **दिसंबर 2027 तक 5,000 आउटलेट पर मिलने लगेगा इस तरह का ईंधन**
- **ई85 में 80-85 प्रतिशत एथनाल और 14-19 प्रतिशत पेट्रोल होता**

पूसा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर ई 85 पेट्रोल भरते केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। जागरण

भारत भारी माल ढुलाई रेल प्रणालियों वाले देशों के क्लब में शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत भारी माल ढुलाई रेल प्रणालियों का संचालन करने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारत माल ढुलाई संचालन की सुरक्षा व दक्षता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में अग्रसर है। यह बात डीएफसीसीआइएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को कही।

भारतीय समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने यहां आयोजित दो दिवसीय हैवी-हाल सेमिनार-2026 सम्मेलन से इतर पत्रकारों संग बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह सेमिनार दुनियाभर के विशेषज्ञों को एक साथ लाने और टेक्नोलाजी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है।।

2060 तक जीडीपी हिस्सेदारी में चीन को पछाड़ देगा भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत वर्ष 2060 के आसपास क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है जबकि सदी के उत्तरार्द्ध में चीन की हिस्सेदारी घटने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) उन कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को मापती है, जिसे किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश में खरीद सकती है।

पेरिस स्कूल आफ इकोनमिक्स में स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब (डब्ल्यूआइएल) द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बारे में यह बात जोर देकर कही जानी चाहिए कि अभी पीपीपी के आधार पर वैश्विक जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है और यह अमेरिका से लगभग एक तिहाई ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुमानों के आधार पर 2035 तक यह अमेरिका की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, "हालांकि, चीन की आबादी की हिस्सेदारी तेजी से घट रही है और यह 1945 में दुनिया की आबादी का 23 प्रतिशत से घटकर 2025 में लगभग 17 प्रतिशत और 2100 में आठ प्रतिशत से भी कम रह जाएगी। 21वीं सदी के दूसरे हिस्से में वैश्विक जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी स्थिर होने या घटने का अनुमान है और 2060 के आसपास भारत आगे निकल जाएगा।' रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में इस बात की कम संभावना है कि चीन कभी उस तरह की दबदबे वाली स्थिति तक पहुंच पाएगा जैसी स्थिति 1950 के आसपास अमेरिका की थी (दुनिया की जीडीपी का 35-40 प्रतिशत हिस्सा) या 1900-1910 के आसपास यूरोप की थी (40-45 प्रतिशत)। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के विपरीत, 21वीं सदी में दुनिया बहुध्रुवीय होने जा रही है।

- **अभी पीपीपी के आधार पर वैश्विक जीडीपी में चीन की हिस्सेदारी 20%**

21 वीं सदी के दूसरे हिस्से में चीन की हिस्सेदारी स्थिर होने या घटने का अनुमान

लगभग 4.15 ट्रिलियन डालर हो जाएगी भारत की इकोनमी: विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, 2026 में भारत की जीडीपी (देश के अंदर बने सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य) लगभग 4.15 ट्रिलियन डालर (2025 में 3.92 ट्रिलियन डालर से ज्यादा) होगी, जबकि ब्रिटेन की जीडीपी 4.27 ट्रिलियन डालर (2025 में 4 ट्रिलियन डालर से ज्यादा) तक पहुंच जाएगी। जबकि जापान की जीडीपी असल में 2025 के 4.48 ट्रिलियन डालर से घटकर 2026 में 4.38 ट्रिलियन डालर रह जाएगी।

संपादकीय

ही आग लावली कोणी?

'दिल्लीमध्ये सर्व काही चालते' हे बेमुर्वत आणि बेफिकीर उत्तर आहे, दक्षिण दिल्लीत अग्निकांड घडलेल्या हॉटेलमालकाचे. त्याला हॉटेलमधील बेकायदेशीर बांधकामाबद्दल पोलिसांनी विचारल्यानंतर त्याने हे उत्तर व्यवस्थेच्या तोंडावर फेकले ! त्याच्या 'फ्लरिश स्टे' या हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीत तब्बल २१ जणांना होरपळून जीव गमवावा लागला. त्यात ११ परदेशी नागरिक होते. त्यानंतर दोन दिवसांच्या अंतराने बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथील खासगी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत पाच रुग्णांचा जळून कोळसा झाला. या दोन्ही घटना म्हणजे केवळ अपघात नव्हे, तर निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाची जळजळीत उदाहरणेच. दिल्लीतील हॉटेलला केवळ सहा खोल्यांची परवानगी असताना कायदा धाब्यावर बसवून २५ खोल्या बांधल्या होत्या. राजधानीत सुरू असलेल्या 'बी ॲण्ड बी' अर्थात 'बेड ॲण्ड ब्रेकफास्ट' योजनेचा हा थेट गैरवापर. राष्ट्रकुल स्पर्धेदरम्यान सरकारने ही योजना आणली. त्यानुसार घरमालक किंवा निवासी मालमत्ताधारक आपल्या घरातील जास्तीत जास्त सहा खोल्या पर्यटकांना अल्पकालीन मुक्कामासाठी भाड्याने देऊ शकतो. या सुविधेत निवासाची सोय (बेड) आणि सकाळचा नास्ता (ब्रेकफास्ट) पुरवला जातो. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात आले खरे; पण या मूळ हेतूलाच हरताळ फासत, प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून या मालकाने २५ खोल्या बांधल्या. शॉर्टसर्किट किंवा वातानुकूलन यंत्रातील बिघाडामुळे आग लागल्यानंतर हॉटेल ज्या भागात होते, तेथील अरुंद रस्ते आणि अपुरी सुरक्षाव्यवस्थाही चव्हाट्यावर आली. मालकाने इमारतीसाठी अग्निसुरक्षेचे प्रमाणपत्र घेतले नाही आणि ना हरकत दाखलाही घेतलेला नव्हता. मुजफ्फरपूरमधील रुग्णालयातील घटना त्याहून अधिक वेदनादायी. जिथे लोक जीव वाचवण्यासाठी दाखल होतात, त्याच रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. ती आगही शॉर्टसर्किटचीच. तेथेही अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यरत नव्हती. लिफ्टही बंद होती, खिडक्या-दारे तोडून रुग्णांना बाहेर काढावे लागले. सार्वजनिक ठिकाणी अशा भीषण आगी लागणे आणि त्यात माणसांचे हकनाक बळी जाणे, हे अलीकडे नित्याचेच झाले आहे. अग्निसुरक्षेचे नियम अत्यंत स्पष्ट आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच होत असल्याचे वारंवार दिसून येते. एखादी दुर्घटना घडली की चौकशी समित्या, निलंबने आणि आश्वासनांचा पाऊस ठरलेलाच. नंतर काही महिन्यांतच सर्व काही पूर्ववत ! दिल्लीतील हॉटेल आणि मुजफ्फरपूरमधील रुग्णालय या दोन्ही ठिकाणी मृत्यूचे कारण केवळ आग नव्हते, तर त्या मृत्यूंना कारणीभूत होते बेफिकीर व्यवस्थापन, निष्क्रिय प्रशासन आणि सुरक्षेवरील खर्चाला पद्धतशीर बगल देणारी मानसिकता. आपल्याकडे एखादी इमारत कोसळल्यानंतर बांधकामाचे नियम आठवतात, विषारी दारूने मृत्यू झाल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभाग जागा होतो आणि आग लागल्यानंतर अग्निसुरक्षेची चर्चा सुरू होते ! प्रतिबंधात्मक यंत्रणा मात्र कायम झोपेत असते. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने केलेले देशभरातील सर्वेक्षण या सगळ्या त्रुटी अधोरेखित करते. देशातील एकाही पालिकेत अग्निशमन विभाग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाही, हे जळजळीत वास्तव या संस्थेने नोंदवले आहे. परिणामी इमारतींची संख्या बेसुमार वाढली; पण त्यांना परवानगी देणारी, त्यांची तपासणी करणारी यंत्रणा कमकुवतच राहिली. म्हणून, दोषी मालकासोबत संबंधित अधिकारी आणि परवानगी देणाऱ्या यंत्रणांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करून कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. सामान्य माणसाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणाऱ्या मुर्दाड यंत्रणेला जमिनीवर आणले पाहिजे. अर्थात, 'मारेकरी कोण?' असे विचारताना, 'वाचवणारे कोण?' हाही प्रश्न विचारला पाहिजे. बुधवारी दिल्लीतल्या मालवीय नगरमध्ये आग लागल्यानंतर अनेकजण समोर आले. त्यापैकी एक नाव आता ठळकपणे ठाऊक झाले आहे. लोकांचे जीव वाचवणाऱ्या या देवदूताचे नाव आहे रियाजुद्दीन अन्सारी. केवळ रियाजुद्दीन अन्सारीच नव्हे, तर अरमान, इसरार खान, मोहम्मद शोएब, गोविंद कुमार, वसीम राजा, मोहम्मद अफजल, शिवानी, मोहम्मद अनिस, वकार, मुस्तकीम असे अनेकजण पुढे आले. त्यांनी लोकांचे जीव वाचवले. या सगळ्या घटनांचे व्हिडिओ आहेत. ते पाहताना अंगावर काटा येतो आणि डोळे भरून येतात. त्या हॉटेलमध्ये तीन परदेशी नागरिक होते. त्यांचेही जीव वाचवण्याचा ही मंडळी आटोकाट प्रयत्न करत होती. आतमध्ये अडकलेल्या लोकांचा जात, धर्म, वंश, लिंग, देश काय, याचा विचार न करता आपला जीव धोक्यात घालत होती. असे आग विझवणारेही आहेत, म्हणून हा 'भारत' आहे. पण, मूळ प्रश्न उरतोच. अशा या भारतात ही आग भडकवणारे कोण आहेत? त्यांना वेळीच ठेचले नाही, तर भारताच्या स्वप्नालाच नख लागणार आहे !

वैर, द्वेष, तुच्छतेशिवाय साहित्यात काय असते?

आपले ते सारे पूज्य आणि इतरांचे सारेच तुच्छ. मग हिंदूंनी मुसलमानांचे वाचायचे नाही आणि त्यांनी ख्रिश्चनांचे काही वाचायचे नाही, अशी मारामारी लागते. हे असेच चालू राहिले, तर आमची दृष्टी माणुसकीची तरी कशी होईल?

सुरेश द्वादशीवार
ज्येष्ठ लेखक, समीक्षक आणि संपादक

माझ्या एका स्नेह्याने त्याचे बाबासाहेबांची थोरवी सांगणारे एक जाडजूड पुस्तक अलीकडेच मला पाठविले. शीर्षकातच आंबेडकरांच्या नावापुढे दुसऱ्या एका मोठ्या आदरणीय माणसाला लहान करून दाखविण्याचा कमालीचा विनोदी प्रकार त्याने केला होता. मी त्या दोन्ही थोरांचे मूळ ग्रंथ वाचले असल्याने त्या स्नेह्याचे ते तसले गाइड वाचायचे मनातही आणले नाही. अशीच एक दुसरी गोष्ट आणखी एका प्रचारी लिखाणाची. एका ज्येष्ठ संपादकाने लिहिलेले 'हिंदुत्व' या नावाचे सातशे पृष्ठांचे पुस्तक मला देऊन त्यावर मी समीक्षा लिहावी असे सुचविले. मी म्हणालो, 'मी तुमचे लिखाण कधीच वाचत नाही.' त्यावर काहीसे संतापून ते म्हणाले, 'का..?' मी म्हटले, 'तुम्ही काय लिहिता व काय सांगता ते मला न वाचताही कळतच असते. मग ते वाचण्यात मी वेळ कशाला दवडायचा?'

- संशय ही शोधाची जननी असली तर द्वेष ही वैराची ठिणगी असते.

आताशा प्रकाशित होणारी बहुतेक पुस्तके द्वेषपूर्ण व प्रचारी असलेली दिसतात. आपल्या पूजास्थानांच्या आरत्या आणि त्याहून वेगळ्या पण तेवढ्याच आदरणीय असणाऱ्यांवर टीकेचा भडीमार. पक्ष राजकारणातच असतात असे नाही. ते साहित्यात, विचारात, चित्रात, सांस्कृतिक व्यासपीठांवर आणि माणसांच्या मनातही असतात. आपल्याला आवडणारी, आपली वाटणारी पुस्तके वाचायची, तशीच भाषणे ऐकायची आणि तेवढ्याच दर्जेदार असलेल्या इतर वेगळ्या गोष्टींकडे ठरवून दुर्लक्ष करायचे, हा एकारलेपणा वा कर्मठ द्वेषबुद्धी सर्वत्र दिसते. द्वेष सोडला तर अनेकांजवळ सांगण्यासारखे काहीच नसते. इतरांना कनिष्ठ ठरविले की आपण मोठे ठरतो असे एका वर्गाला वाटते. काही जातींना शिव्या दिल्या की आपले पुरोगामित्व सिद्ध होते या भ्रमात हा वर्ग जगतो. यात निरक्षरच असतात असे नाही. तो साक्षर व नामवंत ठरलेल्यांचाही किंवा त्यांच्याच अधिकार कक्षेत येणाऱ्यांचा प्रांत असतो.

अशावेळी मनात येते, विचार सहजपणे त्याच्या मूळ व खऱ्या स्वरूपापर्यंत आपल्यात पोहचत नाही की त्याचे खरे असणे आपल्यालाच मानवत नाही? आपल्या आवडत्या पुढाऱ्याचा विचार हाच आपला विचार, आवडत्या लेखकाची मते हीच आपली मते हे का होते? जातीधर्मांनी केलेले संस्कार आणि त्यांनी रुजविलेली मते म्हणजे विचार का? विचार ही स्वतःपाशी सुरू होणारी बाब आहे. कुणा दुसऱ्याने सांगितलेली, सुचविलेली वा समजाविलेली बाब आपला विचार कशी बनेल? तो फारतर एखाद्या वस्त्रप्रावरणासारखा अंगावरचा संस्कार होईल. फारतर तिला श्रद्धेचे नाव देता येईल, पण तिला तर्काची कसोटी आपण कधी लावतो काय आणि ती लावली तर त्या विचाराचे खरेखोटेपण आपल्या लक्षात येते की नाही? आपल्याला आवडणाऱ्या मतांचे समर्थन वा तरफदारी करणारे तेवढेच हल्ली वाचले जाते. गांधीजींची पुस्तके वा त्यांच्याविषयी इतरांनी लिहिलेली आदरणीय पुस्तके संघाची माणसे वाचतात काय? आपण चांगले वाचक आहोत असे समजणारी आंबेडकरी विचारांची माणसे तरी ती वाचतात काय?

अर्थात, या विवेचनाला आणखीही एक बाजू आहे - वाचन, मनन व चिंतनादि गोष्टींनी बुद्धिमत्ता उंचावते असे म्हटले तर बुद्धाने काय वाचले वा सॉक्रेटिसने कुणाचे पुस्तक अभ्यासले? ज्ञानेश्वर १८व्या वर्षी गीतेवर भाष्य लिहितात, त्याच वयात मौलाना आझाद कुराणावर भाष्य लिहितात. शंकराचार्य वयाच्या ८व्या वर्षीच वेदवेदांगे वाचून त्यात पारंगत होतात, हे कसे समजून घ्यायचे? 'वेदांचा भार त्या उच्चभ्रूंनी वहावा आम्ही त्यात कधीचेच पारंगत झालो आहोत' असे आपला तुकाराम कसे म्हणतो? ग्रीक तत्त्वज्ञ, अरब ज्ञानवंत आणि पाश्चात्य फिलॉसॉफर्स तरी परस्परांचे वा पूर्वसूरींचे ग्रंथ वाचून मोठे झाल्याचे दिसत नाही. त्यांना स्फुरणारे ज्ञान स्वयंभूच असते. ते स्वयंभूपण त्यांना कसे लाभले? त्यांनी त्यांची उंची कशी गाठली? तेच वेदांच्या निर्मात्यांचे, कन्फ्युशियस आणि लाओ त्सेचेही. माणसे पुस्तके वाचून त्यानुसार वागतात असेही कुठे दिसत नाही. ती परंपरेने, समजाने व सोयीनेच आपल्या भूमिका घेतात की नाही? मग ही वाचन संस्कृती कशाची व कोणाच्या हिताची? लेखकांच्या, प्रकाशकांच्या, प्रचारकांच्या की जाहिरातदारांच्या?

आपल्या लेखन-वाचन व्यवहारात निर्माण झालेला नवा प्रश्न सामाजिक दुराव्याचा आणि राजकीय वैराचा आहे. जातींची साहित्य संमेलने, जातीपंथांच्या थोरवीची पुस्तके, परजातीला व परधर्माला नावे ठेवणारी व आपल्याच जातीपंथाचा उदोउदो करणारी वा तसे खरेखोटे आकांत मांडणारी पुस्तके एका बाजूला तर तमकी जात वा पंथ श्रेष्ठ व उच्चभ्रू कसा, तोच एक न्यायी व नीतीमान कसा आणि त्याच्याच वर्चस्वाखाली साऱ्यांचे कल्याण होण्याची शक्यता किती मोठी हे सांगणारा दुसराही एक मोठा वर्ग. या दोन तटांमधली शिवीगाळ फक्त वर्तमान वा इतिहासापुरती नाही. लोक थेट पौराणिक काळात जाऊन त्यावर भांडतात. जगातला कोणताही कायदा वा न्यायपीठ बापाच्या अपराधाची शिक्षा मुलाला देत नाही. भारताच्या घटनेनेही तीच बाब प्रस्थापित केली आहे. पण आताची साहित्यात दिसणारी वैरे बापाच्या, आज्याच्या व पणज्याच्याच नव्हे तर थेट ठाऊक नसलेल्या कुळांच्या आरंभापर्यंत केली जातात. परिणाम हा की ज्या जातीचे लेखक त्याच जातीचे वाचक. ज्या धर्माचे नाव त्याच धर्माचे त्यांचे उपासक. वास्तविक या संस्था माणसांना एकत्र आणण्यासाठी निर्माण झाल्या. पण प्रत्यक्षात त्यांनी माणसांच्या जातीचे व जगाच्या प्रदेशाचे तुकडेच केले.

आम्ही बोलतो ते आमच्याच घरी कळत कसे नाही?

ब्राह्मण लेखकांना दलित जीवनावर लिहिता येत नाही आणि दलित लेखकांना ब्राह्मणांवर व सवर्णांवर लेखणी चालवता येत नाही. धर्मांचे वैर तर याहून मोठे. आदिवासी जीवनावर कुणाला आजवर लिहिता आले? स्त्रियांची दुःखे तरी पुरुषांना कितीशी लिहिता येतात? दुःखांना माणुसकीची नाती असतात. तशी ती दिसत नाहीत. पण तीच नाती त्या न दिसणाऱ्या ईश्वरासारखी खरी असतात. गांधी जगाचे का होतात आणि इतरांना त्यांच्या आसपासच जेमतेम पोहचणे का जमते? गांधींना वक्तृत्व नव्हते. त्यांची भाषाही जगाची नव्हती. तरी ते जगाचे झाले. हिंदूंच्या, मुसलमानांच्या, ख्रिश्चनांच्या, बौद्धांच्या आणि साऱ्यांच्याच काळजाचाही विषय बनले. गांधींना हे न बोलता वा न लिहिता कसे जमले? आणि आमची बोली आमच्याच घरच्या लोकांना का कळत नाही?

आपल्या जातींना प्रादेशिक मर्यादा आहेत. आपल्या देशात जातींची संख्या अडीच हजारांहून मोठी, तर जमातींची सातशेहून अधिक आहे. त्यातही त्यांचे पोटजातीतले विभाजन वेगळे. अशा वर्गांच्या बंधनात व संस्कारात अडकलेल्या व जगलेल्या लेखक, कवींच्या मर्यादाही त्याच बंधनांनी आखल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणातील उणेपणाचा दोष त्यांचा नसतो. तो त्यांच्यावरील जातिपातींच्या संस्कारांचा व पारंपरिक मर्यादांचा असतो. ज्यांना या मर्यादा ओलांडता येतात ते 'नोबेल'चा मान मिळवणारे रवींद्रनाथ होतात, प्रेमचंद, इंदिरा गोस्वामी, बेंद्रे वा साहिल किंवा अमृता प्रीतम होतात. ज्यांच्या लिखाणात एकवाक्यता असते, त्यांच्यातून तुकाराम, ज्ञानेश्वर आणि कबीर निपजतात. आम्ही आमच्याच कुंपणात अडकलो असल्याने त्यांच्याएवढे मोठे होत नाही आणि टॉलस्टॉय, गार्गी, बर्क किंवा टोनी मॉरिसनसारखे जागतिकही होत नाही. ज्यांनी जातिधर्म व देश यांच्या मर्यादा झुगारून माणसांच्या दुःखाच्या आणि आनंदाच्या कथा लिहिल्या ते लेखक साऱ्या मानवजातीचे झाले. म्हणून शेक्सपिअर जगाचा होतो आणि कालिदासही जगभर अभ्यासला जातो. रामायण आणि महाभारत आपण त्यांच्या अशा अमर्याद असण्यामुळे वाचतो की नाही? त्या माणसांच्या कथा आहेत, जातिपातीच्या व त्यातून येणाऱ्या बऱ्यावाईट संस्कारांच्या नाहीत.

ज्यांना देश व खंडांच्या मर्यादा ओलांडता येतात ते जागतिक होतात. जे देशातच राहतात ते देश आणि जातिपंथात अडकतात. जे जातिपातीचे व त्यातले आपले स्थान ओळखून उंच विस्तारतात ते मोठे होतात; पण जातींना नेते असतात, प्रादेशिकांना पुढारी असतात, आपले प्रवक्ते असतात. हे जोवर आहे तोवर आपले लेखक आणि त्यांचे लेखन जातिपंथाच्या मर्यादेतच अडकून राहणार. ते आपल्या जाती विशेषाचे महत्त्व गाणार आणि इतरांवर तुच्छतेचे शिडकावे उडवीत राहणार.

देश, धर्म, परंपरा व संस्कृती यांच्यातील भिन्नतेमुळे विचारांचे रंग वेगळे दिसतात हे खरे आहे; पण माणुसकीचा रंग तर एकच असतो ना? जो रक्तासारखा साऱ्यात सारखा आहे. आम्ही त्वचेपाशीच थांबतो का? अंतरंगात शिरण्याचे व माणूसपण शोधण्याचे कसब वा ज्ञान आम्हाला मिळालेच नाही का? आपले ते सारे पूज्य आणि इतरांचे सारेच तुच्छ. मग हिंदूंनी मुसलमानांचे वाचायचे नाही आणि त्यांनी ख्रिश्चनांचे वाचायचे नाही, अशी मारामारी लागते. हे असेच चालू राहिले, तर आमची दृष्टी माणुसकीची तरी कशी होईल?

वाचन संस्कृतीवाले व त्यांचे उद्योजक किंवा झेंडेकरी या वास्तवाचा विचार करणार नसतील तर त्यांचा सारा खटाटोप पुस्तके खपविण्यात व प्रकाशकांच्या तिजोरीत भर घालण्यासाठीच केला असतो की नाही? नवोदित लेखकांकडून जास्तीचे पैसे घ्यायचे आणि त्यांची कमी किमतीतील थोडीफार पुस्तके छापून द्यायची, हा व्यवसाय आता साऱ्या महाराष्ट्रात पसरला आहे की नाही? शिवाय आपल्या पुस्तकांच्या प्रती त्या लेखकालाच देऊन 'तूच त्या वीक' असे सांगणारे बहाद्दर प्रकाशकही आता आपण पाहत आहोतच की नाही? दुःख याचे की, खोटे चलन बाजारात आले की, खऱ्या चलनाकडेच लोकांचे दुर्लक्ष होत जाते. मग त्यातले चांगले साहित्य पडून राहते आणि जाहिरात झालेली बेचव पुस्तकेच बाजारात खपताना दिसतात.

फळांनी लगडलेली झाडे नम्रपणे वाकलेली असतात. ज्या झाडांची फळे हलकी असतात वा लागताच गळून पडणारी असतात ती मात्र ताठ असतात आणि तशीच ती दिसतातही. ज्ञानाचेही असेच आहे. ज्ञानवंत माणसे नम्र, तर स्वतःला तसे समजणारी माणसे अहंकारी दिसतात. ज्ञानी माणसांची चर्याही दयार्द्र दिसते. मात्र, तसे म्हणविणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर एक उर्मट तुच्छपण दिसते. समजदारांना त्यांच्यावरील टीकाही विचारात घ्यावीशी वाटते. तसे नसणाऱ्यांना समीक्षा धुडकावून फेकाविशी वाटते.

- हे दोन्ही वर्ग या लेखावर कशा प्रतिक्रिया देतील याचे भान प्रस्तुत लेखकाला आहे. ज्याला हे लिहिणे आवडेल त्यांचे आभार. ज्यांना ते आवडणार नाही, त्यांचेही आभार.

sdwadashiwar@gmail.com

'इतरां'चे सोडा, जे 'आपले' ते तरी कुणी वाचते का?

खरा प्रश्न असा आहे, की जे 'आपले' आहे, ते तरी मुळात वाचण्याचे कष्ट कुणी घेते का? किती हिंदूंनी वेद वाचणे सोडा, पाहिले तरी आहेत? किती मुस्लिमांनी कुराण शरीफ आणि त्यावर लिहिलेल्या हदीस ग्रंथांचे वाचन केले? ख्रिश्चनांनी नवा करार (तो लहान आहे म्हणून) वाचला असेल, जुन्या कराराचे ज्ञान त्यांना तरी आहे काय? महाराष्ट्रातील नवबौद्धांनी बाबासाहेबांचा 'बुद्ध आणि त्याचा धम्म' हा ग्रंथच जर वाचला नसेल तर त्यांची नजर नागार्जुन वा त्रिपिटकापर्यंत कशी जाईल? साधी वर्तमानपत्रे न वाचता वर्तमान घटनांवर मते द्यायची हाच प्रकार समाजात हल्ली दिसतो की नाही? आजच्या राजकारणातल्या किती लोकांनी त्यांच्या पक्षाची विचारसरणी वा तात्त्विक बैठक समजून घेतली? बापाची जात स्वीकारावी तसे बापाचे पक्षही मुलांनी स्वीकारलेले दिसतात.

जगभर

एआयचा गैरवापर- अभिनेत्याचं करिअर बरबाद!

दक्षिण कोरियाचा लोकप्रिय अभिनेता किम सू-ह्यून (Kim Soo-hyun) हा 'के-ड्रामा' जगतातील सर्वांत यशस्वी आणि प्रभावशाली कलाकारांपैकी एक मानला जातो. रोमँटिक, ऐतिहासिक, भावनिक आणि थ्रिलर अशा विविध प्रकारच्या भूमिका साकारून त्यानं जागतिक लोकप्रियता मिळवली. तो 'Hallyu' म्हणजेच 'कोरियन वेव्ह'चा महत्त्वाचा चेहरा मानला जातो. आपल्या अदाकारीमुळे दक्षिण कोरियात तो चांगलाच प्रसिद्ध आहे. पण, गेल्या काही काळापासून तो एका वेगळ्याच कारणानं गाजतो आहे.

अभिनेत्री किम से-रॉन (Kim Sae-ron) हीदेखील दक्षिण कोरियाची अत्यंत प्रतिभावान अभिनेत्री. बालकलाकार म्हणून सुरुवात करून अतिशय कमी वयातच कोरियन चित्रपटसृष्टीत आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तिनं मोठं नाव कमावलं. परंतु, गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत वयाच्या केवळ २४व्या वर्षी तिनं आत्महत्या केली. तिच्या निधनानं कोरियन मनोरंजनसृष्टीला मोठा धक्का बसला. पण, तिच्याच नावावरून आणि एआयचा वापर करून एका यूट्यूबरनं अभिनेता किम सू-ह्यूनला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. इतका की, अभिनेता किमच्या लोकप्रियतेला त्यामुळे ओहोटी लागली, त्याच्या कारकिर्दीला मोठा फटका बसला आणि स्वत: किमदेखील त्यामुळे नैराश्यात गेला.

'होव्हर लॅब' हे लोकप्रिय यूट्यूब चॅनल चालवणाऱ्या किम से-उई यानं एआयचा वापर करून आणि पुराव्यांमध्ये फेरफार करून लोकांसमोर एक वेगळंच चित्र उभं केलं. लोकांचाही त्यावर विश्वास बसला. अभिनेता किम सू-ह्यूननं या अभिनेत्रीशी ती अल्पवयीन असतानाच संबंध ठेवले होते, असा खोटा दावा केल्याचा आरोप पोलिस आणि सरकारी वकिलांनी केला आहे.

अभिनेत्री किम से-रॉननं आत्महत्या केल्यानंतर काही काळातच हे प्रकरण चर्चेत आलं. तिच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनी जवळपास दहा लाख सदस्य असलेल्या 'होव्हर लॅब' चॅनलनं एक व्हॉइस रेकॉर्डिंग प्रसिद्ध केलं. त्यात अभिनेत्री म्हणते आहे, मी माध्यमिक शाळेत असल्यापासूनच अभिनेता किम सू-ह्यूनला डेट करते आहे. मात्र, हे व्हॉइस रेकॉर्डिंग एआयच्या मदतीनं तयार करण्यात आल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

अभिनेत्रीच्या फोनमधून पाठवण्यात आलेल्या मजकूर संदेशांचे स्क्रीनशॉट्सही फेरफार करून ते किम सू-ह्यूनशी झालेल्या संभाषणासारखे दाखवण्यात आल्याचा आरोप यूट्यूबरवर आहे. 'होव्हर लॅब' हे दक्षिण कोरियातील वादग्रस्त चॅनल मानलं जातं. या चॅनलवर राजकारण आणि मनोरंजन क्षेत्रावरील भाष्य नियमितपणे प्रसिद्ध केलं जातं. सेलिब्रिटींबाबतच्या चर्चांसाठीही हे चॅनल लोकप्रिय आहे.

'होव्हर लॅब'वरील दाव्यांमुळे 'किम सू-ह्यून'चा सामाजिक पाया आणि आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे कोलमडले, तसेच त्याच्या व्यावसायिक अस्तित्वाचा पायाही उद्ध्वस्त झाला', असं 'जुंगआंग इल्बो'नं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. या आरोपांमुळे धक्का बसलेला अभिनेता अजूनही मानसिक आरोग्यासाठी उपचार घेत असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

मार्च २०२५मध्ये घेतलेल्या भावनिक पत्रकार परिषदेनंतर अभिनेत्यानं आजपर्यंत अधिकृत सार्वजनिक उपस्थिती लावलेली नाही.

जनमन

आकड्यांपलीकडचा राजकीय संदेश

विधानपरिषदेच्या निवडणुका सर्वसामान्य मतदारांपेक्षा राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत ताकदीच्या परीक्षा मानल्या जातात; कारण या निवडणुकांमध्ये थेट जनता मतदान करत नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे या निवडणुकांचा निकाल केवळ संख्याबळाचा नसून संघटनात्मक शिस्तीचाही मापदंड असतो. यावेळी काही ठिकाणी मित्रपक्षांमधील मतदानाच्या पद्धतीवर चर्चा रंगली. एका पक्षाच्या उमेदवाराला दुसऱ्या मित्रपक्षातील सर्व मते मिळाली का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. अशा चर्चा केवळ विजय किंवा पराभवापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. त्या पक्षांमधील स्थानिक संबंध, कार्यकर्त्यांमधील समन्वय आणि नेतृत्वावरील विश्वास यांचाही वेध घेतात. युतीचे राजकारण राज्य पातळीवर मजबूत दिसत असले तरी स्थानिक पातळीवर वास्तव वेगळे असू शकते. अनेक भागांत मित्रपक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असतात. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत कधीकधी अशा अंतर्गत विसंगती उघडपणे दिसून येतात. स्थानिक नाराजी, उमेदवाराची प्रतिमा किंवा वैयक्तिक समीकरणे यांचाही निकालावर प्रभाव असतो. विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती पक्षांना आत्मपरीक्षण करण्याची संधी देते. पक्षाचा आदेश किती प्रभावी आहे, संघटना किती एकसंध आहे आणि स्थानिक नेतृत्व किती सक्षम आहे, याचे संकेत या निवडणुकांतून मिळतात. त्यामुळे या निवडणुका केवळ जागा जिंकण्याची स्पर्धा नसून राजकीय संदेश समजून घेण्याचे महत्त्वाचे माध्यम ठरतात.

- वीरेंद्र सोनवणे, जळगाव

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

चित्रकथा

काचेच्या बंद भिंतीआड कुणीच कुणाशी का बोलत नाहीये?

या माणसांच्या जागी आपण असतो तर? - हा विचार फार अस्वस्थ करतो. महानगरातील प्रत्येकाच्या आपापल्या एकटेपणाचे हे प्रातिनिधिक चित्रण.

शर्मिला फडके
ख्यातनाम कला समीक्षक, लेखिका

एडवर्ड हॉपर या अमेरिकन चित्रकाराने १९४२ मध्ये रंगवलेले एका महानगरातले डायनर. मध्यरात्र उलटून गेली आहे. बाहेरचा रस्ता निर्मनुष्य. रुंद काचेच्या भिंतीमागे चार लोक, तीन ग्राहक एक वेटर. कुणी कुणाशी बोलत नाहीये. एकमेकांकडे बघतही नाहीयेत. पिवळ्या दिव्याच्या कृत्रिम, ऊब नसलेल्या प्रकाशात प्रत्येकाचे एकाकीपण स्वतंत्र अधोरेखित होत आहे. हे कोणतेही एक विशिष्ट डायनर नाही. ते कोणत्याही मोठ्या शहरातले असू शकते.

डायनरला दार नाही. आपण बाहेरून आत पाहतो आहोत. आतल्या लोकांचा एकाकीपणा आपल्याला दिसत आहे, त्यांना तो कदाचित जाणवतही नाही. आपण आत त्यांच्या जागी असतो तर आपल्यालाही तो जाणवला नसता कदाचित अशी जाणीव आपल्याला अस्वस्थ करते. शहरी निशाचर आपण असतोच कधी ना कधी. काचेच्या कधी अल्याड, कधी पल्याड. महानगरातील एकाकीपण सर्वव्यापी आहे. शहरी समूहातल्या प्रत्येकाच्या आपापल्या एकटेपणाचे हे प्रातिनिधिक चित्रण. हॉपरला हेच दाखवायचे आहे.

काचेची भिंत हे माणसांमधल्या अभेद्य एकटेपणाचे प्रतीक. हॉपरने चित्र रंगवले ते दिवस जागतिक महायुद्धाचे. माणसांच्या मनातली परस्परांबद्दलची असुरक्षितता, भीतीची सावली कदाचित नाइटहॉक वर दबा धरून आहे. काचेच्या आतली शांतता स्फोटानंतरची किंवा आधीची असू शकते. आतल्या कृत्रिम पिवळ्या उजेडाची अनैसर्गिकता अशावेळी जास्त खटकते. बाहेरचा गडद अंधार भकास वाटायला लागतो. हेमिन्ग्वेच्या एका लघुकथेवरून प्रेरणा घेऊन हॉपरने हे चित्र काढले, असेही म्हटले जाते.

एडवर्ड हॉपर हा विसाव्या शतकातला महानगरीय चित्रकार. १८८२-१९६७ या काळात त्याने अशी अनेक शहरे, गर्दीत हरवलेली एकटी माणसे, स्त्रिया रंगवल्या आहेत. हॉटेलच्या रूममधल्या खिडकीतून रहदारीचा रस्ता न्याहाळणाऱ्या, रेस्टॉरंटमध्ये टेबलावर एकटीने कॉफी पिणाऱ्या, ऑफिसात रात्री उशिरा काम करणाऱ्या एकेकट्या स्त्रिया. महानगरीय माणसांच्या समूहातले एकाकीपण चित्रित करणारी हॉपरची वास्तववादी चित्रे अमेरिकन आर्टचा चेहरा मानली जातात.

हॉपरला खरंतर माणसे नाही, माणसांमधले अंतर रंगवायचे आहे. माणसे ज्या जागेत उभी अथवा बसलेली असतात, त्या जागांशी त्यांचे जोडलेले नसणे, कोरड्या अलिप्ततेचे थंड नाते तो रंगवतो. शारीरिक जवळीक असते, पण मानसिक अंतर अमर्याद. त्याची चित्रशैलीही तटस्थ, आशयाशी सुसंगत कट-ऑफ फ्रेम, प्रकाश-छायेमधला कठोर विरोधाभास डोळ्यात भरतो. त्याच्या चित्रात माणूस लहान, सावल्या लांब आणि आजूबाजूचा रिकामा अवकाश प्रचंड मोठा, अंगावर येणारा. खिडक्या, दारे, काचा हे सगळे सीमा अधोरेखित करणारे. रंगछटाही म्यूटेड, चेहरे अस्पष्ट. त्यातून भावनिक अलिप्तता जाणवते.

शिकागो आर्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये हे चित्र - नाईटहॉक लावलेले आहे. ८३ वर्षं झाली तरी ते अजिबात जुने वाटत नाही. संपूर्ण जग कोलाहलाने गजबजलेले एक मोठे शहर बनलेले असताना माणसांमधले अंतर जास्त ओसाड, एकटेपणा जास्त तीव्र झाला आहे. चित्रातली समकालिनता कालातीत आहे. आजूबाजूचे जग बदलले, डायनर बदलले. पण काचेची भिंत तशीच आहे. आता मोबाईलच्या स्क्रीनच्या काचेने तिची जागा घेतली आहे. एकाकीपणा बाहेरून पाहणाऱ्यालाच अस्वस्थ करतो फक्त, आतल्या माणसांकरिता तो सुखावहही असू शकतो ही जाणीव आता नव्याने अस्वस्थ करते.

sharmilaphadke@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

संवाद
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 6 जून 2026

न्यायपालिका में AI

अवसर के साथ चुनौती भी है तकनीक

तकनीक को हमेशा इंसानों के मददगार के रूप में देखा गया। यहां कमान इंसानों के हाथों में होती है और तकनीक बस मदद करती है। लेकिन, AI के मामले में यह चिंता बहुत बड़ी बन चुकी है कि क्या इंसानों के हाथ से लगाम छूटती जा रही? आर्टिफिशल इंटेलिजेंस किस तरह अवसर होने के साथ एक चुनौती भी है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसी ओर ध्यान दिलाया है।

उपयोग की सीमा । प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर आज युद्ध तक में AI का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा बहस न्यायपालिका में इसके उपयोग की सीमा को लेकर है। चीफ जस्टिस के मुताबिक, इसका प्रभाव इस पर निर्भर है कि समाज टेक्नॉलजी को किस कानूनी, राजनीतिक और नैतिक ढांचे के भीतर उपयोग करता है। उनकी यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि इंटेलिजेंट मशीनों के इस दौर में भी उन मूल्यों की संरक्षक मानवता ही रहे, जिस पर वह टिकी है।

CJI ने उठाया मुद्दा

एल्गोरिद्म की ताकत । CJI का यह सवाल बेहद अहम है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून AI की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस तकनीक ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब एल्गोरिद्म कहीं लिखा जाता है, उपयोग कहीं और होता है और असर किसी और पर पड़ता है। ऐसे में कानूनों को वक्त के हिसाब से लचीला बनाना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने बर्कबेक कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ये बातें तब कही हैं, जब देश में सुप्रीम कोर्ट ने AI के औपचारिक इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे हैं।

गलत इस्तेमाल । ड्राफ्ट के मुताबिक, AI केवल सहायक की हैसियत से काम करेगा। उसका उपयोग हमेशा मानवीय निर्णय और न्यायिक अधिकार के प्रति अधीन रहेगा। ये रेगुलेशंस तय करेंगे कि न्यायपालिका में AI का इस्तेमाल कहां तक होना है। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर चिंता जताई थी, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने फैसले में AI जेनरेटेड आदेशों का हवाला दिया था।

तकनीक जरूरी भी । लेकिन, इन चुनौतियों के साथ AI की उपयोगिता का भी ध्यान रखना होगा। मुकदमों के बोझ से निपटने, डॉक्युमेंटेशन और लीगल रिसर्च में तकनीक मददगार साबित हो सकती है। पिछले महीने जब पोप लियो XIV ने अपने संदेश में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के खतरों के प्रति आगाह किया था, तब उन्होंने यह भी कहा था कि मकसद तकनीक को ठुकराना नहीं है। असल बात है नियंत्रण और जवाबदेही। इससे समझौता नहीं हो सकता।

अंतर्दृष्टि

सजा की व्यवस्था नहीं कर्म सिद्धांत, यह सबसे बड़ी पाठशाला

जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है, जब कोई तकलीफ देता है, जब कोई अन्याय होता है, तो अक्सर एक वाक्य सुनाई देता है- 'जो जैसा कर्म करेगा, उसे उसका वैसा ही फल मिलेगा।' और इस वाक्य में एक छिपी हुई संतुष्टि होती है कि जैसे कर्म एक न्यायाधीश है, जो एक दिन सबका हिसाब करेगा। हम दूसरों के कर्मों का हिसाब लगाते रहते हैं, उनके दंड की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन क्या यही कर्म का सच्चा अर्थ है? क्या कर्म केवल बदले की एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है? नहीं। यह कर्म के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। कर्म का सिद्धांत कोई सजा की व्यवस्था नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पाठशाला है। हर अनुभव, वह चाहे सुखद हो या दुखद, एक सबक लेकर आता है। और जब तक वह सबक सीखा नहीं जाता, वह अनुभव किसी न किसी रूप में लौटता रहता है। यही कर्म का वास्तविक स्वभाव है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कर्म की जो व्याख्या की है, वह अद्भुत है। उन्होंने कहा - कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल त्याग का उपदेश नहीं है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तब हमारा कर्म शुद्ध होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है।

सुंदर चंद ठाकुर

अब ज़रा अपने जीवन को देखिए। जो कठिनाइयां बार-बार आती हैं - वही रिश्तों में समस्या, वही काम में अवरोध, वही भावनात्मक उथल-पुथल, तो क्या आपने कभी सोचा कि यह बार-बार क्यों आती है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि जब तक हम उस अनुभव से सीखते नहीं, वह अनुभव अलग-अलग रूपों में सामने आता रहता है। जैसे एक टीचर जब तक छात्र पाठ नहीं समझता, उसे बार-बार दोहराता है। व्यक्ति बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर वही पाठ फिर सामने आ जाता है। क्योंकि जीवन चाहता है कि हम सीखें, बढ़ें, और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटें।यह दंड नहीं है। यह करुणा है। ब्रह्मांड की हम पर करुणा।

और यहीं से कर्म का दूसरा गहरा सत्य सामने आता है कि हम अपने कर्मों के शिकार नहीं हैं, हम उनके निर्माता हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे आज के विचार, आज के निर्णय, आज के कार्य, हमारा कल बना रहे हैं, तब एक जबरदस्त जागरूकता जन्म लेती है। तब हम परिस्थितियों को दोष देना बंद करते हैं। तब हम प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई और हमारा जीवन बदलेगा। तब हम स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। और यही जागरूकता मनुष्य को भीड़ से अलग करती है। यही उसे एक सचेत जीवन जीने की शक्ति देती है। यही कर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। जागरूक बनो, जिम्मेदार बनो।

ऑफ़ दि ट्रैक

मास्टर जेनेटिक घड़ी

दिलीप लाल

लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए यह खोज का विषय रहा है कि जीवों का विकास इतनी सटीक समय-सारिणी के हिसाब से कैसे होता है। अमेरिका की कोल्ड स्प्रिंग हार्बर प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी 'मास्टर जेनेटिक घड़ी' की खोज की है, जो जीवों की वृद्धि और विकास की गति को कंट्रोल करती है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि विकास के दौरान जीन एक निश्चित क्रम में सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं। और ऐसा छोटे-छोटे पल्स या तरंगों के रूप में होता है। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि इन तरंगों का समय आखिर कैसे निर्धारित होता है। शोध में यह बात सामने आई है कि इसके लिए दो प्रोटीन - MYRF-1 और LIN-42 जिम्मेदार हैं। इन्हीं से तय होता है कि विकास के लिए जिम्मेदार ये छोटी-छोटी तरंगें कब शुरू होंगी, कितनी देर तक चलेंगी और कब समाप्त होंगी। एक और बात सामने आई है कि ये तरंगें घड़ी की सूई की तरह हमेशा आगे ही बढ़ती रहती हैं। यदि यह 'मास्टर जेनेटिक घड़ी' काम करना बंद कर दे, तो विकास रुक जाता है और जीव वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। यह ठीक वैसा है जैसे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के सभी यात्री तैयार हों, लेकिन ड्राइवर की घड़ी बंद होने के कारण ट्रेन कभी रवाना ही न हो। भविष्य में इससे मानव विकास और रोगों के उपचार से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलने की संभावना है।

समिट में ख़ुद को स्वतंत्र-संतुलित शक्ति के रूप में पेश करेगा भारत

शी आए, तो सीमा पर होगी बात!

Xi

भारत साल के अंत में BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी शामिल हो सकते हैं, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने पहले ही आने की सहमति दे दी है। यह समिट ऐसे समय में हो रही है, जब दुनियाभर में उठापटक चल रही है। वैश्विक राजनीति नाजुक दौर से गुजर रही है और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बिखर रही है। चीन-अमेरिका के बीच तनातनी भी पहले से ज्यादा मुखर है।

हर्ष वी. पंत

नए अलायंस का दौर । रूस के पश्चिमी देशों से सीधे टकराव के चलते नए राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन बन रहे हैं। अब विकासशील या पिछड़े (ग्लोबल साउथ) देश उन वैश्विक संस्थाओं में असरदार भागीदारी चाहते हैं, जिन पर लंबे समय से पश्चिमी देशों का प्रभुत्व रहा है। इन हालात में भारत की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है।

बड़ी ताकतों से रिश्ते । भारत इस सम्मेलन के जरिए खुद को स्वतंत्र और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर सकता है। भारत दिखा सकता है कि वह किसी गुट का हिस्सा नहीं है बल्कि अपने हितों के अनुसार दूसरे देशों के साथ संबंध रखता है। भारत की खासियत यह है कि उसके रिश्ते लगभग सभी प्रमुख शक्तियों से हैं। अमेरिका के साथ उसके संबंध मजबूत हो रहे हैं। रूस आज भी भारत की विदेश नीति में अहम भूमिका निभा रहा है।

रूस-चीन करीब । रूस से पारंपरिक रिश्ते कायम हैं और चीन से तनाव के बावजूद संवाद बनाए रखने की कोशिश जारी है। इसलिए, चिनफिंग और पूतिन की एक साथ मेजबानी भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक ताकत की ओर इशारा करती है। हालांकि, रूस-चीन की बढ़ती करीबी भारत के लिए चिंता का विषय है। अगर रूस कमजोर होकर चीन पर निर्भर हो गया तो यूरेशिया (यूरोप-एशिया) में भारत के रणनीतिक विकल्प सीमित हो सकते हैं।

चीन से संबंध सुधरे । 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत-चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। वैसे, भारत जानता है कि चीन से संघर्ष कभी-कभार की बात नहीं बल्कि स्थायी स्थिति है। बावजूद इसके दोनों देश समझते हैं कि दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव खतरनाक हो सकता है। इधर दोनों देशों की ओर से संबंधों में बेहतरी की कोशिश हुई है। सम्मेलन में मोदी और शी की मुलाकात में सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी या सीमित आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि बड़े बदलाव की उम्मीद बेमानी है क्योंकि झगड़े की असल जड़ (सीमा विवाद) बनी हुई है। चीन आज भी पाकिस्तान का करीबी है और हिंद महासागर में पांव पसारने के मौके भी वह नहीं छोड़ता।

AI Image

बदलते लक्ष्य । BRICS उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग के लिए बना था, लेकिन अब धीरे-धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE जैसे देश इसमें शामिल हुए हैं। यानी, इन देशों में मौजूदा वैश्विक व्यवस्था से असंतोष बढ़ रहा है। लेकिन, BRICS को पश्चिम-विरोधी संगठन कहना, जल्दबाजी होगी। क्योंकि, इन देशों के हित, राजनीतिक व्यवस्था, महत्वाकांक्षाएं भी अलग-अलग हैं। भारत भी नहीं चाहता कि BRICS को पश्चिमी देशों के खिलाफ मंच बनाया जाए, जैसा कि चीन और रूस की कोशिश रही है। वह BRICS का इस्तेमाल वैश्विक व्यवस्था में सुधार के लिए करने के हक में है, न कि एक वर्चस्ववादी व्यवस्था को हटाकर दूसरी ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए।

> **समिट में आएंगे शी-पूतिन!**
> - ग्लोबल साउथ के अजेंडा पर भारत का रहेगा जोर
> - भारत के ज्यादातर बड़ी ताकतों से अच्छे रिश्ते
> - चीन के साथ सुधर रहे हैं भारत के संबंध

भारत का अजेंडा । भारत चाहेगा कि सम्मेलन में विकास, वित्त, तकनीक के आदान-प्रदान को लेकर बातचीत और फैसले हों। वहीं, चीन और रूस डॉलर पर निर्भरता कम करने और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले मुद्दों को उठाना चाहेंगे। ऐसे में भारत के लिए सम्मेलन में सर्वसम्मति बनाना आसान नहीं होगा।

नजर भविष्य पर । सम्मेलन से बदलती हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की तस्वीर स्पष्ट होगी। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का दुनिया पर प्रभाव घट रहा है, लेकिन फिलहाल कोई नया शक्तिशाली वैश्विक ढांचा भी पूरी तरह बना नहीं है। इस अनिश्चितता के दौर में वैश्विक मंच पर भारत की अहमियत बढ़ रही है क्योंकि वह एक साथ कई बड़े देशों और समूहों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम है। ऐसे में चिनफिंग और पूतिन का भारत आना किसी एक गुट की जीत नहीं बल्कि इससे पता चलता है कि दुनिया आज ज्यादा बंटी हुई है और इसमें शक्ति के ध्रुव कई हैं।

(लेखक लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

AI Image

5 पॉइंट

गर्म मिज़ाज क्यों AC

गर्मियों में एयर कंडीशनर (AC) में आग लगना और धमाका होना आम होता जा रहा है। हालांकि इससे होने वाले जान-माल के नुकसान का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। गंभीरता को देखते हुए सरकारी दखल जरूरी है।

1 मांग और जोखिम बढ़े
भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ नए AC बिक रहे हैं। बढ़ती आय, शहरीकरण और गर्मी के कारण AC अब जरूरत बन गया है। इससे उपकरणों की संख्या और उनसे जुड़े सुरक्षा जोखिम, दोनों ही बढ़ रहे हैं।

2 लगातार चलने से दबाव
ज्यादा गर्मी में लगातार चलने से AC पर दबाव बढ़ता है। ओवरहीटिंग से आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। खराब रखरखाव, घटिया सर्विसिंग और ज्वलनशील refrigerants भी कारण हैं।

3 नए डिजाइन की जरूरत
देश में अब भी कई उपकरण 40 डिग्री सेल्सियस मानक के लिहाज से डिजाइन किए जा रहे हैं, जबकि कई शहरों में अब तापमान का 45 पार करना आम हो गया है। उमस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

4 सख्त मानकों की दरकार
सरकार को AC के लिए न्यूनतम सुरक्षा व प्रदर्शन मानक तय करने चाहिए। कम्प्रेसर और दूसरे जरूरी पार्ट्स की इंजीनियरिंग में जरूरत के अनुसार बदलाव किए जाएं। सबसे ऊपर उपभोक्ता सुरक्षा हो।

5 भविष्य की बड़ी चुनौती
साल 2050 तक भारत में AC की संख्या 110 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसीलिए ऊर्जा दक्ष डिजाइन, कम बिजली खपत और शहरों को ठंडा रखने वाली शहरी योजना पर काम करना जरूरी है।

*प्रस्तुतिः **अभिषेक मिश्र***

ऐसे आर्थिक सुधार हों, जिनसे खपत बढ़े

*ईरान और अमेरिका की लड़ाई से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ा है। इस युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है। साथ ही, भारत में अल निनो का बड़ा प्रभाव भी दिख सकता है। यह कहना है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के चीफ इकॉनमिस्ट डॉ. देवेंद्र कुमार पंत का। प्रस्तुत हैं **अखिलेश प्रताप सिंह** से डॉ. पंत की विशेष बातचीत के मुख्य अंशः*

■ पश्चिम एशिया संकट के चलते अर्थव्यवस्था के सामने कैसी चुनौतियां हैं?

यह संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, सबके दाम बढ़ गए और सप्लाई में दिक्कतें उभर आईं। हालांकि भारत में दाम उतने नहीं बढ़े क्योंकि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर घटा दी। फिर भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय भाव बहुत ज्यादा बढ़ने पर उसका बोझ आगे बढ़ाना पड़ा। हालांकि अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था में भी महंगाई दर 4% के करीब पहुंच चुकी है, जो 2% के आसपास रहती थी। पश्चिम एशिया संकट बड़ा खतरा इसलिए है कि इसका असर LPG, नैचरल गैस से आगे चलकर उर्वरक, सेरामिक, बिटुमिन सहित तमाम चीजों पर बढ़ सकता है।

दूसरी बात यह है कि विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश से बाहर निकलने के चलते रुपया कमजोर हुआ है। इससे एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है, लेकिन जब तक ग्लोबल इकॉनमी में डिमांड नहीं बढ़ती, तब तक केवल रुपये के कमजोर होने से निर्यात उतना नहीं बढ़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर है। आयात बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा। ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट हुआ तो इसका भी इस पर असर पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से रुपये पर दबाव और बढ़ता है। इससे पेट्रोलियम और खाद्य तेल से लेकर उर्वरक सहित जो भी चीजें आयात की जाती हैं, उनके दाम रुपये में बढ़ेंगे। इसका असर ज्यादा महंगाई के रूप में दिखेगा। इसका प्रभाव ब्याज दरों पर होगा। इस तरह पश्चिम एशिया संकट का असर काफी बड़ा हो सकता है।

सप्ताह का इंटरव्यू

डॉ. देवेंद्र कुमार पंत

■ क्या युद्ध का असर देर तक रह सकता है?

ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म होते ही कीमतें एकदम से नीचे आ जाएंगी क्योंकि जिस तरह से उस इलाके में रिफाइनरी से लेकर गैस के कारखानों तक पर असर पड़ा है, उसके चलते लंबे समय तक प्रभाव बना रह सकता है। युद्ध रुकने पर भी कीमतों को लड़ाई शुरू होने के पहले के स्तर पर जाने में करीब 6 महीने या इससे ज्यादा लग सकते हैं।

■ अल निनो और पश्चिम एशिया संकट का ग्रामीण इलाकों में कैसा असर दिख सकता है?

अभी मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होने से 100 के बजाय 125 दिनों तक काम मिलेगा। पिछले दो-तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड शहरों से ज्यादा मजबूत रही है। गांवों में शहरों के मुकाबले बेरोजगारी दर भी कम रही है। लेकिन खेती-बाड़ी ज्यादा प्रभावित हुई, तो रूरल डिमांड पर असर आ सकता है।

■ महंगाई का मिजाज कैसा रह सकता है?

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जो अंडर-रिकवरी बताई जा रही है, उसके हिसाब से पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम थोड़ा-थोड़ा करके 12-13 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। हमारा अनुमान है कि इसके चलते इस साल ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.5% के करीब रह सकती है। इसमें हमने यह माना है कि अप्रैल से जून तक क्रूड के दाम 110 डॉलर/बैरल पर रहेंगे, जुलाई-सितंबर में 100 डॉलर पर, अक्टूबर-दिसंबर में 90 डॉलर और जनवरी-मार्च 2027 में 80 डॉलर/बैरल के करीब आ जाएंगे। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट के चलते महंगाई का जो रुझान बना है, वह अगली तीन-चार तिमाहियों में साइक्लिकल से परमानेंट तो नहीं हो जाएगा, यह देखना होगा।

■ इकॉनमी और मजबूत करने के लिए किन आर्थिक सुधारों की जरूरत है?

हिंदुस्तान के पक्ष में एक जो सबसे बड़ी बात रही है, वह कोविड के बाद दिखी थी। जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा करीब 60% है। सुधार ऐसे होने चाहिए, जिनसे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़े। आम आदमी की ओर खपत बढ़ाने के लिए वेजेज का रियल टर्म में बढ़ना जरूरी है। अब जो लेबर कोड लागू हुए हैं, उनमें असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को फायदा होगा तो खपत बढ़ने की संभावना है। इकॉनमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर को ज्यादा उत्पादन करना होगा और इससे अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

■ विदेशी निवेशक लंबे समय से बिकवाली कर रहे हैं। क्या यह ट्रेंड जल्द बदलेगा?

इक्विटी इनवेस्टमेंट से विदेशी निवेशकों के निकलने के कई कारण होते हैं। वे यह भी देखते हैं कि किस बाजार से उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। यह रिटर्न हमेशा डॉलर टर्म में होगा। जिस तरह रुपये में 6-7% कमजोरी आई है, उससे डॉलर टर्म में विदेशी निवेशकों के लिए रिटर्न घटा है। विदेशी निवेशकों को टैक्स के मामले में रियायत मिलने पर उनका मूड कुछ बदल सकता है।

www.nbt.in

अपने-अपने आंबेडकर

कुछ अरसा पहले संसद भवन परिसर में बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला। मेट्रो स्टेशन पर मेरे कॉलोनी के तिवारी जी, शर्मा जी और खान साहब भी मिल गए। तिवारी जी ने बताया कि वह एक सरकारी कार्यक्रम में कुछ स्कूली बच्चों को साथ ले गए थे। आयोजकों ने बताया था कि बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे, मगर कुछ नहीं दिया।

उत्सुकतावश मैंने पूछा कि कैसा कार्यक्रम था। वह बोले, 'बच्चों के लिए क्विज थी। भाई साहब, अब तो सरकारी कार्यक्रम महज औपचारिकता रह गई है। वहां काम करने वाली एक महिला ने बताया था कि मंत्रालय से बस का किराया मिलेगा। लेकिन, वह भी नहीं मिला। पूछने पर महिला ने कहा कि मंत्री जी ने ही बजट कम कर दिया।' मैंने पूछा कि फिर कहां से मिलता? जिस पर तिवारी जी ने कहा कि मंत्री को इससे क्या लेना-देना। अधिकारी ही बेईमान हैं, वही ऐसा करते हैं।

'ऐसा नहीं है। मंत्री भी सही नहीं होते हैं।' बीच में शर्मा जी बोल पड़े। 'देखो यूपी में योगी जी ने कैसा पूरा प्रदेश सुधार दिया है। अब आप रात-बेरात कभी भी कहीं भी जा सकते हैं।' सफर के दौरान एक और परिचित मेट्रो में आए और मेरे बगल की सीट पर बैठ गए। वह एक बुजुर्ग वामपंथी थे। हमारी बातचीत आसपास के लोग भी सुन रहे थे। मैंने कहा कि यूपी में कानून-व्यवस्था पहले भी ठीक थी, तब मेरे सामने बैठे एक शख्स ने तपाक से कहा, नहीं। योगीजी ने प्रदेश को सुधारा है। खान साहब सभी बातों में हां में हां मिला रहे थे। तभी मेरे बगल में बैठे बुजुर्ग वामपंथी ने आरोप लगाया कि आंबेडकर तो साम्राज्यवादी और सामंतवादी थे। मैंने उनसे कहा कि लगता है कि आपने आंबेडकर को पढ़ा नहीं है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, 'वह अंग्रेजों के साथ रहते थे।' मैंने कहा, 'वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए आंबेडकर भगवान से कम नहीं हैं।'

खुद अपनी आंख से

सैयद परवेज़

तब तक केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन आ गया और हम लोग वहां से निकलकर संसद भवन के गेट नंबर-1 पर पहुंच गए। वहां पता चला कि गेट बंद हो गया है। मैंने एक पुलिस वाले से कहा कि जाने दीजिए, तो उसने कहा कि अब कार्यक्रम खत्म होने पर 9 बजे के बाद ही एंट्री मिलेगी। संसद के बाहर जय भीम के नारे गूंज रहे थे। दलित और शोषित वर्ग के लोगों की आंखों में दलित चेतना की चमक दिख रही थी। तब मुझे खयाल आया कि क्या किसी की उम्र बढ़ जाने, ऊंचे पद पर पहुंच जाने या किसी आंदोलन में पूरी उम्र गुजार देने से क्या अक्ल आ जाती है? अक्ल उम्र या पद से नहीं आती। वह चिंतन, अनुभव और समाज की वास्तविकताओं से जुड़कर आती है।

चलते-चलते...

स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की पुष्टि हाल ही अमेरिका से प्रकाशित *Pediatrics* पत्रिका में भी की गई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन्हें 12 वर्ष से पहले स्मार्टफोन मिल गया था, उनमें डिप्रेशन, मोटापा और नींद की समस्याएं अधिक थीं। अध्ययन के अनुसार, जितनी कम उम्र में स्मार्टफोन मिला, जोखिम उतना ही अधिक पाया गया।

रीडर्स मेल

▸ पर्यावरण बचाने का संकल्प

पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरियाली और जैव विविधता के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर वर्ष 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का कम उपयोग जैसे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और रहने योग्य बनाना होगा।

-दीपा सिन्हा, ईमेल से

▸ हादसों से कब सीखेंगे?

दिल्ली के एक होटल में लगी आग ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुखद यह है कि ऐसे हादसों के बाद जांच, कार्रवाई और मुआवजे की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन लापरवाही का सिलसिला थमता नहीं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहायशी इलाकों में अवैध गतिविधियां न चलें और बड़े भवनों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों। भवनों में आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था की नियमित जांच जरूरी है। हादसे अचानक होते हैं, लेकिन उनके पीछे अक्सर लापरवाही और नियमों की अनदेखी जिम्मेदार होती है। समय रहते सबक लेना ही ऐसी त्रासदियों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही नागरिकों में आपदा के समय बचाव और निकासी संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित मॉक ड्रिल भी आयोजित की जानी चाहिए।

-साजिद अली, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 इस समाचार-पत्र का प्रकाशन आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए किया गया है। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) मुद्रण उपेंद्र नायक द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई-400101 में (टेलीफोन नंबर: 66353535, 22733535) और इंद्रजीत सेन द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400 708 में (टेलीफोन नंबर: (022) 2760 9999.) किया गया है।
सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित।
सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलोंके बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर,नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 6.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 7.00 रुपये।

‘माझे घर’ आजही तसेच आहे का?

फाळणीनंतर भारतात आलेल्या, आपली पाळेमुळे कुठे रुजली आहेत, या प्रश्नाचा शोध घेणाऱ्या आणि अखेर ती संविधानात आढळल्याने त्यालाच आपले घर मानणाऱ्या कायदेतज्ज्ञाची ही कथा. पण त्यांचे ते जुने घर आजही तसेच आहे का, हा प्रश्न प्रत्येकाने विचार करावा असाच!

प्राजक्ता कदम
prajakta.kadam@expressindia.com

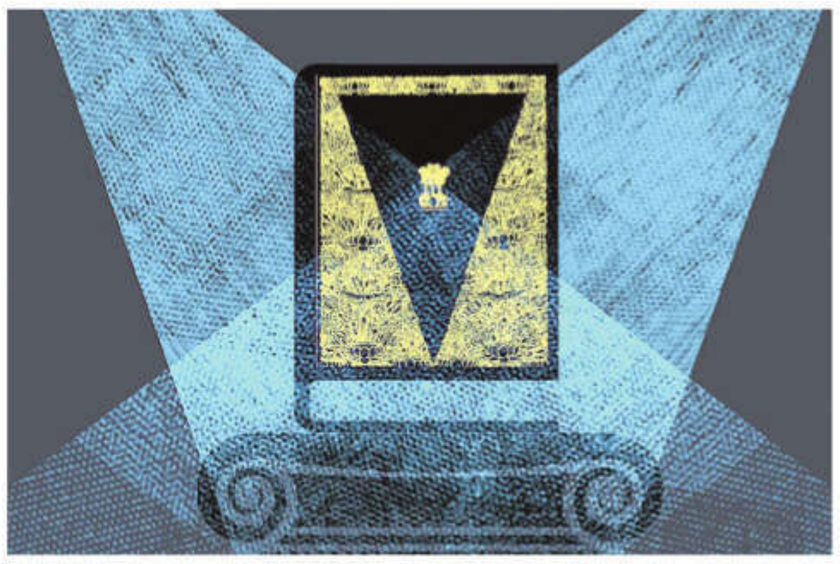

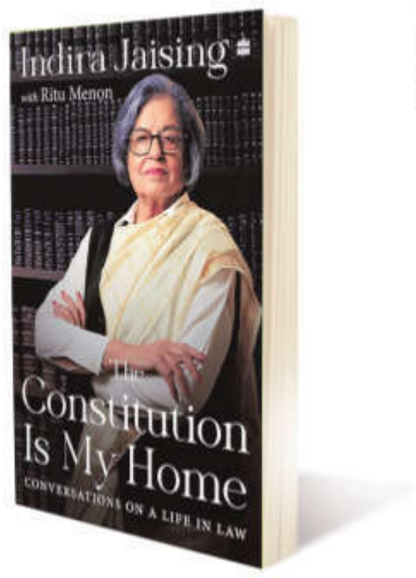

‘द कॉन्स्टिट्यूशन इज माय होमः कॉन्व्हर्सेशन्स ऑन अ लाइफ इन लॉ’
लेखक : इंदिरा जयसिंग आणि रितू मेनन.
प्रकाशन : हार्पर कॉलिन्स इंडिया
पृष्ठे : २२०, **किंमत :** ६९९ रु.

ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या इंदिरा जयसिंग यांची ओळख करून देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयीन क्षेत्रातील त्यांच्या भरीव कार्यामुळे जयसिंग आज प्रतिष्ठित आणि नामांकित कायदेतज्ज्ञांच्या पंक्तीत समाविष्ट झाल्या आहेत. मात्र एका टप्प्यावर आपली ओळख काय आणि आपण नेमक्या कुठल्या, या प्रश्नांनी त्यांना भेडसावले होते. त्यांच्या आयुष्यातील बराच काळ या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर शोधण्यात गेला. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर त्यांचे सिंधी कुटुंब भारतात निर्वासित म्हणून आले होते. भारतात सिंध नावाचे कोणतेही राज्य नाही, ही त्यांना पडलेल्या प्रश्नामागील पार्श्वभूमी होती. मात्र, वैयक्तिक अनुभवांतून आणि वकिली करताना त्यांना या प्रश्नाचे एक उत्तर सापडले- ‘आपण कोणत्याही राज्याच्या किंवा प्रांताच्या नाही, तर भारताच्या संविधानाच्या आहेत आणि संविधानच आपले घर आहे.’ ही त्यांची भावना विविध न्यायालयांत विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना प्रबळ झाली आणि आजही ती कायम असल्याचे जयसिंग यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘द कॉन्स्टिट्यूशन इज माय होमः कॉन्व्हर्सेशन्स ऑन अ लाइफ इन लॉ’ या पुस्तकातून स्पष्ट होते.

वैयक्तिक अनुभव आणि पाच दशकांच्या वकिली क्षेत्रातील कारकीर्दीचा आढावा घेणाऱ्या या पुस्तकाचे शीर्षक, त्यामुळेच एक रूपक नसून नागरिकत्वाचा दावा आहे. प्रकाशक रितू मेनन यांच्याशी त्यांनी साधलेला हा संवाद, स्वतः निवडलेल्या घराचे रक्षण करण्यासाठी ५० वर्षे घालवलेल्या एका महिलेची एकप्रकारची साक्ष आहे. या मुलाखतरूपी पुस्तकात जयसिंग यांनी आत्मचरित्र आणि कायदेविषयक चिंतन यांचा मिलाफ साधत, लोकशाही, राजसत्ता आणि न्यायपालिका यांच्या बदलत्या रूपांवर एक दृष्टिक्षेप टाकला आहे. न्यायालये कार्यकारी अधिकारांचा वापर कसा करतात याचे त्यांनी चिकित्सक मूल्यांकन केले आहे. तसेच न्यायालयीन उत्तरदायित्व आणि मूलभूत हक्कांच्या अढळ संरक्षणाच्या गरजेवर भर दिला आहे. फाळणीनंतर मुंबईत स्थलांतरित झाल्यावर सिंधी निर्वासित मुलगी म्हणून वाढत असताना आलेले अनुभव, त्यातून भारताचे संविधान हेच आपले ‘खरे घर’ असल्याची झालेली जाणीव या संवादातून व्यक्त होते आणि तीच पुस्तकाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यांच्यासाठी घर म्हणजे एखादा भौगोलिक प्रदेश नसून संविधानात मांडलेली समता, न्याय आणि स्वातंत्र्य यांसारखी मूल्ये असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

फाळणीच्या काळातील हिंसाचाराचा जयसिंग यांच्या कुटुंबावर खोल परिणाम झाला होता. त्यांच्या पालकांनी त्यांना आणि त्यांच्या दोन भावांना त्या काळातील कटू अनुभवांबद्दल फारसे कधी सांगितले नाही. मात्र त्याची छाया त्यांच्या वर्तनातून या मुलांना जाणवत असे. त्याबाबतचे काही प्रसंग जयसिंग यांनी पुस्तकात विशद केले आहेत. अशा वातावरणात वाढताना कायम एक प्रकारचे विस्थापन आणि मुळांपासून तुटल्याची भावना असते.

पुस्तकात, जयसिंग यांनी संवादात्मक शैलीत घटनात्मक प्रकरणांतील त्यांच्या अनेक वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेतला आहे आणि त्याचबरोबर भारताची ओळख, लैंगिक न्याय आणि बहुसंख्याकवादापुढील आव्हानांचादेखील वेध घेतला आहे. जयसिंग यांनी संविधानाशी असलेला त्यांचा आयुष्यभराचा संबंध व्यावसायिक कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर एक ओळख म्हणून मांडला आहे.

संविधान आपल्यासाठी काय आहे, हे सांगताना जयसिंग यांनी संविधानाने वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याला दिशा दिल्याचे नमूद केले आहे. त्या काळी कामगार संघटनांचे नेतृत्व करणारे माजी संरक्षणमंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस यांसह काही तळागाळातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणारे नेते, विचारवंतांमुळे त्यांच्या वकिलीला कशाप्रकारे कलाटणी मिळाली याबाबत पुस्तकात सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, वकिली क्षेत्रात प्रवेश करताना आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांत युक्तिवाद करताना त्यांना स्त्री म्हणून अनेक प्रकारच्या भेदभावांना सामोरे जावे लागल्याच्या घटनाही त्यांनी सविस्तर विशद केल्या आहेत. त्यांच्या आक्रमक युक्तिवादावरून एका न्यायाधीशांकडून त्यांना दिली गेलेली अपमानास्पद वागणूक, त्याक्षणी त्यांची असलेली मानसिक स्थिती, त्यातून सावरत पुन्हा त्याच आक्रमकतेने न्यायधीशांना दिलेले प्रत्युत्तर, याची आठवण जयसिंग यांनी सांगितली आहे. त्यांच्या अशा आठवणी न्यायालयीन क्षेत्रात त्या काळात असलेल्या पुरुषी वर्चस्वावर प्रकाश टाकतात.

अशा परिस्थितीत काम करताना लिंगभेदास मनाई करणाऱ्या संविधानातील अनुच्छेद १५मुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. संविधानामुळेच अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद मिळाली. लैंगिक छळ, बेघर नागरिकांचे हक्क आणि फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर काम करताना संविधानातील तत्त्वे त्यांच्या लढ्याचा आधार ठरल्याचे जयसिंग यांनी सांगितले आहे. हक्क केवळ कागदावर असणे पुरेसे नाही, त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करताना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे महत्त्व प्रामुख्याने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळेच, राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून त्यांना प्रेरणा मिळाल्याचे त्या सतत सांगतात. त्यांच्या दृष्टीने संविधान हा केवळ कायदेशीर दस्तावेज नसून शासन आणि नागरिकत्वाला दिशा देणारी नैतिक चौकट आहे.

राष्ट्राची उभारणी ही एक अखंड प्रक्रिया असून ती अविरत सुरू राहते. त्यामुळे, संविधानाच्या ‘संस्थापक मातां’नी त्यांचे कार्य पूर्ण केल्यावर त्याच्या देखभालीची जबाबदारी आपण ‘संस्थापक कन्या’ म्हणून वारसा हक्काने स्वीकारली आहे, अशा शब्दांत जयसिंग यांनी एका ठिकाणी संविधानाशी असलेल्या त्यांच्या नात्याची ओळख सांगितली आहे. त्यांच्या इतक्या सातत्याने आणि निर्भयपणे भारताच्या घटनात्मक परिदृश्याला आकार देणारे वकील फारच थोडे आहेत. पाच दशकांहून अधिक काळ, त्यांनी देशातील काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढ्यांचे नेतृत्व केले आणि लिंगभाव, असमानता, राज्याकडून होणारी हिंसा आणि संस्थात्मक उपेक्षा यांसारख्या वास्तवातील प्रश्नांची दखल घेण्यास त्यांनी न्यायालयांनाही भाग पाडले. या पुस्तकात, जयसिंग यांनी कायदा आणि सामाजिक चळवळींच्या आघाडीवर व्यतीत केलेल्या आपल्या आयुष्याचा मागोवा घेतला आहे.

अनेक न्यायालयीन प्रकरणांतून आपण घडत गेलो, याची जाणीव जयसिंग यांना आहे. त्याची माहिती त्या विस्ताराने देतात. ती प्रकरणे कशी उभी राहिली आणि त्यांनी कायद्यांत कसा बदल घडवला, या लढाईत त्यांना कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले, वैयक्तिक पातळीवर कशाप्रकारे टीका सहन करावी लागली, हे जयसिंग यांनी विशद केले आहे. मेरी रॉय प्रकरण आणि समान वारसा हक्कासाठीचा लढा; रूपन देओल बजाज खटला आणि लैंगिक छळाच्या विरोधात न्यायाचा पाठपुरावा; पदपथावर राहणाऱ्यांच्या उपजीविकेच्या अधिकाराला मान्यता देणारे ओल्गा टेलिस प्रकरण, तिहेरी तलाकाला आव्हान देणारे शायरा बानो प्रकरण; भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांसाठी त्यांनी दिलेला दीर्घकालीन कायदेशीर लढा आणि महिलांच्या उपासनेच्या अधिकाराशी संबंधित शबरीमला प्रकरण यांचा त्यात समावेश आहे. एका माजी सरन्यायाधीशांवरील लैंगिक छळाच्या आरोप प्रकरणातील अंतर्गत कार्यपद्धतीवर जाहीरपणे टीका केल्यानंतर काही दिवसांनी, २०१९ मध्ये जयसिंग यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांबाबत बोलताना त्यांनी, ज्या संस्थेची मी आयुष्यभर सेवा केली, त्याच संस्थेने माझ्यावर हल्ला केला अशी खंत व्यक्त केली आहे.

सध्या संविधानाला सर्वाधिक धोका

पुस्तकाचा एक मोठा भाग आजच्या राजकीय परिस्थितीवर केंद्रित आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्य व्यवस्था संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे आणि आतापर्यंत संविधानच सर्वश्रेष्ठ राहिले असल्याचे जयसिंग सांगतात. मात्र, गेल्या दशकभरापासून संविधानात थेट बदल न करता शासनाला हाताशी धरून या मूल्यांना कमकुवत केले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद आणि बहुसंख्याकवादी राजकारणामुळे सांविधानिक मूल्यांची जागा वैचारिक उद्दिष्टे घेत असल्याबाबत त्यांनी पुस्तकात चिंता व्यक्त केली आहे. जयसिंग यांनी १९७५ च्या आणीबाणीची तुलना आजच्या परिस्थितीशी केली आहे. मात्र त्यांच्या मते आजचा धोका वेगळ्या स्वरूपाचा आणि अधिक गंभीर आहे. आणीबाणीच्या काळात दडपशाहीसाठी संविधानातील तरतुदींचाच वापर करण्यात आला होता आणि सत्ता केंद्रित करण्यात आली होती. आज मात्र संविधानात बदल न करता त्यातील उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना बाजूला सारले जात आहे, नाकारले जात आहे. संस्थांची स्वायत्तता कमी करणे, उत्तरदायित्व घटवणे आणि सांविधानिक मूल्यांपेक्षा सांस्कृतिक ओळखीला महत्त्व देणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा इशारा जयसिंग यांनी पुस्तकात दिला आहे.

लढाऊ बाण्याच्या अभावाबाबत खंत

जयसिंग यांनी पुस्तकात न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर टीका करतानाच या व्यवस्थेविषयी आशावादही व्यक्त केला आहे. एका विशिष्ट विचारसरणीच्या आधारे शासन करणाऱ्या सरकारच्या निर्णयांना रोखण्यात देशातील सध्याची न्यायव्यवस्था अपयशी ठरत आहे, अशी टीका करताना सध्याची स्थिती पाहता घटनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आता जनतेवरच असल्याचे जयसिंग यांनी म्हटले आहे. न्यायालयांतर्गत कायद्याची शिस्त आणि अधिक मजबूत, अधिक ठाम वकीलवर्गाच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला आहे. केवळ एक मजबूत वकीलवर्गच न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू शकतो. परंतु, याचाच सध्या अभाव असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

वाढता हिंदू राष्ट्रवाद, माघार घेणारी न्यायव्यवस्था आणि दिवसेंदिवस ठिसूळ होत जाणारी लोकशाही यांची गडद छाया देशावर सध्या पसरली असल्याचे जयसिंग यांनी पुस्तकात वारंवार अधोरेखित केले आहे. तरीही त्या हे संकट संविधानाच्या माध्यमातूनच दूर केले जाऊ शकते, अशी आशा व्यक्त करतात. त्यामुळेच, स्पष्ट, निर्भीड आणि सखोल राजकीय भान असलेले ‘द कॉन्स्टिट्यूशन इज माय होमः कॉन्व्हर्सेशन्स ऑन अ लाइफ इन लॉ’ हे पुस्तक देशातील एका प्रेरणादायी कायदेतज्ज्ञाने नोंदवलेला प्रतिकाराचा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असून त्याद्वारे प्रजासत्ताकाच्या संस्थापकांनी दिलेल्या वचनांना ठामपणे जपण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि, ‘माझे जुने घर (संविधान) आजही तेच आहे का, जे मला एकेकाळी माहीत होते?’ हा जयसिंग यांचा एक संयत, मात्र धारदार प्रश्न नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे.

एका विश्वकोशाची संघर्षकथा

तमिळ विश्वकोशाच्या निर्मितीचा इतिहास सांगतानाच भाषा, ज्ञान आणि सांस्कृतिक राजकारणाचे गुंतागुंतीचे पदर उलगडणाऱ्या पुस्तकाविषयी...

अवनीश पाटील
avnishpatil@gmail.com

गूगल आणि विकिपीडियाच्या आधीच्या काळात एखाद्या भाषेत विश्वकोश असणे, हे त्या भाषेच्या बौद्धिक परिपक्वतेचे चिन्ह मानले जात असे. विश्वकोश म्हणजे केवळ माहितीचा साठा नव्हे, तर एका समाजाच्या ज्ञानेच्छेचा, भाषिक आत्मसन्मानाचा आणि आधुनिकतेच्या दाव्याचा दस्तावेज असतो. ए. आर. वेंकटचलपती यांचे ‘द ब्रीफ हिस्टरी ऑफ अ व्हेरी बिग बुक, द मेकिंग ऑफ द तमिळ एन्सायक्लोपीडिया’ हे पुस्तक तमिळ भाषेतील ‘कलईक्कलंजीयम’ या महत्त्वाकांक्षी विश्वकोशाच्या निर्मितीमागील श्रम, जिद्द आणि सामूहिक संकल्पाची सूक्ष्म व चिंतनशील कहाणी उलगडते. मराठी वाचकाला हे वाचताना सहजच आपल्या विश्वकोश परंपरेचीही आठवण होते.

हे पुस्तक केवळ एका प्रकल्पाचा इतिहास नाही. विसाव्या शतकातील तमिळनाडूचा बौद्धिक प्रवास, भाषाशुद्धीचे वाद, मुद्रणसंस्कृती, संस्थात्मक अडथळे आणि सांस्कृतिक राजकारण यांचा तो सखोल दस्तावेज आहे. विश्वकोश तयार करणे म्हणजे केवळ ज्ञान गोळा करणे नव्हे. कोणतीही भाषा आधुनिक संज्ञा कशी घडवते, स्वतःला कशी प्रमाणित करते आणि स्वतःचे सांस्कृतिक स्थान कसे निर्माण करते, याचीही ती प्रक्रिया असते. हे पुस्तक सातत्याने हेच वास्तव अधोरेखित करते.

‘द ब्रीफ हिस्टरी ऑफ अ व्हेरी बिग बुक, द मेकिंग ऑफ द तमिळ एन्सायक्लोपीडिया’
लेखक : ए. आर. वेंकटचलपती
प्रकाशक : पर्मनंट ब्लॅक
पृष्ठे : १४३, **किंमत :** ३९५ रुपये

पुस्तकाचा पहिला भाग संस्थात्मक पाठबळ नसताना वैयक्तिक जिद्दीवर विश्वकोश घडवणाऱ्या, झपाटलेल्या व्यक्तींना समर्पित आहे. ए. सिंगारवेलू मुदलियार (१८५५-१९३१) यांनी १८९० च्या सुमारास ‘अभिताना चिंतामणी’ हा विश्वकोश तयार करण्याचे काम हाती घेतले. इंग्रजी कोशकार सॅम्युअल जॉन्सनप्रमाणेच त्यांनी एकट्याने संशोधन केले. या कामापायी त्यांचे आरोग्य ढासळले आणि पैसाही खर्ची पडला. अखेरीस एका आश्रयदात्यामुळे १९१० मध्ये हा ग्रंथ प्रकाशित झाला. पुढे मृत्यूपर्यंत त्यांनी दुसऱ्या आवृत्तीचे काम सुरूच ठेवले.

पुस्तकातील सर्वांत लक्षात राहणारी व्यक्तिरेखा म्हणजे टी. व्ही. संबासिवम पिल्लई. एक साधा पोलीस कारकून, पण तमिळ-इंग्रजी वैद्यकीय शब्दकोश घडवण्याचा ध्यास घेतलेला. या कामासाठी त्यांनी १३ एकर वडिलोपार्जित जमीन विकली आणि निवृत्तिवेतनही खर्च केले. पाच खंडांच्या या प्रचंड उपक्रमातील निम्मे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. लेखकाने नोंदवलेला तपशील अस्वस्थ करणारा आहे. त्यांच्या अंत्ययात्रेवेळी आयुष्यभराच्या मेहनतीची छापील पाने तिथेच पडून होती. ज्ञाननिर्मितीमागे किती वैयक्तिक झीज दडलेली असते, याची यातून प्रकर्षाने जाणीव होते.

तमिळ विश्वकोशाची अधिकृत घोषणा झाली १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आणि हा प्रवास संस्थात्मक प्रयत्नांकडे वळला. या टप्प्यात टी. एस. अविनाशिलिंगम आणि मुख्य संपादक एम. पी. पेरियास्वामी थूरन हे दोन आधारस्तंभ होते. अविनाशिलिंगम यांनी सरकारी निधीसाठी प्रयत्न केले. थूरन यांनी संपादकीय जबाबदाऱ्या आयुष्य वेचून पेलल्या. त्यांच्या समर्पणाचे एक उदाहरण लेखक देतात. त्यांच्या मुलीच्या आजारपणाच्या वेळीही त्यांच्या मनात प्रथम आलेला विचार असा होता, या आजाराची नोंद विश्वकोशात आहे का. हे वाक्य या उपक्रमाने त्यांना किती व्यापून टाकले होते, याचे मार्मिक प्रतीक आहे.

पण मोठ्या सांस्कृतिक प्रकल्पांमागे केवळ आदर्श नसतात. गोंधळ, अपुरे वेतन, कर्मचाऱ्यांचा अभाव आणि गैरव्यवहारही असतात. संस्थेच्या खजिनदाराने तब्बल तीन लाख रुपयांचा अपहार केला. त्या काळच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या मोठ्या भागाइतकी ही रक्कम होती. अंतिम ग्रंथाच्या भव्यतेमागे दैनंदिन पातळीवर किती अस्थिरता असते, हे लेखक चपखल दाखवतात.

विश्वकोशामुळे भाषेचे राजकारणही टोकदारपणे समोर आले. विज्ञानासाठी तमिळ प्रतिशब्द तयार करताना शुद्ध तमिळ वापरावी की संस्कृतप्रचुर संज्ञा स्वीकाराव्यात, यावरून वाद निर्माण झाले. द्रविड चळवळीच्या नेत्यांनी विश्वकोशावर टीका केली की तो प्रसिद्ध इंग्रजी विश्वकोश ‘ब्रिटानिका’चे अनुकरण आहे, त्यात पुराणातील निरुपयोगी संदर्भ भरले आहेत आणि त्यावर ब्राह्मणी छाप आहे. म्हणजेच वाद ज्ञानावर कोणाचा ताबा असणार, याचाही होता.

तमिळ अकादमीने अनेक जुन्या नोंदी नष्ट केल्याने त्यांच्याकडे तयार अभिलेख उपलब्ध नव्हते. उरलेल्या पत्रव्यवहार, शासकीय फाईली, खतावण्या आणि खासगी कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी हा इतिहास पुन्हा बांधला गेला. म्हणूनच हे पुस्तक एखाद्या संस्थेची अधिकृत कथा वाटत नाही. ते हरवलेल्या पुराव्यांमधून घडवलेली एक बौद्धिक पुनर्रचना वाटते. त्यात शैक्षणिक काटेकोरपणा आहे, पण शैली क्लिष्ट नाही. मानवी संघर्ष आणि संस्थात्मक तपशील यांचा तोल लेखकाने अचूक राखला आहे. कलईक्कलंजीयम १९५४ ते १९६८ या काळात प्रसिद्ध झाला. तो आज कालबाह्य वाटू शकतो, पण त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व कमी होत नाही. तो एका पिढीच्या बौद्धिक आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे. एका भाषेला आधुनिक ज्ञानाच्या तोडीस तोड उभे करण्यासाठी किती चिकाटी, श्रम आणि संघटनशक्ती लागते, याची तो ठळक साक्ष आहे. मराठी वाचकांसाठी हे पुस्तक विशेष महत्त्वाचे ठरते. मराठी विश्वकोश, मराठी कोशपरंपरा आणि ज्ञानभाषा म्हणून मराठीची उभारणी यामागेही अशाच संघर्षकथा दडलेल्या असतील. आपल्या भाषेतील मोठे प्रकल्प आपण तयार स्वरूपात पाहतो, पण त्यामागच्या आयुष्यभराच्या धडपडीची नोंद क्वचितच घेतो. आज मराठीवर इंग्रजीचे वाढते वर्चस्व, शिक्षणातील मागे पडणे आणि ज्ञानभाषा म्हणून कमी होत चाललेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर वेंकटचलपती यांचे हे पुस्तक अधिकच विचारप्रवृत्त करणारे ठरते.

हे पुस्तक एक महत्त्वाची जाणीव करून देते. ज्ञाननिर्मिती ही केवळ कल्पनांची नव्हे, तर श्रमांची, संस्थांची, पैशांची, संघर्षांची आणि भाषिक स्वप्नांची कहाणी असते. गूगलपूर्व काळात ज्ञानाचा प्रत्येक शब्द आपल्या भाषेत आणण्यासाठी माणसांनी आयुष्ये वेचली. म्हणूनच हे पुस्तक अंतर्मुख करते. एक प्रश्न सारखा मनात रुंजी घालतो, आपण आपल्या मराठी भाषेसाठी, तिच्या ज्ञानभांडारासाठी आणि तिच्या विश्वकोशासाठी तेवढी धडपड करत आहोत का?

बुकबातमी

‘प्रगल्भ’ बालसाहित्याचा गौरव

एका अस्वलाची लाल टोपी हरवली आहे. ती शोधण्यासाठी ते संपूर्ण जंगल चाळून काढते. वाटेत भेटणाऱ्या प्राण्यापक्ष्यांना त्याविषयी विचारते. शेवटी त्याला आपली टोपी मिळते, पण ज्याने टोपी घेतली, त्या सशाला तो खाऊन टाकतो. टोपी हरवणे, त्यामुळे खट्टू होणे, ती मिळेल की नाही ही हुरहुर, जंगलात भेडसावणारा एकाकीपणा, टोपी मिळाल्याचा आनंद, चोरल्याचा राग, त्या रागाच्या भरात हातून घडलेला गुन्हा आणि त्या गुन्ह्याचा पश्चात्ताप... बालकांच्या सगळ्याच गोष्टी राजा-राणीच्या नसतात. परीकथा आणि बोधकथांपलीकडेही बालकांचे भावविश्व आहे, याची जाणीव करून देणारे हे चित्रमय पुस्तक म्हणजे ‘आय वॉन्ट माय हॅट बॅक’. ज्यांनी ते लिहिले आणि चितारले त्या जॉन क्लासेन यांना नुकतेच बालसाहित्यातील प्रतिष्ठितेच्या ‘ॲस्ट्रिड लिंडग्रेन मेमोरियल अवॉर्ड’ने गौरवण्यात आले. हा पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले कॅनेडियन ठरले आहेत.

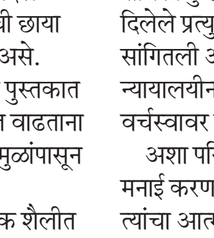

बालवयातल्या कोणत्या भावना आणि कथांच्या कोणत्या संकल्पना देशांच्या सीमा ओलांडू शकतात आणि कोणत्याही संस्कृतीत सहज विरघळून जाऊ शकतात, याचा लेखाजोखा घेऊन हा पुरस्कार दिला जातो. सर्वच वयोगटातील वाचकांचा बराच वेळ कोणत्या न कोणत्या स्क्रीनसमोर जात असल्याच्या आजच्या काळात चित्रमय पुस्तकाला पुरस्कार मिळाणे कालसुसंगतच. कथा आणि चित्रांची सांगड घातलेली पुस्तके सर्वच काळांतील मुलांना आकर्षित करत आली आहेत, पण आज अशा पुस्तकांविषयीचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे. ती केवळ अंथरुणावर पडून आजीकडून ऐकल्या जाणाऱ्या गोष्टींना पर्याय वा हसत खेळत शिक्षणाची साधने राहिलेली नाहीत. तर बालकांच्या मनातील अनिश्चितता, त्यांच्या चिंता, त्यांचे विनोद, मोठ्यांच्या व्यवहारी आणि दुटप्पी जगात वावरताना नैतिक संदर्भांविषयी त्यांच्या मनात उडणारा गोंधळ यांसारख्या भावना हाताळण्यास सक्षम कलाकृती म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले आहे.

सुरुवातीपासूनच, जगभरात बाल आणि किशोरवयीन साहित्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित एक आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून ‘ॲस्ट्रिड लिंडग्रेन मेमोरियल अवॉर्ड’कडे पाहिले जाते. तो लेखकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देतो आणि स्कँडिनेव्हियाच्या पलीकडे जाऊन अनुवाद बाजारपेठा व शैक्षणिक चर्चांवर प्रभाव टाकतो. क्लासेन यांच्या कलाकृती विशेष ठरतात कारण त्या, लिखित आशय आणि प्रतिमा यांच्यात एक विलक्षण बंध निर्माण करतात. त्यांची साधी सुटसुटीत चित्रे आणि तेवढ्याच सोप्या कथा जे शब्दांत म्हटलेले नाही वा चित्रातही दाखवलेले नाही, ते वाचण्यास पुरेसा अवकाश सोडतात. उपदेशामृत देण्याऐवजी मौन, चित्रांची पुनरावृत्ती आणि भावनिक तणावाच्या सूक्ष्म जागांतून विनोद निर्माण करतात.

‘आय वॉन्ट माय हॅट बॅक’ आणि ‘धिस इज नॉट माय हॅट’सारखी पुस्तके बालसाहित्यात गणली गेली असली, तरीही त्यांत प्रौढांशी संवाद साधण्याची क्षमता आहे. मुलांचे लक्ष विनोदावर आणि चित्रांवर केंद्रित होते, मात्र त्याच वेळी प्रौढ वाचक त्यातील अपराधीपणा, सत्ता गाजवण्याची वृत्ती, भीती किंवा सामाजिक अवघडलेपणा यांसारख्या गडद छटा ओळखू शकतात. कथांचा अर्थ लावण्याची मुलांची पद्धत मोठ्यांपेक्षा वेगळी असते, हे क्लासेन यांनी ओळखले आहे. केवळ शब्दांनी स्पष्ट न करता येणाऱ्या भावना चित्रांमधून व्यक्त करण्याचे कौशल्य त्यांनी अवगत केले आहे.

क्लासेन यांना मिळालेल्या पुरस्काराच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावर कॅनडातील बालसाहित्याविषयी कुतूहल आणि आकर्षण निर्माण होत असल्याचे दिसते. तेथील अनेक पुस्तकांत बालकांचे साहित्य आणि प्रौढांचे साहित्य यातील सीमा रेषा धूसर होताना दिसते.

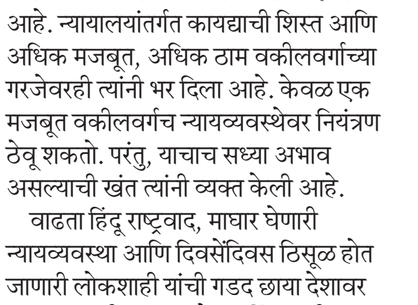

‘न्यू यॉर्कर’चा फिक्शन विशेषांक...

न्यू यॉर्करच्या समर फिक्शन विशेषांकाचे गणित गेल्या काही वर्षांत थोडे कोसळत गेले. वास्तविक युरो-अमेरिकी उन्हाळ्यातला हा अंक जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच यायचा. पण करोनानंतर जूनच्या मध्यापासून जुलैच्या आरंभीच्या आठवड्यात कधीही तो प्रकाशित होऊ लागला. यंदा मात्र जून महिन्यातील पहिलाच अंक पारंपरिक मुहूर्ताबरहुकूम फिक्शन विशेषांक म्हणून सादर झाला आहे. नोबेल विजेत्या फ्रेन्च साहित्यिका ॲनी अर्नो, अमेरिकी-आफ्रिकी लेखिका तायी सेलासी, अफगाणी- अमेरिकी नागरिकांचे जगणे कथांमधून मांडणारे जमिल जन कोचाई आणि ज्येष्ठ अमेरिकी लेखक जोनाथन फ्रॅन्झन आदींच्या कथा यावर्षी कथा विशेषांकात आहेत. त्याशिवाय एक पानी निबंध यावेळी ‘फॅमिली व्हॅल्यूज’ या संकल्पनेभोवती आखला आहे. या दुव्यातील पहिल्या चार कथा ताज्या अंकातील.

- *https://tinyurl.com/y439u53h*

बुक-नेट

बुकर आणि वाचन...

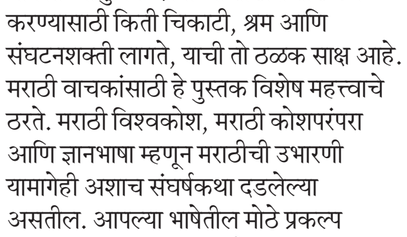

‘इंटरनॅशनल बुकर’ पारितोषिकाच्या निवड समिती सदस्यांत यंदा निलंजना रॉय या ‘फायनान्शिअल टाइम्स’मध्ये पुस्तकांवर सदर लिहिणाऱ्या समीक्षिकेचाही समावेश होता. कोलकाता येथे जन्मलेल्या रॉय गेली २० वर्षे आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये लिहिताहेत. ‘द गर्ल हू एट बुक्स’ हे त्यांचे पुस्तकप्रेमावरील निबंधांचे पुस्तकदेखील लोकप्रिय. त्यांनी सात-आठ महिन्यांत प्रत्येक सदस्याने वाचलेल्या पुस्तकांचा तपशील दिला आहे. रोजच्या जगण्यावर तसेच सामाजिक आयुष्यावर झालेला परिणाम यांवरही चर्चा केली आहे. तो लेख सशुल्क आहे; पण माहितीसाठी पर्याय म्हणून बुकरच्या संकेतस्थळावर असलेली ही मुलाखत वाचता येईल. निवड समिती सदस्यांचा आणखी तपशीलदेखील या मजकुरात स-छायाचित्र मिळेल.

- *https://tinyurl.com/4x72hsjw*

सर्वोत्कृष्ट कादंबरीच्या मागावर...

ब्रिटनमधील निम्मी जनता पुस्तके वाचत नसल्याचा अहवाल गेल्या वर्षी ‘गार्डियन’मध्ये विस्तृत सर्वेक्षणानंतर प्रसिद्ध करण्यात आला होता. मोबाइलमुळे मनोरंजन आणि ज्ञानाच्या इतक्या माहितीपोया तयार झाल्या आहेत की आबालवृद्ध त्यात गुंतलीत. बहुतांश नागरिकांचे अभ्यासापलीकडे विरंगुळा हे वाचनकारण उरलेले नाही. अजूनही १२० ते २०८ पानांचे वृत्तपत्र जिथे विकले जाते तिथली ही स्थिती नेटफ्लिक्स युगातच झाली, हा निष्कर्ष. आता यात बदल घडावा यासाठीच म्हणून की काय तीन आठवड्यांपूर्वी जगभरच्या कित्येक लेखकांशी, समीक्षकांशी चर्चा करून सर्वोत्तम १०० कादंबऱ्यांची यादी ‘गार्डियन’मध्येच जाहीर झाली. यादीत (शंभर पुस्तकांसह) पहिल्या दहा कोणत्या ते जाणून घेण्यासाठी आणि निष्णात लेखकांकडून या यादीच्या निमित्ताने घडलेली चर्चा जाणून घेण्यासाठी पुढील दुवे.

- *https://tinyurl.com/386834ny*
- *https://tinyurl.com/5an44ztn*

परदेशांतले 'आत्म'दर्शन...

देशाभिमान ठीक, संस्कृतीचा अभिमान तर छानच; पण तो अन्य देशांत किती- कसा आणि कुठे दाखवावा, 'आत्मीयता' किती ठेवावी याचे सुटले भान, तर?

आपण विश्वगुरू आहोत, याबद्दल अनेकांच्या मनात कोणतीही शंका नाही. त्याशिवाय जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन)नुसार आपण जगातली सहाव्या क्रयशक्ती समानतेनुसार जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोतच. साहजिकच महासत्ता बनण्यापासून फार दूर नाही... 'ऑपरेशन सिंदूर'सारख्या मोहिमांतून आपण कोणत्याही शत्रुदेशाला कशी सहज धूळ चारतो हे सगळ्या जगाने नुकतेच आ वासून बघितले आहे. शिवाय देशातल्या अर्बन- रुरल नक्षल्यांचा, फालतू डाव्यांचा, बिनडोक समाजवाद्यांचा आणि मूर्ख काँग्रेसवाल्यांचा जवळपास नायनाट करण्यात आला आहे. जगभर जाल तिकडे भारतीयच भारतीय दिसताहेत. अनेक देशांमध्ये त्यांनी राजकीय सत्तापदे मिळवली आहेत. मोठमोठ्या अमेरिकी कंपन्यांची प्रमुखपदे हस्तगत करून त्यांनी भारतीय संस्कृतीचा डंका पिटला आहे. अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न 'वसुधैव कुटुम्बकम'मध्ये परावर्तित झाले आहे. आता हे विश्वचि माझे घर... अशा वेळी आपले परके असे काही उरतच नाही. 'हे विश्वाचे अंगण आम्हां दिले आहे आंदण' या भावनेने आपली म्हणजे भारतीय माणसे जगभर वावरताना दिसतात.

एके काळी साप, गारुडी, वाघ, हत्ती रस्त्यावर फिरतात, अशा देशातले लोक या नजरेने ज्यांच्याकडे बघितले गेले होते, त्या देशातले लोक इतक्या आत्मविश्वासाने दुनिया फिरतात, हे ज्यांना बघवत नाही, भारताच्या या सगळ्या प्रगतीबद्दल ज्यांना असूया वाटते, असे लोकच या विश्वगुरू असलेल्या देशातल्या लोकांच्या सगळ्याच गोष्टींवर सतत टीका करत राहतात... या नतद्रष्ट लोकांनी गेल्या काही वर्षांत भारतीय पर्यटकांच्या वागण्याला नावे ठेवणे सुरू केले आहे...

आता आपल्याला हवे तिथे जाऊन, हवे तसे मनमौजी वागून, सुट्टी मस्त घालवून निघण्याच्या आनंदात काही भारतीयांनी घेतला एखाद्या विमानतळाच्या धावपट्टीवर मनमुरादपणे त्यांच्या पारंपरिक नृत्याचा आनंद तर कुठे आणि काय बिघडले? कुणा नतद्रष्टाने त्याचे चित्रीकरण करून समाजमाध्यमांवर नेताच, 'यांनी तर धावपट्टीजवळच गरबा खेळून कशी देशाची लाज घालवली,' वगैरे चोची मारणारेही लगेच पुढे आले. पण व्हिएतनामसारख्या देशात जाऊन विमानतळावरच नाही, तर त्याच्या धावपट्टीजवळ असेल, पण आपल्या नृत्यसंस्कृतीचे दर्शन घडवणे म्हणजे लाज घालवणे कसे बरे? तिथल्या धावपट्टीवरच्या कर्मचारी वर्गाला तरी यामुळे कळले असेलच ना भारतीय संस्कृती किती महान आहे आणि भारतीय लोक किती आनंदी आहेत ते. शिवाय धावपट्टीजवळ त्यांची रोजची काहीही कामे चालोत. आम्ही थोडेच रोज तिथे जातो? यांचे-त्यांचे नियम आम्ही पाळत बसलो, यांचा-त्यांचा विचार करत बसलो, तर आम्ही आमच्या सुट्टीचा आनंद कधी घेणार? तो तर प्रत्येक ठिकाणाहून शक्य तितका घ्यायला हवा. परदेशात फिरायला जाताना आम्हाला समजते की आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेत विनामूल्य मद्य मिळते. मग ते पुन्हा पुन्हा मागून हवे तेवढे घेतले तर काय बिघडले? पण लागले लगेच इतरांच्या पोटात दुखायला. हवाई सुंदऱ्या या प्रवाशांच्या सेवेसाठी नेमलेल्या अधिकृत कर्मचारी. त्यांना चारदोन वेळा बेल वाजवून पुन्हा पुन्हा बोलावून घेतले तर त्यात काय चुकले? झाला लगेच 'भारतीय लोक कसे चुकीचे वागतात'चा गजर सुरू. अलीकडेच शिकागोहून निघालेले एअर इंडियाचे एक विमान अर्ध्या वाटेतून परत फिरले म्हणे. कारण काय तर त्या विमानात खूप मोठ्या प्रमाणात भारतीय प्रवासी होते आणि त्यांनी विमानाच्या शौचालयात फ्लश करताना कपडे, प्लास्टिक पिशव्या, डायपर टाकल्यामुळे विमानातील १२ पैकी आठ शौचालये बंद पडली. या कारणासाठी विमान परत फिरवले असे म्हणणे जरा अतिच. बरेच भारतीय प्रवासी होते, म्हणजे त्यांनीच केले असे थोडेच आहे? भारतीय प्रवाशांना बदनाम करायचा हा कटच असणार; दुसरे काही नाही!

> **...तर काय म्हणून काय विचारता, मनमौजीपणे फिरायलाच जायचे असते ना आम्हाला!**

भारतीय लोक आजकाल मोठ्या संख्येने देशाबाहेर फिरायला बाहेर पडू लागले आहेत. ते उत्साहाने पर्यटनाचा आनंद घेत फिरतात आणि त्यांचा हा आनंद न बघवणारे सगळे जग भारतीय लोक कसे मोठमोठ्याने बोलतात, सगळीकडचे नियम मोडतात, गोंधळ घालतात असे म्हणत बोटे मोडते. स्वित्झर्लंडमधील एका महागड्या हॉटेलात म्हणे 'भारतीय पर्यटक पाहुण्यांसाठी' असे शीर्षक असलेल्या एका फलकावर 'बाल्कनीत, पॅसेजमध्ये हळू बोला, शांतता पाळा, न्याहारीच्या बुफेमधील पदार्थ हॉटेलच्या रूममध्ये नेऊ नका, तसे केल्यास स्वतंत्र आकार पडेल' असे लिहिले होते.

म्हणजे पुन्हा तेच. 'वसुधैव कुटुम्बकम' हा संदेश जगाला देणाऱ्या भारतीयांनी काय आपल्याच कुटुंबातही मनासारखे वागायचे नाही? आम्ही काय यांचे नियम पाळायला तिथे जातो की काय? ज्यांना शांतता हवी असते, त्यांना मजा करायची नसते, ज्यांना आमचे बोलणे बडबड वाटते, त्यांनाच त्यांच्या घरीच बसायला सांगा ना मग... काही महिन्यांपूर्वी बालीमधल्या एका हॉटेलमध्ये म्हणे एका भारतीय पर्यटक कुटुंबाच्या सामानातून हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी आरसे, शोभेच्या वस्तू, हँगर्स अशा वस्तू काढून घेत त्यांच्यावर चोरीचा आरोप केला होता. पण आवडली एखादी वस्तू, टाकली बॅगेत आत्मीयतेने, तर म्हणून लगेच कुणाला चोरासारखे वागवायचे? आम्ही आमच्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांना 'अतिथी देवो भव' म्हणतो आणि आम्ही तुमच्याकडे आल्यावर तुम्ही काय म्हणणार, तर आम्ही गोंधळ घालतो?

थायलंडमध्ये पट्टायाच्या समुद्रकिनारी आम्ही जरा मोकळेपणाने वागलो की म्हणे भारतीय पर्यटक असभ्यपणे वागतात. पण रोजच्या जगण्याला कंटाळलेले पर्यटक समुद्रकिनारी जाऊन मोकळेपणाने पहुडले, त्या वातावरणाचा आनंद घेताना झाल्या चारदोन गोष्टी, पडली चिप्सची वगैरे पाकिटे इथेतिथे, तर त्याचे काय एवढे? चारदोन माणसे कामाला लावून घ्या की स्वच्छ करून... गेलाबाजार शाळकरी मुलांसाठी एखादी स्वच्छता मोहीम राबवून समुद्रकिनारा साफसूफ करून घ्यायचा. पर्यटक म्हणून पैसे खर्च करून आम्ही तिथे जायचे आणि आम्हीच तिथल्या स्वच्छतेची काळजी करायची, हा कुठला न्याय? आमच्याकडे नसते असे काही. शिवाय त्या पट्टायाच्या समुद्रकिनारी नैसर्गिक विधींसाठी केवढे पैसे मोजावे लागतात. 'होल वावर इज अवर' असताना त्यासाठी पैसे कशाला द्यायचे? आणि थायलंडचे काय सांगता? पर्यटकांच्या म्हणजे आमच्या पैशांवर चालणारा हा देश. आता म्हणे पर्यटकांच्या गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी त्याने ९३ देशांमधील पर्यटकांवर बंधने घातली आहेत. पण त्यात महान भारताचाही समावेश करायचा? पुण्याहून मुंबईला जावे तसे आपले लोक बँकॉक, पट्टायाला जात असताना आपल्यासाठीची ६० दिवसांची व्हिसामुक्त सवलत नेमकी मे महिन्याआधीच थायलंडने रद्द करून १५ दिवसांवर आणायची? शिवाय आता यापुढच्या काळात थायलंडला जायचे तर ई व्हिसा घेऊन त्यासाठी एका वेळचे अडीच हजार रुपये भरायचे? असे असेल तर थायलंडला काय सोने लागले आहे की काय? इतर ठिकाणी जाऊ.

तर हे सारे असे आहे. आपण वेगाने प्रगती केली आहे. आपला खूप विकास झाला आहे. त्यामुळेच २०१४ च्या आधीच्या काळाच्या तुलनेत आता भारतीय लोकांकडे खूप पैसा आला आहे. ते खूप मोठ्या संख्येने परदेशी फिरू लागले आहेत. जगात वावरण्याचा आधी कधीच नव्हता इतका आत्मविश्वास त्यांच्याठायी निर्माण झाला आहे. त्याचे दर्शन ते जिथे जातात, तिथे त्यांच्या वागण्यातून होत राहते. अनोळखी ठिकाणी जाऊन आपल्याला हवे तसे वागणे हे सोपे नाहीच मुळी. भारतीयांचा हा आत्मविश्वास जगाला झेपत नाही... म्हणून तर भारतीय पर्यटकांच्या बेशिस्तीबद्दल वटवट वाढते... याला अपवाद असतीलच, त्यांना वाटेल हे सारे अनाठायी... पण परदेशांतले 'आत्म'दर्शन तेवढ्याने थोडेच थांबेल!

मंदीच्या झळांतून युद्धाच्या ज्वाळांकडे

ऑलिम्पिक आख्यान

सिद्धार्थ खांडेकर
siddharth.khandekar@expressindia.com

अमेरिकेत आणि एकूणच जगभर १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीनंतर ऑलिम्पिक भरवण्याची धमक अमेरिकेनेच दाखवली. रोम येथे १९२३ मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक समितीच्या अधिवेशनात लॉस एंजलिस या एकाच शहराची बोली दाखल झाली होती. इतर कोणत्याही शहराने - युरोपातील वा अमेरिकेतील - ऑलिम्पिक भरवण्याची इच्छा प्रदर्शित केली नव्हती. मंदीच्या ऐन मध्यावर अनेक देशांची स्पर्धेसाठी पथके पाठवण्याचीही ऐपत नव्हती. ॲमस्टरडॅम (१९२८) ऑलिम्पिकसाठी ४६ देशांनी पथके पाठवली. लॉस एंजलिसमध्ये हा आकडा ३७ वर येऊन घसरला. त्यामुळे सहभागी खेळाडूंची संख्या सेंट लुईस १९०४ ऑलिम्पिकनंतर प्रथमच इतकी कमी नोंदवली गेली. तरी ती फार निराशाजनक नव्हती असे अनेक अमेरिकी विश्लेषक आजही सांगतात. कारण लॉस एंजलिस हे अमेरिकेच्या पार पश्चिम टोकावरील कॅलिफोर्निया राज्यात वसलेले शहर. त्या काळात विशाल अमेरिकेत फार मोठ्या प्रमाणात वाहतूक साधनेही नव्हती. या पार्श्वभूमीवर प्रतिसाद यापेक्षाही कमी अपेक्षित होता.

लॉस एंजलिस १९३२

अमेरिकेत भरवले गेलेले हे दुसरे ऑलिम्पिक. पण अमेरिकेतील पहिल्या, सेंट लुईस ऑलिम्पिकपेक्षा ते कितीतरी अधिक सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक ठरले. सेंट लुईसप्रमाणे एक्स्पोझिशनच्या निमित्ताने ऑलिम्पिकचा साईड-शो असा प्रकार नव्हता. वंशद्वेष, वर्णद्वेषाचे जाहीर प्रदर्शन मांडल्यामुळे सेंट लुईस ऑलिम्पिक डागाळले गेले. लॉस एंजलिस १९३२ त्यापेक्षा कितीतरी वेगळे आणि चांगले ठरले. सर्वांत उल्लेखनीय बदल ठरला वेळापत्रकाचा. आधीची बहुतेक सर्व ऑलिम्पिक एक, दोन किंवा तीन महिन्यांपर्यंत चालली. लॉस एंजलिसने हा शिरस्ता मोडून काढला. ती स्पर्धा केवळ १६ दिवस चालली. तेथूनच अर्ध्या महिन्यात किंवा त्यापेक्षाही कमी दिवसांत ऑलिम्पिक संपवण्याचा स्वागतार्ह पायंडा पडला. ऑलिम्पिक व्हिलेजची संकल्पना आधीच्या ॲमस्टरडॅम ऑलिम्पिकमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर वापरली गेली होती. त्यावेळी लाकडी केबिन उभारून तात्पुरती निवास व्यवस्था करण्यात आली होती. लॉस एंजलिसमध्ये आयोजकांनी त्याच्या एक पाऊल पुढे जात पक्क्या बांधकामाचे पूर्ण संकुलच उभारले. तोही पायंडा महत्त्वाचा ठरला. भविष्यात ऑलिम्पिक भरवताना अशा प्रकारे यजमान देशाची आणि शहराची ऑलिम्पिक व्हिलेज उभारण्याची क्षमताही जमेस धरली जाऊ लागली. ज्यांना ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने व्हिलेज उभारायचेय, त्यांना त्या संकुलाचा पुढे वापर कसा करायचा याविषयी नियोजन करणे आवश्यक ठरू लागले. पदकविजेत्यांसाठी पोडियमची उभारणी आणि शर्यतींसाठी स्टॉपवॉच आणि फोटो-फिनिश तंत्रज्ञान हे आणखी दोन महत्त्वाचे बदल याच स्पर्धेत प्रथम दिसून आले. मंदीच्या वातावरणातही या ऑलिम्पिकला अमेरिकनांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. उद्घाटन सोहळ्यास तत्कालीन अध्यक्ष हर्बर्ट हूवर उपस्थित नव्हते. त्यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष चार्ल्स कर्टिस यांच्या हस्ते स्पर्धांना प्रारंभ झाला. तरी उत्साह उदंड होता. लॉस एंजलिसमधल्या अजस्त्र कोलिसियम संकुलाच्या प्रेक्षागारात तब्बल एक लाख प्रेक्षक आले होते.

> **लॉस एंजलिस- १९३२ हे आटोपशीर, 'स्टॉपवॉच'चा उपयोग करणारे पहिले ऑलिम्पिक, तर बर्लिन-१९३६ हे इतिहासातले पहिले चलचित्रित आणि प्रक्षेपित ऑलिम्पिक. पण यापेक्षाही लक्षात राहील तो मंदीतही अमेरिकेने केलेला खर्च आणि हिटलरने स्व-प्रतिमेच्या प्रचारासाठीच ऑलिम्पिकचा केलेला वापर...**

बर्लिन १९३६ – नाझी स्पोर्ट्सवॉश!

मध्यंतरी कतारमधील फुटबॉल विश्वचषकाच्या निमित्ताने अरब स्पोर्ट्सवॉश हा शब्दप्रयोग, विशेषतः पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये वापरला गेला. अरब देशांमध्ये मूलभूत मानवी हक्कांची मुस्कटदाबी झाकोळण्याचा प्रयत्न भव्य क्रीडास्पर्धांच्या आयोजनानिमित्ताने कशा प्रकारे होत असतो,

बर्लिन १९३६ मधली ही सलामी खेळाडूंना नव्हे- हिटलरच्या भेदमूलक राजकारणाला!

यावर भरपूर लिहून येत होते. तो धागा पकडायचा, तर बर्लिन ऑलिम्पिक १९३६ स्पर्धा आधुनिक क्रीडा इतिहासातील पहिली ठसठशीत स्पोर्ट्सवॉश (sports eyewash) किंवा क्रीडा दिशाभूल ठरते. जर्मनीला युद्धखोरीबद्दल १९२० आणि १९२४ मधील ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होऊ दिले गेले नव्हते. पण १९३१ मध्ये ऑलिम्पिक समितीची बैठक झाली आणि तीत १९३६ साठीच्या यजमान देशांची चर्चा झाली, त्यावेळी जर्मनीचे नाव पुढे आले होते. अर्थात त्या दिवसांमध्ये जर्मनीत वायमार रिपब्लिकची राजवट होती. पण जर्मन कायदेमंडळ किंवा राइशस्टागमध्ये नाझी सदस्यांची संख्या लक्षणीय होती. जर्मनीमध्ये राजकीय परिवर्तन होऊ लागल्याची चाहूल त्यावेळी युरोप आणि युरोपबाहेर लागली होती. व्हर्साय करारातून सावरू लागलेल्या जर्मनीला आर्थिक उभारी आणि आंतरराष्ट्रीय स्वीकारार्हता मिळावी हा उद्देश यजमानपद बहाल करताना असल्याचे त्यावेळी सदस्यांनी सांगितले होते. पण १९३३ मध्ये नाझी नेता अडॉल्फ हिटलर जर्मनीचा चान्सेलर बनला. त्यानंतर वर्षभरातच त्याने जर्मनीची सूत्रे हाती घेतली नि स्वतःला 'फ्युरर' अर्थात (सर्वोच्च) नेता म्हणून घोषित केले. जर्मनीमध्ये निर्दय सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला मोकळी वाट मिळाली. या बदलांची नोंद घेतली जात नव्हती असे नव्हे. पण हिटलरची लोकप्रियता जर्मनीत प्रचंड होती आणि तो किमान सुरुवातीस तरी लोकशाही मार्गाने निवडून आला, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येत नव्हते.

पण अमानवी ज्यूद्वेष; समाजवादी आणि साम्यवादी विचारसरणीची गळचेपी; अश्वेत, समलिंगींची हेटाळणी हे अवगुण युरोप-अमेरिकेतील लोकशाहीप्रेमी मंडळींना खुपू लागले होते. नाझींना ज्या पाश्चिमात्य मंडळींची सहानुभूती मिळायची, त्यांना साम्यवादाविरोधात नाझीवाद वरचढ ठरतो आहे यातच समाधान वाटत होते. यात आघाडीवर होते अमेरिकी ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष ॲव्हरी ब्रुंडाग. हिटरच्या धोरणांमुळे १९३३ च्या आसपास जर्मनीतील ऑलिम्पिक इतरत्र हलवण्याबाबत विचार होऊ शकत होता. पण ब्रुंडाग हे हिटलरच्या पाहुणचाराने आणि खेळांतील पायाभूत सुविधा उभारणीत जर्मनीने केलेल्या प्रगतीने भलतेच मोहीत झाले.

ऑलिम्पिक समितीने ज्यूविरोधी धोरणांसदर्भात तत्कालीन जर्मन सरकार आणि जर्मन ऑलिम्पिक समितीकडून काही हमी घेतल्या. यात जर्मन ऑलिम्पिक संघटनेमध्ये ज्यू किंवा अर्ध-ज्यूंच्या नियुक्त्या कायम राहातील, ज्यूंना ऑलिम्पिकमध्ये खेळू दिले जाईल या प्रमुख अटी होत्या. कालांतराने जर्मनीत स्थिरावलेल्या नाझी राजवटीने यांतली पहिली अट पाळली. दुसरी अट पाळण्याची फारशी वेळच त्यांच्यावर आली नाही, कारण ऑलिम्पिक सुरू होईपर्यंत जर्मनीच्या सामाजिक, सांस्कृतिक प्रहावाहातून ज्यूंची हकालपट्टी जवळपास पूर्ण झाली होती. अनेक ज्यूंनी भेदाभेदाच्या धोरणांना कंटाळून स्वतःच माघार घेतली होती.

ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरू झाल्या, तेव्हा ज्यूविरोधी फलक उतरवणे वगैरे वरवरचे उपचार हिटलरने केले. अतिभव्य ऑलिम्पिक स्टेडियम उभारले, पण त्यावर नाझी बोधचिन्हे आणि राष्ट्रचिन्हेच अधिक प्रखरतेने दिसली. बर्लिन १९३६ हे इतिहासातले पहिले चलचित्रित आणि प्रक्षेपित ऑलिम्पिक. यातून अनेक वर्षे जगासमोर हिटलरच झळकला. भव्य तरी उद्दाम नाझी संचलने आणि ऑलिम्पिक यांतील फरकच अनेकदा कळायचा नाही. त्या स्पर्धेत जेसी ओवेन्स या अश्वेत धावपटूने चार सुवर्णपदके जिंकली. ध्यानचंद यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय हॉकी संघाने हॉकीत जादू दाखवत सुवर्णपदक जिंकले. पण त्यामुळे हिटलरचे अश्वेतांविषयी मतपरिवर्तन झाल्याचे दाखले सापडत नाहीत. उलट अधिक अविचारी चेवाने तो गोऱ्या आर्यांचा वर्चस्ववाद दामटत राहिला आणि एक दिवस स्वतःच भस्मसात झाला!

भारतीय हॉकीची द्वाही!

लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेने सर्वाधिक ४१ सुवर्णपदके जिंकली. त्या स्पर्धेआधीपासूनच अमेरिकेच्या पथकाचा ऑलिम्पिकमध्ये दबदबा दिसू लागला होता. आजही तो कायम आहे. परंतु पहिल्या लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकमध्ये एक भन्नाट प्रकार घडला. भारताकडून ॲथलेटिक्स, जलतरण या प्रकारांसाठी काही मोजके खेळाडू धाडले गेले. त्यांच्याबरोबर हॉकी संघही गेला, कारण पदकाची आशा त्यांच्याकडूनच होती. मंदीचा फटका बसल्यामुळे अनेक देशांनी हॉकी संघ धाडलेच नाहीत. खुद्द भारतीय संघालाही निधीची मोठी चणचण होती. पैसा उभा करण्यासाठी स्पर्धेपूर्वी अनेक प्रदर्शनीय सामने खेळावे लागले. इतके होऊनही प्रत्यक्ष ऑलिम्पिकमध्ये केवळ तीनच संघ उतरले – अमेरिका, जपान आणि भारत. त्यामुळे तिन्ही संघांची पदकनिश्चिती पहिल्या सामन्यापूर्वीच झाली! भारताचे वर्चस्व

वादातीत होते. त्यांनी प्रथम जपानला ११–१ असे तुडवले. मग यजमान अमेरिकेला त्यांच्याच प्रेक्षकांसमोर २४–१ असे लोळवले. ध्यानचंद यांनी ८ गोल केले. त्यांचे धाकटे बंधू रूपसिंह यांनी १० गोल केले. ऑलिम्पिकमध्ये त्यापूर्वी किंवा नंतर २४–१ इतक्या विनोदी फरकाने कोणत्याही संघाला विजय मिळवता आलेला नाही.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

सुरक्षा व्यवस्थाच 'ऑप्शनला'

'चलता है'चे बळी' हा 'अन्वयार्थ' फक्त दिल्लीमधील अग्नितांडवावर भाष्य न करता संपूर्ण देशात बेकायदा बांधकामे आणि व्यवसाय कसे दिवसाढवळ्या बिनधास्त सुरू असतात, यावर प्रकाश टाकतो. फक्त चहाच्या दुकानाची परवानगी असलेल्या जागेत पाच मजली इमारत बांधून बेड-ब्रेकफास्टच्या नावाखाली राहायला जागा दिली जाते. मालक तिथे अग्निसुरक्षेचे कोणतेही नियम पाळत नाही, हे अविश्वसनीय आहे. एकुणात खरोखरच 'चलता है' वृत्ती इतकी रक्तात भिनली आहे की काही जण मृत्युमुखी पडले तरी अनेकांना अजिबात वाईट वाटत नाही. दिल्लीसारख्या शहरात जागोजागी असे लॉज असतात जे खिशाला परवडतात, पण त्याकडे प्रशासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष होत असते. एकूणच सुरक्षा व्यवस्था व अग्निप्रतिबंध हे विषय 'ऑप्शनला' टाकल्यासारखे प्रशासन वागत आहे.

■ **माया भाटकर,** बाणेर (पुणे)

मिडास राजासारखी अवस्था

'पर्यावरणविषयक अहवालांतून दिसणारे वास्तव' हा डॉ. पल्लवी कुलकर्णी यांचा लेख (लोकसत्ता- ५ जून) वाचला. दरवर्षी होणाऱ्या पर्यावरण परिषदांवरचा खर्च आणि त्यात होणारी निष्फळ चर्चा टाळून आता कृतीची गरज आहे. आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेली युद्धे किती प्रदूषण करतात याची कल्पना संबंधित देशांना नसेल का? पर्यावरणविषयक कायद्यांना वळसा घालून अनेक अनधिकृत बांधकामे आणि विकासकामे यांतून भलेही विकासकांना पैसा मिळेल, पण शुद्ध हवा आणि पाण्याशिवाय ते जगू शकतील का? ज्या देशातील अनेक सण- उत्सव पर्यावरणाशी जोडलेले आहेत, त्याच देशात कुंभमेळ्यासाठी हजारो वृक्षांची कत्तल केली जाते आणि ते योग्य आहे हे भासवले जाते. मानवाची अवस्था मिडास राजासारखी झाली आहे. हात लावू तिथे विकास करायचा या धुंदीत निसर्ग भकास करण्याचे काम राजरोस सुरू आहे.

■ **बागेश्री झांबरे,** मनमाड (नाशिक)

नेतृत्व कमी पडले

'शहाणा निर्णय!' हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. कर्नाटकात काँग्रेसने भाकरी फिरवली आणि सिद्धरामैया जाऊन शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ त्यांना मिळेल. शिवकुमार हे सिद्धरामैयांपेक्षा अधिक निष्ठावंत आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा तरुण आहेत, २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता स्थापन होण्यात शिवकुमार यांचा वाटा सिंहाचा होता. तरीसुद्धा त्यांना डावलून सिद्धरामैया यांना मुख्यमंत्री केले आणि आता निवडणुकांना केवळ दोन वर्षे राहिल्यावर कर्नाटकची धुरा शिवकुमार यांच्या खांद्यावर दिली आहे, म्हणजे सिद्धरामैया निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाहीत, याची खात्रीच काँग्रेसच्या नेत्यांना आहे किंवा होती असे म्हणावे लागेल. अडीच वर्षांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ हा सिद्धरामैया यांना केवळ बक्षीस म्हणून दिला होता का? मुख्यमंत्र्यांचे वय हा काही मुद्दा निवडणुकीत फार महत्त्वाचा असतो असे नाही, बिहारमध्ये नितीशकुमार हेसुद्धा तसे वय झालेलेच होते. तरीसुद्धा त्यांच्या नेतृत्वावर निवडणुका लढविण्यात आल्या आणि त्यांनी जिंकून दाखवल्या! त्यामुळे सिद्धरामैया यांचे नेतृत्व आणि 'कर्तृत्व' कमी पडले म्हणून त्यांना हटविण्यात आले असे म्हणणे वावगे ठरू नये!

■ **अनिरुद्ध बर्वे,** कल्याण

मानसिक आधार गरजेचा

'फेरपरीक्षेचा नीट फास' (लोकसत्ता- ५ जून) हे वृत्त वाचले. नीट पेपरफुटीच्या घटनेनंतर फेरपरीक्षेचे सुकाणू पंतप्रधान कार्यालयाने हाती घेतले आहे. परंतु केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्याची धडाडी मोदी सरकार दाखवू शकलेले नाही. केंद्राच्या राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध धोरणानुसार 'मनोदर्पण' उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 'उम्मीद' या नावाने काही मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करण्यात आली आहेत. हा उपक्रम देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचणे गरजेचे आहे. सध्याच्या स्पर्धात्मक वातावरणात खासगी शिकवणी केंद्रे मोठे शुल्क आकारून मोठी आश्वासने देतात. पण आपण पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही असे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येते तेव्हा अनेक विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक प्रक्रिया ही आव्हानात्मक न वाटता मैत्रीपूर्ण वाटणे गरजेचे आहे.

■ **बाळकृष्ण शिंदे,** पुणे

वाघांच्या स्थलांतरातील यशापयश आणि आव्हाने?

विशेष विश्लेषण

राखी चव्हाण
rakhi.chavhan@expressindia.com

> **वाघांचे स्थलांतर हा त्यांच्या अस्तित्वाशी आणि संवर्धनाशी निगडित असलेला महत्त्वाचा नैसर्गिक तसेच व्यवस्थापकीय मुद्दा आहे. नैसर्गिक तसेच कृत्रिम स्थलांतरणाच्या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने असली तरीही अलीकडच्या काळात त्यात यशही मिळाले आहे.**

वाघांचे स्थलांतर म्हणजे नेमके काय?

नव्या अधिवासाच्या, जोडीदाराच्या तसेच अन्नाच्या शोधात वाघ स्थलांतर करतात. त्यांचे हे स्थलांतर नैसर्गिक स्थलांतर असून त्याचा मार्ग ठरलेला असतो. दुसरा प्रकार म्हणजे वाघाचे कृत्रिम स्थलांतरण. हे राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्यीयदेखील असते. मानव-वाघ संघर्षाच्या स्थितीत वाघ एका वनक्षेत्रातून दुसऱ्या वनक्षेत्रात जाणे हे कृत्रिम स्थलांतर आहे. एखाद्या वनक्षेत्रात केवळ वाघ असतील तर त्या ठिकाणी वाघीण स्थलांतरित केली जाते. महाराष्ट्रात या नैसर्गिक तसेच कृत्रिम स्थलांतराची अनेक उदाहरणे आहेत. प्रामुख्याने चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या अधिक असल्यामुळे परिणामी मानव-वाघ संघर्ष अधिक असल्यामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून राज्यातीलच नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासह ओडिशातही वाघ कृत्रिमरीत्या स्थलांतरित करण्यात आले आहेत.

वाघांच्या स्थलांतरणात कोणती आव्हाने?

वाघांचे नैसर्गिक स्थलांतर सुलभ मानले जाते, पण त्यात जेवढी आव्हाने आहेत, तेवढीच कृत्रिम स्थलांतरणात देखील आहेत. नैसर्गिक स्थलांतर करताना वाघ नदी, नाले, कालवे, रस्ते, रेल्वे मार्ग ओलांडतो. यादरम्यान त्याच्या अपघाती मृत्यूचा धोका मोठ्या प्रमाणात असतो. बऱ्याचदा तो गावांच्या वेशीवरून, वेशीवरील शेतातून जातो. अशा वेळी मानव-वाघ संघर्षही निर्माण होतो. कृत्रिम स्थलांतरात मात्र वाघांसाठी तो परिसर पूर्णपणे नवीन असतो. त्याच्या मूळ अधिवासाप्रमाणेच नवीन अधिवासाचेही व्यवस्थापन केले तरीही वाघ त्या ठिकाणी जुळवून घेतीलच असे नाही. अशा वेळी त्याच्या नैसर्गिक वागणुकीत बदल होऊ शकतो. त्यामुळे कृत्रिम स्थलांतर करताना त्यातील आव्हानांचा गांभीर्याने अभ्यास होणे आवश्यक मानले जाते.

वाघांच्या स्थलांतराचे यश कसे मोजता येईल?

वाघांच्या नैसर्गिक स्थलांतराचे यश मोजता येणार नाही, पण कृत्रिम स्थलांतरणाचे यश मोजता येते. महाराष्ट्रातील पेंच तसेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघिणींचे स्थलांतर करण्यात आले. ताडोबा आणि पेंचच्या तुलनेत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे भौगोलिक वनक्षेत्र पूर्णपणे वेगळे असल्याने या कृत्रिम स्थलांतरणाबाबत अनेक शंका होत्या. मात्र, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील तत्कालीन वनाधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे वेगळ्या असलेल्या भौगोलिक वनक्षेत्रातील या स्थलांतरणासाठी खूप चांगले काम केले. परिणामी विदर्भातून सोडलेल्या वाघिणी आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात चांगल्याच स्थिरावल्या आहेत. तर काही वर्षांपूर्वी ओडिशात सोडलेल्या दोन वाघिणीदेखील तिथे स्थिरावल्या आहेत. त्यातील एका वाघिणीने काही दिवसांपूर्वीच चार बछड्यांना जन्म दिला.

स्थलांतर करण्यासाठी योग्य काळ कोणता?

नैसर्गिक स्थलांतर करताना वाघ योग्य ती काळजी घेत असतो. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील 'वॉकर' या नावाने प्रसिद्ध असलेला वाघ तीन हजारांहून अधिक किलोमीटर फिरून आणि यादरम्यान इतर राज्यात जाऊनही पुन्हा जुन्याच ठिकाणी परतला आहे. मात्र, कृत्रिम स्थलांतर करताना अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. प्रामुख्याने लांब अंतरावर स्थलांतर करताना वाघच नाही तर सर्वच वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत वाहतुकीदरम्यान ऋतू आणि इतर बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. या वाहतुकीदरम्यान वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण ४० टक्के आहे. हिवाळा किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा काळ हा वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतरणासाठी योग्य मानला जातो.

स्थलांतरणात व्याघ्रमार्गिका किती महत्त्वाच्या?

वाघांच्या नैसर्गिक स्थलांतरणासाठी व्याघ्रमार्गिका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या अखंड राहिल्यास वाघांचे जनुकीय वैविध्य टिकून राहते आणि एकाच भागातील रक्तसंबंधांमुळे होणाऱ्या प्रजननाच्या समस्या कमी होतात. मात्र, रस्ते, रेल्वे मार्ग, खाणकाम, औद्योगिक प्रकल्प आणि मानवी वसाहतींमुळे या मार्गिका खंडित होत आहेत. परिणामी वाघांना मानवी वस्त्यांमधून मार्ग काढावा लागतो आणि मानव-वाघ संघर्षाची शक्यता वाढते. त्यामुळे केवळ व्याघ्र प्रकल्पांचे संरक्षण पुरेसे नसून त्यांना जोडणाऱ्या मार्गिकांचे संवर्धनदेखील तितकेच आवश्यक मानले जाते. वारंवार स्थलांतरणाऐवजी वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे जतन आणि विस्तार हे अधिक प्रभावी संवर्धन धोरण मानले जाते.

संक्षिप्त

उमेदवारी अर्ज मागे घेणाऱ्या दोघांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी

साहेबराव कांबळे

शैलेश अग्रवाल

मुंबई : विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी पक्षाला अंधारात ठेवून परस्पर उमेदवारी अर्ज मागे घेणाऱ्या दोन उमेदवारांवर शुक्रवारी काँग्रेसने हकालपट्टीची कारवाई केली. यवतमाळ विधान परिषद मतदारसंघातील उमेदवार साहेबराव कांबळे आणि चंद्रपूर-गडचिरोली-वर्धा मतदारसंघातील उमेदवार शैलेश अग्रवाल यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. या दोन मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराच्या माघारीमुळे महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. काँग्रेस उमेदवारांच्या अर्ज माघारीच्या कृत्याची गंभीर दखल घेत प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही कारवाई केली. पक्षाने कांबळे आणि अग्रवाल या दोघांचे सदस्यत्वही रद्द केले आहे.

मत्स्य उत्पादन निर्यातीवर भर

पाच वर्षांत निर्यात ३० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट : पीयूष गोयल

कल्पेश भोईर, लोकसत्ता

सध्या देशातील मत्स्यनिर्यातीपैकी केवळ १२ टक्के निर्यात ही प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची होते. या क्षेत्रात वाढीला मोठा वाव असून उद्योगांनी याकडे संधी म्हणून पाहावे, याशिवाय गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियेवर भर द्यावा.
- चिराग पासवान, केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री

निर्यात वाढवून संभाव्य नुकसानाची भरपाई : गोयल

विशाखापट्टणम : भारताच्या सागरी मत्स्य उत्पादन निर्यातीला गती देण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. पुढील पाच वर्षांत मत्स्योत्पादन निर्यातीचे मूल्य सध्याच्या ८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून थेट ३० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

सागरी उत्पादनाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय व आंध्र प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने ५ आणि ६ जून २०२६ रोजी विशाखापट्टणम येथे राष्ट्रीय सागरी अन्न परिषद कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह, नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरपु राममोहन नायडू आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांच्यासह देशातील दिग्गज अधिकारी व उद्योग क्षेत्रातील भागधारक उपस्थित होते.

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी २१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगातील प्रत्येक देशात भारतीय मासे पोहोचविण्याचा निर्धार गोयल यांनी केला. भारताची एकूण सागरी उत्पादन निर्यात २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ७३,८९०.४६ कोटी रुपये (८.४५ अब्ज डॉलर) इतकी झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील मत्स्योत्पादनातील सद्यस्थिती आणि निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्राला निर्यातीची संधी

महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन होते. मात्र राज्यांतर्गत अमेरिकेने ५५.८ टक्के इतके आयात शुल्क लावले असले, तरी भारतीय निर्यातदारांनी युरोपियन संघ, जपान, चीन आणि आग्नेय आशियातील निर्यात वाढवून संभाव्य नुकसान यशस्वीपणे भरून काढले असल्याची माहिती मंत्री गोयल यांनी या परिषदेत दिली. भारताने गेल्या साडेतीन वर्षांत विकसित देशांबरोबर ९ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतिम केले. यामुळे भारतीय मत्स्योत्पादन क्षेत्राला जगातील मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, मागणीसाठी माशांचा पुरवठा केला जातो. जर निर्यातीकडे लक्ष दिल्यास महाराष्ट्रासाठी ही मोठी संधी ठरू शकते, असे मत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले आहे.

आंध्र प्रदेशात 'राष्ट्रीय मत्स्य मंडळ' कार्यालय

देशातील सर्वाधिक मासे उत्पादन व त्याची निर्यात करणारे राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशात लवकरच 'राष्ट्रीय मत्स्य मंडळा'चे प्रादेशिक कार्यालय सुरू केले जाणार असल्याचे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी सांगितले. तर या केंद्रासाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केली.

मालवाहतूक विमानतळाची उभारणी

सरकार देशातील विमानतळांची संख्या ३५० हून अधिक करण्याच्या दिशेने काम करत असून, अधिक मालवाहतूक विमानतळ उभारण्याची योजना आखली जाणार असल्याचे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांनी सांगितले. असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर असलेल्या अंतर्गत राज्यांमधून निर्यात वाढवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी सांगितले.

मिसिंग लिंकवर 'विंड शिल्ड'

वादळ-वाऱ्यापासून वाहनांची सुरक्षा करण्यासाठी निर्णय

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'कनेक्टिंग लिंक'वरून (मिसिंग लिंक) मुंबई-पुणे प्रवासाचा कालावधी ३० मिनिटांनी कमी झाला आहे. आता येथील प्रवास आणखी सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) येथील 'केबल स्टेड' पुलावर वादळ-वाऱ्यापासून संरक्षण करणाऱ्या 'विंड शिल्ड' बसवण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरच हे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.

मिसिंग लिंकवर एका १८२ ते १८५ मीटर उंच केबल स्टेड पुलाचा समावेश असून हा पूल देशातील सर्वात उंच केबल स्टेड पूल ठरला आहे. या पुलाची उभारणी दरीखोऱ्यात करण्यात आली आहे. या ठिकाणी प्रचंड वेगाने वारे वाहतात. पुलाचे काम करताना एमएसआरडीसी आणि कंत्राटदारांना अनेक आव्हानात्मक गोष्टींचा सामना करावा लागला होता. पावसाळ्यात येथे वाऱ्याचा वेग प्रचंड असतो. त्यामुळे वादळ-वाऱ्यात केबल स्टेड पुलावरून वाहने धावताना धोका उद्भवू शकतो. त्यातच चक्रीवादळाचीही भीती असते. या सर्व बाबींचा विचार करून 'एमएसआरडीसी'ने केबल स्टेड पुलावर विंड शिल्ड उभारण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती 'एमएसआरडीसी'चे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी 'लोकसत्ता'ला दिली.

केबल स्टेड पुलाच्या दोन्ही बाजूंनी 'विंड शिल्ड' बसविण्याच्या कामास नुकतीच कंत्राटदाराने सुरुवात केली. येत्या १०-१२ दिवसांत हे काम पूर्ण करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले. केबल स्टेड पूल ६५० मीटर लांबीचा असला तरी पुलावरील पायलॉनच्या भागात अर्थात ४० मीटर लांबीपर्यंतच विंड शिल्ड बसविण्यात येणार आहेत.

'विंड शिल्ड' म्हणजे काय?

- विंड शिल्ड म्हणजे एक प्रकारची संरक्षक भिंत. ही प्रामुख्याने दरी किंवा खोल भागात असणाऱ्या केबल स्टेड पुलावर बसविण्यात येते.
- विंड शिल्ड वाऱ्याचा वेग खंडित करून त्याचा दाब कमी करतात. तर पुलांवरून जाणाऱ्या भरधाव गाड्यांना जोराच्या वादळी वाऱ्यांमुळे वा चक्रीवादळामुळे होणाऱ्या अपघातांपासून वाचवते. वाऱ्याचा थेट मारा कमी झाल्यामुळे चालकांचे गाडीवरील नियंत्रण अबाधित राहते.

'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' स्थापण्याचा निर्णय

संस्थेला तीन हजार कोटींचा निधी

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : येत्या चार वर्षांत म्हणजेच २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'ची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संस्थेला ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असून, विश्वासार्ह जागतिक भागीदार म्हणूनही उदयास आला आहे. तसेच नवोन्मेष, उत्पादन क्षेत्र आणि शाश्वत विकासाला चालना देणारा देश म्हणूनही भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. देशाच्या या वाटचालीची आर्थिक शक्ती म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. राज्याचा राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांचा वाटा आहे, तसेच देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात १५.४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. राज्याने परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यात देशात आघाडी राखली असून, गेल्या दशकात देशातील एकूण 'एफडीआय'पैकी ३१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा महाराष्ट्राचा राहिला आहे.

महाराष्ट्राने आपले नेतृत्व स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या अधिनस्त कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत जागतिक दर्जाची गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधिन होता. त्यानुसार 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' ही गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' ही संस्था महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अधिनियम, २०२३ आणि नियम २०२५ अंतर्गत गुंतवणूक आकर्षण व सुलभीकरणासाठी कार्य करेल.

मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार; तीन ठार

पीटीआय, इम्फाळ

मणिपूरमधील हिंसाचार पुन्हा उफाळून आला असून कांगपोकपी जिल्ह्यातील एका गावावर सशस्त्र हल्लेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात एका महिलेसह तिघांचा मृत्यू झाला. हल्लेखोरांनी अनेक मिनिटे गोळीबार केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, तर किमान सात घरे आगीत जळून खाक झाली.

शुक्रवारी पहाटे सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास सैतू-गामफाझोल उपविभागातील लोइबोल खुल्लेन गावावर सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला चढवला. प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये झालेल्या गोळीबारामुळे ग्रामस्थांनी जीव वाचवण्यासाठी जंगलांमध्ये आश्रय घेतला. यात लेटखोंगाम हाओकिप, टिनमेरी हाओकिप आणि जांगमिनलाल हाओकिप यांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री वाय. खेमचंद सिंह आणि उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन यांनी हल्ल्याचा निषेध केला आहे. निरपराध नागरिकांची हत्या आणि घरे जाळण्याचा प्रकार अत्यंत दुर्दैव असल्याचे सांगत दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

महाविकास आघाडीतच बिघाडी : एकनाथ शिंदे

लोकसत्ता प्रतिनिधी

ठाणे : विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याची टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी ठाण्यात केली. राज्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी माघार घेतली. तर महायुती मजबुतीने यशाकडे वाटचाल करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने महाराष्ट्राला पाठबळ देण्याचे काम करत असल्याचेही शिंदे म्हणाले.

ठाणे-पालघर स्थानिक प्राधिकारी निवडणुकीत शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार रवींद्र फाटक बिनविरोध निवडून आल्यानंतर शुक्रवारी टेंभीनाका येथील आनंद आश्रमात जल्लोष करण्यात आला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. त्यानंतर शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या निवडणुकीत शिवसेनेचे दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन आणि भाजपचे दोन असे सहा बिनविरोध उमेदवार निवडून आले आहेत. ही पुढच्या विजयाची नांदी असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

महायुतीचे सरकार निवडून आले तेव्हापासून या राज्यात विकासाची घोडदौड सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्राला पाठबळ देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीचा आम्ही निर्णय घेतला, विविध विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे काम महायुती सरकार करत आहे, असे शिंदे म्हणाले.

देश विकासाच्या की आर्थिक मंदीच्या वळणावर? : जयंत पाटील

लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

'आर्थिक मंदीच्या संकटाकडे वेळीच लक्ष द्या'

महागाई बुलेट ट्रेनच्या वेगाने वाढत असून, लोकांचे उत्पन्नही त्याच वेगाने घसरत आहे. रिझर्व्ह बँकेला काही प्रमाणात का होईना आकडेवारी द्यावीच लागत आहे. सर्व गोष्टींचे सोंग करता येते, परंतु पैशाचे सोंग करता येत नाही. केंद्राने कोणतेही सोंग न करता देशावरील मंदीच्या संकटाकडे वेळीच लक्ष द्यावे, अन्यथा सर्वसामान्य उद्ध्वस्त होतील, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकार अमृतकाळाची जाहिरात करीत आहे, परंतु आर्थिक परिस्थिती पाहता देश विकासाच्या मार्गावर आहे की, आर्थिक मंदीच्या वळणावर, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारकडून अमृतकाळाच्या जाहिराती सुरू आहेत, पण अर्थव्यवस्थेची स्थिती वेगळीच आहे. मे महिन्यात एप्रिलच्या तुलनेत 'जीएसटी' संकलनात २० टक्क्यांनी म्हणजे जवळपास ५० हजार कोटींची मोठी घट झाली आहे. 'आरबीआय'ने दिलेल्या माहितीनुसार महागाई दर ४.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांवर गेला आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांवर घसरण्याचा अंदाज आहे.

जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा विकासाचा वेग कमी होतो आणि सामान्य नागरिकाची क्रयशक्ती घटते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची खरी अवस्था सरकारी जाहिरातींमधून नाही तर बाजारातून दिसते. देशातील तरुण रोजगारासाठी झगडत आहेत, उद्योग गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगत आहेत. सामान्य कुटुंबांचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे देश विकासाच्या मार्गावर आहे की, आर्थिक मंदीच्या धोकादायक वळणावर, असा प्रश्नही पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

चूकभूल

संपादकीय पानावरील 'विश्लेषण'मधील 'निकाल काय?' या तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात वेश्याव्यवसायाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशाची तारीख '२९ मे २०१६' अशी नजरचुकीने छापली गेली आहे. वास्तविक हा निकाल २९ मे २०२६ रोजी देण्यात आलेला आहे.

'व्यक्तिवेध' सदरात 'एडगर मॉरिन' यांच्या नावाचा मूळ फ्रेंच उच्चार 'मोरँ' असा लिहिल्यास तो बिनचूक ठरला असता, असे फ्रेंच जाणणाऱ्या वाचकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. अंकात इंग्रजी स्पेलिंगप्रमाणे होणाऱ्या उच्चारानुसार लिहिलेल्या नावाऐवजी 'मोरँ' असे वाचावे.

लक्ष्य ॲकॅडमीतर्फे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबिर

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : लक्ष्य ॲकॅडमीतर्फे दादर येथील स्वाती मनोर सोसायटीमध्ये शनिवार, ६ जून रोजी दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्टाफ सिलेक्शन, बँक पीओ, आरबीआय आदी परीक्षांबाबत मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच, रविवार, ७ जून रोजी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी आदी पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेची तयारी कशी करावी, यासाठी 'चला घडवू या आयएएस, आयपीएस अधिकारी' या शिबिराच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. यासाठी २०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

दहावी-बारावीनंतर कोणती शाखा निवडावी, कोणते करिअर निवडावे, महाविद्यालयीन जीवनापासूनच आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, एमपीएससी, आरबीआय, बँक पीओ आदी परीक्षांची तयारी कशी करावी? याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या शिबिरात संचालक अजित पडवळ, प्राध्यापक वसिम खान यांच्यासह स्पर्धा परीक्षेतील विविध मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. यूपीएससी, एमपीएससीतील पूर्व परीक्षा, बहुपर्यायी प्रश्न कसे सोडवावे, मुख्यपरीक्षेतील वर्णनात्मक पेपर कसे लिहावे, चालू घडामोडीचा अभ्यास कसा करावा, निबंधाची तयारी कशी करावी, मुलाखतीची तयारी कशी करावी याबाबत विद्यार्थी व पालकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. हे शिबिर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही उपयुक्त ठरेल. नाव नोंदणी व अधिक माहितीसाठी मोबाइल क्रमांक ९८२०९७१३४५, ९६१९०७१३४५ वर संपर्क साधावा.

'देशी'च्या विक्री केंद्रांअभावी हातभट्टीकडे कल

अशोक अडसूळ, लोकसत्ता

गावठी दारूविरोधात मोहीम, तीन हजार गुन्हे नोंद

अंकुश ठेवण्याचे आव्हान

राज्यात ३० हजार गावे आहेत. गाव तेथे हातभट्टी विक्री केंद्र असून उत्पादन शुल्क विभागाचे गणवेशधारी जवानांचे ३ हजारांचे बळ आहे. त्यामुळे हातभट्ट्यांवर अंकुश कसा ठेवायचा ? याचे या विभागासमोर आव्हान आहे.

उत्पादन शुल्क विभाग दरवर्षी ४० ते ४५ हजाराच्या आसपास गुन्हे दाखल करतो व तितकेच आरोपी पकडलेही जातात. पुणे विषारी दारू दुर्घटनेनंतर राज्यव्यापी विशेष अभियान राबवले जात आहे.
- प्रसाद सुर्वे, सहआयुक्त, दक्षता व अंमलबजावणी, उत्पादन शुल्क विभाग

मुंबई : पुणे विषारी दारू दुर्घटनेनंतर उत्पादन शुल्क विभागाने (हातभट्टी गावठी) दारू विरोधात राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. एका आठवड्यात ३,३१२ गुन्हे नोंदले असून २,०५७ लोकांना अटक केली आहे. स्वस्त देशी दारूची विक्री केंद्रे मर्यादित असल्याने ग्राहक हातभट्टीकडे वळतो. परिणामी, उत्पादन शुल्क विभागासमोर वाढत्या हातभट्ट्यांवरील कारवाईचे आव्हान आहे.

राज्यात देशी दारूचा खप पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशी स्वस्तही आहे, मात्र १९७३ पासून देशी दारू विक्रीचे परवाने बंद आहेत. १३ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात ४,३३४ देशी दारू विक्री केंद्रे आहेत. परिणामी, स्वस्त मद्याच्या शोधात ग्राहक हातभट्टीला जवळ करतो. उन्हाळ्यात ओढे आटल्याने हातभट्टीची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे स्वस्त मेथेनॉल मिसळून गरज भागवण्याकडे कल वाढतो, त्यातून विषारी दारू दुर्घटना घडतात. पुणे प्रकरणात नाचक्की झाल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने हातभट्टीविरोधात राज्यव्यापी मोहीम उघडली. यामध्ये ३,३१२ गुन्हे नोंद केले असून २,०५७ लोकांना अटक केली. १०७ वाहने, ९ कोटी ११ लाखांचा मुद्देमाल आणि ७४ हजार लिटर हातभट्टी जप्त केली आहे. सर्वाधिक गुन्हे कोकण, पुणे आणि नागपूर विभागात नोंदले आहेत.

दिनदर्शिका

शनिवार, ६ जून २०२६
भारतीय सौर १६ ज्येष्ठ शके १९४८
मिती अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष षष्ठी
उत्तर रात्री ०२ : ४२ पर्यंत.
नक्षत्र : श्रवण ०६ : ०३ पर्यंत.
चंद्र : मकर १९ : ०४ पर्यंत.
सूर्योदय : ०६ : ०२
सूर्यास्त : १९ : १३

- **मेष :** नोकरीत बढती मिळेल.
- **वृषभ :** शुभ संकेत मिळेल.
- **मिथुन :** स्वतःवर नियंत्रण ठेवा.
- **कर्क :** नवीन संधी मिळेल.
- **सिंह :** बेकायदेशीर गोष्टी टाळा.
- **कन्या :** प्रशंसा होईल.
- **तूळ :** भावंडांची भेट होईल.
- **वृश्चिक :** शेजाऱ्यांना मदत कराल.
- **धनू :** खरेदी कराल.
- **मकर :** विवाहाचे प्रस्ताव येतील.
- **कुंभ :** आरोग्याची काळजी घ्या.
- **मीन :** आनंदी दिवस.

शुभ राशी : मेष , धनू.

शब्दकोडे- ६

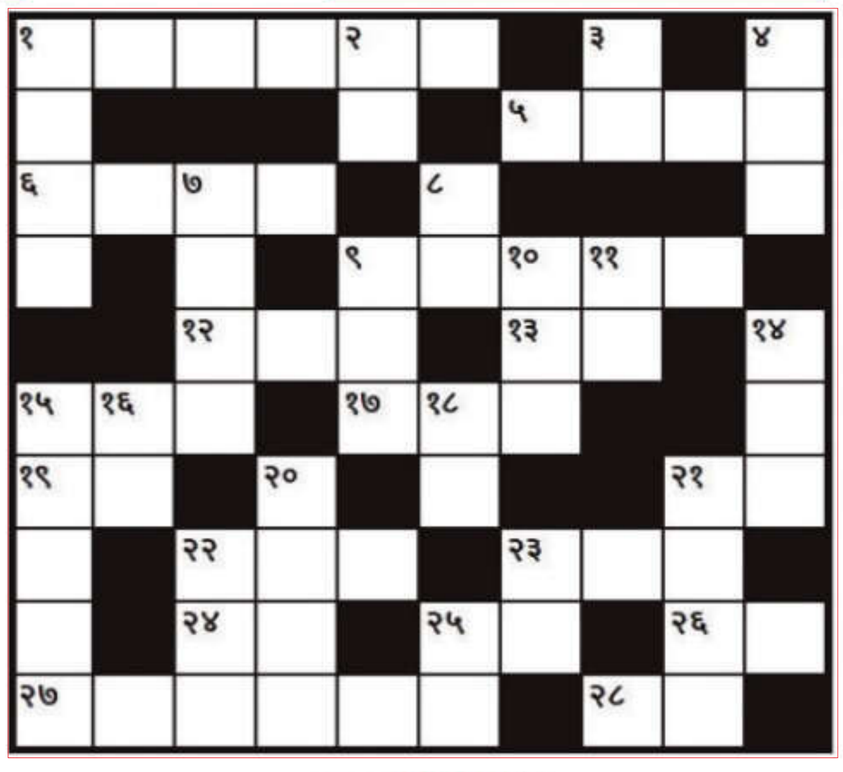

आडवे शब्द :
(१) वीजकपात (५) लबाड कोल्ह्याला जशास तसे अशी अद्दल घडवणारा पक्षी (६) निरर्थक, जे केले असता फायदा होत नाही असे (९) नीटनेटका, व्यवस्थित (१२) विशिष्ट आकाराचे धातूचे भांडे, गडू (१३) युद्ध, लढाई (१५) सकाळ (१७) वात जळून काळा झालेला भाग (१९) दिराची पत्नी (२१) बोकड (२२) बाणेदार, आपल्या शब्दावर ठाम राहणारा (२३) परंपरा, प्रथा (२४) याचा हिंदी अर्थ शहद (२५) XX घालणे म्हणजे नियंत्रण ठेवणे, निर्बंध घालणे (२६) खर्च (२७)काल्पनिक (२८) हैराण, त्रासलेला

उभे शब्द :
(१) नशीबवान (२) जुन्या काळातील वजनाचे एक माप (३) झाडाभोवती घातलेला ओटा, कट्टा (४) वटवट करणारा (७) फसवणूक, फजिती (८) नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन या इंग्रजी नावातील आद्याक्षरांवरून रूढ झालेली संज्ञा. (९) व्याप्ती, पल्ला (१०) XXX वैजनाथ मंदिर हे बीड जिल्ह्यातील ज्योतिर्लिंग आहे. (११) थकवा (१४) शिकारीचे जनावर (१५) दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी भारताचा हा दिन साजरा केला जातो. (१६) बंधू (१८) पाणी (२०)उपासक, भक्त (२१) इकडेतिकडे विखुरलेले, अव्यवस्थित (२२) पद्म, पंकज (२३) मोठा दगड, पाषाण (२५) बाहेरच्या उलट

- मनाली रानडे

सुडोकू - ६

१		७			९			
				६		१	८	
३	६		२			९	१	
७			८		६			५
	४	८			३		६	७
	१	२		८				
			५			४		६

सुडोकू - ५ चे उत्तर

६	२	३	८	४	७	१	५	१
४	१	१	३	५	६	७	२	८
५	७	८	२	१	१	६	३	४
७	५	१	१	३	८	४	६	२
२	३	६	७	१	४	५	८	१
१	८	४	६	२	५	३	१	७
१	१	५	४	६	२	८	७	३
३	६	७	१	८	१	२	४	५
८	४	२	५	७	३	१	१	६

शब्दकोडे - ५ चे उत्तर

सा	ब	र	म	ती	■	न	ज	रा	णा
र	स	■	स	ज	ग	■	प	क्ष	■
या	■	मा	त	■	ज	ग	■	स	म
न	फा	■	त	मा	■	त	■	■	हि
■	र	ग	■	न	ग	■	या	त	ना
व्या	क	र	ण	■	य	म	क	■	■
■	त	ळ	■	अ	■	ठ	■	ग	या
अ	■	■	यो	ज	ना	■	म	ढा	र
क्ष	त्रि	य	■	ग	रा	■	■	■	स
र	■	म	■	र	ज	नी	गं	धा	■

आर्थिक चिंता का समय

विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा शुक्रवार को एक साथ किए गए उपाय सराहनीय हैं। इन उपायों से तीन लाभ होंगे- विदेशी निवेश का पलायन थमेगा, स्थानीय ऋण बाजार को मजबूती मिलेगी और रुपये की स्थिति सुधरेगी। वैश्विक अनिश्चितता के इस समय में रिजर्व बैंक को ऐसे तमाम उपाय करने ही चाहिए, जिनसे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ध्यान देने की बात है, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने विदेशी निवेश के लिए अपने रास्तों को उस तरह से नहीं खोला है, जैसे दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश कर रहे हैं। तथ्य है, इन छोटे देशों के शेयर बाजार का मूल्य भारतीय शेयर बाजार से ज्यादा हो गया है। भारतीय शेयर बाजार का मूल्य दो साल पहले दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने लगा था, मगर अब गिरकर सातवें स्थान पर आ गया है। सबसे मूल्यवान अमेरिकी शेयर बाजार 80 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, तो 16 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीनी शेयर बाजार दूसरे स्थान पर है, जबकि भारतीय शेयर बाजार का मूल्य पांच ट्रिलियन से भी नीचे आ गया है। ऐसे में, शेयर बाजार में निवेश की गिरावट को रोकना बहुत जरूरी हो गया है।

विदेशी निवेशकों की ताकत को बढ़ाया गया है। उन्हें ज्यादा कर सुविधा के साथ ही शेयर बाजार में अधिक पहुंच की सुविधा दी गई है। सॉवरेन बॉन्ड में निवेश पर कर छूट, विदेशी निवेशकों के लिए निवेश प्रतिबंधों में ढील और विदेशियों के लिए शेयर निवेश सीमा में वृद्धि से निश्चित ही भारतीय निवेश में बढ़ोतरी होगी। इन उपायों से विदेशी निवेशकों का फायदा बढ़ेगा, पर यह जोखिम भारत को उठाना ही पड़ेगा। हमें व्यापकता में सोचना होगा कि हम अपने देश में निवेश बढ़ाने के लिए क्या ठोस उपाय कर रहे हैं? क्या हम भारत में व्यापार को और आसान बना सकते हैं? क्या हम अपनी पूंजी को विदेश जाने से रोक सकते हैं? वास्तव में, देश के विकास को तेज करने के लिए ऐसा करना ही होगा। अच्छी बात है, शुक्रवार को रुपये का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पचास पैसे बढ़ा है। किसी भी स्थिति में कोशिश होनी चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर रहे। आज एक बड़ी आशंका है कि एक डॉलर की कीमत 100 रुपये से ज्यादा न हो जाए। पेट्रोल की कीमत तो पहले ही 100 रुपये के पार चली गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा घोषित ताजा मौद्रिक व आर्थिक उपाय दीर्घकालिक विकास को बल देने के साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ाएंगे।

अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकना प्राथमिकता बने। वैश्विक गिरावट हमारे लिए बहाना न बने, तो ही अच्छा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसकी मौद्रिक नीतियां पिछलग्गू न बनें, यह सुनिश्चित करना होगा। निस्संदेह, घोषित उपाय दीर्घकालिक विकास को बल देने के साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएंगे। रिजर्व बैंक का एक और उपाय खास ध्यान खींच रहा है। अब निर्यातकों को अपनी विदेशी मुद्रा आय को जल्द से जल्द भारत लाना होगा। भारत के हिस्से की विदेशी मुद्रा और कमाई भारत में ही रहे, इसके उपाय बढ़ाने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने उचित ही बैंक दर या रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। जीडीपी विकास दर 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दी गई है, तो खुदरा महंगाई दर अनुमान को 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया गया है। भारत अभी भी संभल या संभाल सकता है। विकास की रफ्तार में आ रही अड़चनों को दूर करना होगा। यह खुशखबरी है कि स्वर्ण के भाव में एक प्रतिशत और चांदी के भाव में दो प्रतिशत की कमी देखी गई है। चुनौतियों के बीच जहां भी सुधार के सुखद संकेत दिख रहे हैं, उनसे प्रेरित होने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 06 जून, 1951

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

प्रजातंत्र में विरोधी दल का महत्व उपेक्षणीय नहीं, किन्तु भारत में विरोधी प्रवृत्तियों का आरंभ जिस रूप में हुआ है वह इस महान देश की तत्वदर्शी एवं समन्वयकारी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ेगा। पश्चिम से आई हुई 'विरोध के लिये विरोध' अथवा 'स्वार्थ के लिये विरोध' की प्रवृत्ति सद्य-स्थापित भारत-गणराज्य के भविष्य के लिये शुभ नहीं हो सकती।

गत कुछ दिनों में संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक पर संसद के अंदर और बाहर बहुत-कुछ इसी प्रकार का विरोध दिखलाई पड़ रहा है। यद्यपि अब विधेयक पर वैधानिक रूप से अंतिम पर्दा पड़ चुका है, तथापि कुछ क्षेत्रों में उसकी चर्चा समाप्त नहीं हुई। विरोधियों में सर्वाधिक उग्र कुछ पत्र और पत्रकार हैं, जो महसूस करते हैं कि संशोधन से उनकी स्वतंत्रता पर आघात हुआ है। एक पत्र ने तो यहां तक कहा है कि 'पत्रों के पास सरकार से कम शक्तिशाली शस्त्र नहीं है। उन्हें भाषण तथा अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए अपने वैध तथा योग्य शस्त्रागारों को खोल लेना चाहिए। कुछ अन्य पत्रों ने नेहरूजी की स्पष्ट किन्तु कटु उक्तियों का ऐसे शब्दों में स्मरण किया है, जिन से मानसिक संतुलन का परिचय नहीं मिलता। शनिवार को संशोधन संबंधी वाद-विवाद का उत्तर देते हुए नेहरूजी ने कहा था : 'डा. मुखर्जी ने जिस प्रकार की आलोचनाएं की हैं, वे अपवाद फैलाने वाली हैं, क्योंकि सत्य से उनका कोई संबंध नहीं है। हमसे बार-बार कहा गया है कि आप पत्रों की स्वतंत्रता का दमन कर रहे हैं।' जो व्यक्ति या पत्र ऐसा कहता है वह झूठ बोलता है और जानता है कि वह झूठ बोल रहा है।'

जहां तक पत्रों की स्वतंत्रता का प्रश्न है, श्री जोकीम अलवा के ये शब्द, जो उन्होंने शनिवार की बहस के दौरान संसद में कहे थे, महत्वपूर्ण हैं: '1946 के पूर्व, जबकि भारतीय पत्रों पर नाना प्रकार के प्रतिबन्ध थे और उन्हें भयानक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, भारतीय पत्रों का सुनहरा समय था। उस समय पत्रकार देशभक्ति से प्रेरित होकर 'देश का मान बढ़ाने के लिए लिखते थे, रुपये के लिए नहीं। किन्तु 1946 के पश्चात् जबकि 'अखबारी नवाबों' ने पत्रों पर अधिकार करना आरंभ किया, पत्रों ने सोने का सच्चा रंग-पीला- ग्रहण कर लिया और वे रुपया-आना-पाई के पत्र बन गये।'

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सही करार दिया है। इसके बाद भी अनेक राजनीतिक दलों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इस कवायद पर लगातार टीका-टिप्पणी की जा रही है। क्या उनका यह व्यवहार उचित है? क्या इससे देश की सांविधानिक संस्थाओं की साख को चोट नहीं पहुंचती? प्रस्तुत है, इस विषय पर दो नजरिया :

एसआईआर की प्रक्रिया पर बेबुनियाद हंगामा

यहां स्कैन करें

नवनीत सहगल | पूर्व चेयरमैन, प्रसार भारती

- बकौल सुप्रीम कोर्ट, यह काम निर्वाचन आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी है।
- चिंताजनक है कि पूर्व चुनाव आयुक्त भी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे?
- संस्थाओं पर बार-बार हमले से दुनिया भर में देश की साख पर असर होता है।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र की प्राणवायु उसके नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। यह विश्वास इस बात पर टिका होता है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य समान है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष। अवैध व फर्जी वोटों की उपस्थिति वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों का हनन करती है। ऐसे में, जब भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की इन विसंगतियों को दूर करने के लिए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) जैसा व्यापक अभियान चलाता है, तो उसके विरुद्ध होने वाला राजनीतिक शोर गंभीर सवाल खड़े करता है। मतदाता सूची को शुद्ध करना महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक शर्त है।

आजकल राजनीतिक विमर्शों में यह माहौल बनाया जा रहा है, मानो एसआईआर कोई अचानक थोपी गई, नई या लोकतंत्र विरोधी प्रक्रिया हो। तथ्य इसके विपरीत हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव आयोग नियमित रूप से यह कदम उठाता रहा है। वर्ष 2002 से 2004 के बीच देशव्यापी स्तर पर घर-घर जाकर ऐसा ही सघन सत्यापन अभियान चलाया गया था। इसके पश्चात भी जरूरत के अनुसार विभिन्न राज्यों में एसआईआर होते रहे हैं। यह आयोग की एक वैधानिक और स्थापित कार्यप्रणाली है, न कि कोई राजनीतिक हथियार। विडंबना यह है कि जो लोग मतदाता सूची की शुद्धता की मांग करते रहे हैं, वे ही कई बार दोहराव व निष्क्रिय प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते दिखाई दिए। सवाल यह है, यदि एक व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण है, तो उस गलती को सुधारना गलत कैसे हो सकता है? यदि मृत लोगों के नाम हटाना आवश्यक है, तो उस प्रक्रिया का विरोध किस तर्क पर आधारित है?

एसआईआर के विरोध में सबसे मुखर आरोप यह लगाया जाता है कि चुनाव आयोग मनमाने ढंग से लाखों मतदाताओं के नाम काट रहा है। यह आरोप भ्रामक है। किसी भी नागरिक का नाम रातोंरात या बिना सूचना के नहीं हटाया जाता। इसकी एक पारदर्शी त्रि-स्तरीय प्रक्रिया होती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि चुनाव आयोग स्वयं घर-घर नहीं जाता। जमीनी स्तर पर यह पूरा कार्य बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), तहसीलदार और राज्य सरकार के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। सत्यापन के बाद एक प्रारूप सूची सार्वजनिक की जाती है। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया है, तो उसे दावा करने और पुनः अपना नाम जुड़वाने का पूरा कानूनी अधिकार और समय दिया जाता है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना और अविश्वास पैदा करने में अंतर होता है। पिछले कुछ वर्षों में एक प्रवृत्ति देखने को मिली है, जिसमें चुनावी परिणाम अनुकूल होने पर संस्थाओं की निष्पक्षता स्वीकार कर ली जाती है और प्रतिकूल होने पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। यह प्रवृत्ति केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। ईवीएम से लेकर मतदाता सूची तक, कई विषयों पर यही रवैया देखने को मिला है।

चिंता की बात यह है कि ऐसे आरोप घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते। जब बार-बार कहा जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मतदाता सूची से छेड़छाड़ हो रही है या चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत की चुनावी प्रक्रिया पर वैश्विक नजर रहती है। ऐसे में, बिना पर्याप्त तथ्यों के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संदेह खड़ा करना देश की संस्थागत साख को प्रभावित कर सकता है।

चिंताजनक बात यह भी है कि कुछ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे पूरी प्रक्रिया को भली-भांति जानते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान समय-समय पर इस प्रक्रिया का हिस्सा भी रह चुके हैं।

अपने प्रशासनिक जीवन में कई बार चुनावी प्रक्रियाओं का हिस्सा रहने के कारण यह लेखक भली-भांति जानता है कि चुनाव आयोग किसी प्रक्रिया को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह अत्यंत व्यापक व्यवस्था है, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ऐसे में, चुनाव की किसी प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध प्रभावित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। चुनाव आयोग पर राजनीतिक दलों के आरोपों और टिप्पणियों को जागरूक नागरिक सहजता से विश्वास नहीं करता, लेकिन जब पूर्व चुनाव अधिकारी ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो वे अनजाने में खुद के बारे में बन रही उस धारणा को बल देते हैं कि उनकी टिप्पणियों के पीछे राजनीतिक झुकाव काम कर रहे हैं।

एसआईआर को लेकर चले इस पूरे विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। न्यायालय के अनुसार, मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन रखना निर्वाचन आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए एक सटीक मतदाता सूची अपरिहार्य है। यह स्पष्ट संकेत है कि मतदाता सूची को अद्यतन रखना केवल प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि एक सांविधानिक दायित्व भी है। अतः सवाल वहीं लौटता है, जहां से यह चर्चा शुरू हुई थी। यदि मतदाता सूची में मृत लोगों के नाम बने रहे, यदि एक व्यक्ति कई जगह वोटर बना रहे और यदि वर्षों तक कोई व्यापक सत्यापन न हो, तो क्या चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी? यदि इसका उत्तर 'हां' है, तो फिर उन खामियों को दूर करने की प्रक्रिया को भी निष्पक्ष दृष्टि से देखना होगा।

एसआईआर का समर्थन या विरोध करना राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन मतदाता सूची की शुद्धता का समर्थन करना लोकतांत्रिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत के करोड़ों मतदाताओं का हित इसी में है कि हर वोट वास्तविक हो और हरेक मतदाता वैध हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आयोग भी इस कवायद में कमियां मान रहा

यहां स्कैन करें

फैजान मुस्तफा | कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विवि

- निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है।
- एसआईआर में बाहर किए गए तमाम लोग मौलिक अधिकारों के हकदार।
- बिहार में इस प्रक्रिया का नुकसान गरीब महिलाओं को उठाना पड़ा है।

नागरिकता वास्तव में किसी व्यक्ति और राजनीतिक समुदाय के बीच का संबंध है, पर क्योंकि आज, नागरिकता की आधुनिक अवधारणा में 'बाहरी' लोगों को बाहर रखना महत्वपूर्ण हो गया है, इसीलिए *वसुधैव कुटुंबकम* की प्राचीन भारतीय अवधारणा नागरिकता की संकल्पना से मेल नहीं खाती। क्या नागरिकता के मुद्दे को इस प्रकार सुलझाया जाना चाहिए कि हमारे अपने ही लोग विदेशी घोषित कर दिए जाएं या आजीविका या कल्याणकारी योजनाओं से वे वंचित कर दिए जाएं? यह आज का सबसे गंभीर सवाल है।

आमने-सामने

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद कई राज्य सरकारों ने उन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करना शुरू कर दिया है, जिनके नाम एसआईआर सूची में शामिल नहीं हैं। बिहार एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह विधि सम्मत है, लेकिन नागरिकता तय करने के मामले में यह चुनावों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अदालत ने यह माना है कि निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, पर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने से पहले उसकी नागरिकता को लेकर संतुष्ट होने का इख्तियार आयोग जरूर रखता है।

हालांकि, उदार भारतीय संविधान समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व धर्म की स्वतंत्रता जैसे कुछ मौलिक अधिकार गैर-नागरिकों को भी देता है, इसलिए एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बाहर किए गए ये लाखों लोग सांविधानिक रूप से इन मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, और बने रहेंगे। अतः उनको कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करना भी संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो सकता।

फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश था, जिसने 1539 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू किया था। भारत में भी, साल 2003 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के जरिये एनपीआर का प्रस्ताव सामने आया, जिसके तहत सभी नागरिकों का पंजीकरण और उन्हें राष्ट्रीय पहचानपत्र भी जारी किए जाने थे। किंतु, दुर्भाग्य से असम में, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का काम सुप्रीम कोर्ट की सीधी देख-रेख में किया गया था, रजिस्टर-प्रकाशन के सात साल बाद भी एक भी व्यक्ति को नागरिकता कार्ड जारी नहीं किया जा सका है। यहां तक कि उन 19 लाख बदकिस्मत लोगों को भी अभी तक 'विदेशी ट्रिब्यूनल' के सामने पेश होने की सूचना नहीं दी गई है, जिन्हें इस प्रक्रिया के बाद बाहर कर दिया गया था। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने एसआईआर फैसले में अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह चार हफ्तों में एसआईआर से बाहर किए गए लोगों की नागरिकता तय करने का मामला गृह मंत्रालय को भेजे।

निस्संदेह, इस फैसले के मुताबिक, चुनाव आयोग नागरिकता का निर्धारण नहीं कर सकता, पर इस फैसले से हमने संदिग्ध या संदेहास्पद नागरिकों की एक नई श्रेणी जरूर बना दी है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह 1997 के चुनाव आयोग के विवादास्पद फैसले की तरह है, जिसमें असम में 'संदिग्ध मतदाताओं' की एक नई श्रेणी बनाई गई थी। दिलचस्प है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6-ए के तहत यह प्रावधान है कि भारतीय मूल के उन विदेशियों को भी, जो 1996 से 1971 के बीच असम में आए और वहीं रह रहे हैं, नागरिकों की तरह सभी अधिकार दिए जाएंगे। बस, उन्हें दस वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में इन प्रावधानों को सांविधानिक माना था। ऐसे में, उन वंचित लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखना अमानवीय होगा, जो हमारे अपने नागरिक हैं, मगर किसी कारणवश एसआईआर में शामिल नहीं हो सके।

इस बात के भी पुख्ता सुबूत हैं कि बंगाल में जिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया, उनमें से अधिकतर नागरिक और मतदाता पाए गए। अपीलीय न्यायाधिकरणों से करीब 98 फीसदी लोग मतदाता सूची में शामिल हुए। इसी तरह, बिहार में भी इस प्रक्रिया का नुकसान गरीब महिलाओं को उठाना पड़ा है। वहां अगस्त 2025 की मतदाता सूची में 3.4 करोड़ महिलाएं थीं, जो संख्या जनवरी, 2025 की सूची से 31 लाख कम है।

एसआईआर को मुख्यतः मतदाता सूची की शुद्धता और घुसपैठियों को हटाने के आधार पर सही बताया गया था। किंतु न तो बिहार में और न ही बंगाल में चुनाव आयोग ने उन विदेशियों की सही संख्या बताई, जिन्हें उसने मतदाता सूची से हटाया है। अगर यह संख्या इतनी कम है कि उसका उल्लेख करना भी उचित नहीं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि जिन लाखों मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वे न तो विदेशी हैं और न घुसपैठिए। आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए कि उनकी नागरिकता साबित करने का बोझ उन्हीं लोगों पर डालना चाहिए, जो यह दावा करते हैं कि वे नागरिक नहीं हैं। विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत भी सुबूत का बोझ हम इन लोगों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि वे ऐसे विदेशी नहीं हैं, जो अवैध रूप से देश में घुसे हैं। उनके भारत में प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने भी माना है कि वर्तनी की गड़बड़ियों के कारण बंगाल में एसआईआर में विसंगति हो सकती है।

एसआईआर के फैसले में चुनाव आयोग की बड़ी जीत यह थी कि अदालत ने उसके 11 दस्तावेजों की सूची कायम रखी, हालांकि उसने 'आधार' को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वयं जोड़ा था। दिलचस्प है, बिहार में लगभग 37 फीसदी वयस्कों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं था, जबकि 15 से 22 दस्तावेज होने के बावजूद लोगों को असम में एनआरसी से बाहर रखा गया। यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी को भी मान्यता न देकर चुनाव आयोग अपनी ही मतदाता सूचियों के खिलाफ जाता दिखा। अब अदालत ने भी माना है कि कोई मतदाता सूची दोषमुक्त नहीं हो सकती।

भारत की संस्कृति बहिष्कार के बजाय समावेशन की रही है। कृपया, इसे कमजोर न करें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

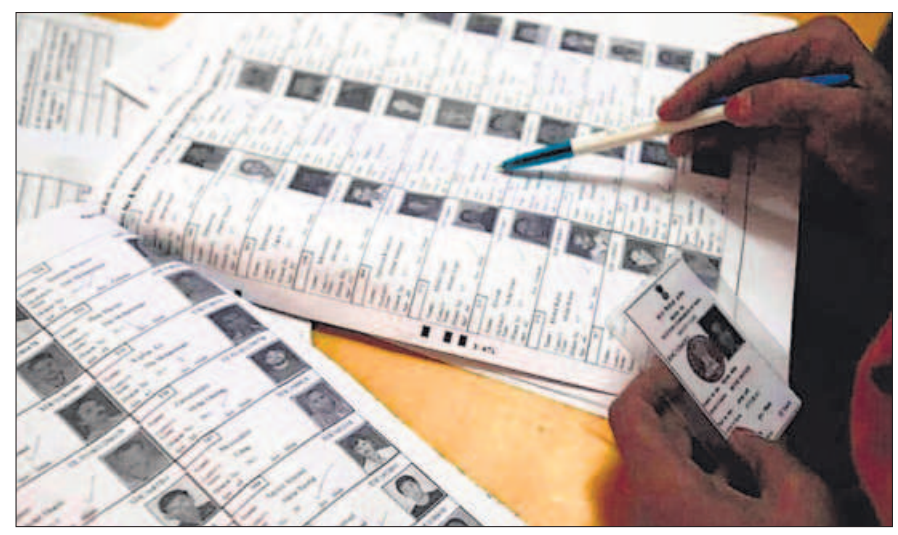

मनसा वाचा कर्मणा

ज्ञानी होने का मतलब

मुझसे पूछा गया है कि क्या ज्ञानी कभी पाप कर सकता है?

असल में, अज्ञानी ज्ञानी को जब देखता है, तो उसे उसके शरीर से एकरूप मान लेता है। चूंकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है, तो वह अपनी भूल का ज्ञानी पर भी आरोप करता है। इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता न होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर की चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह, वह ज्ञानी के शरीर को कर्म करते देख उसे कर्ता मानता है, पर ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी की अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता, अतः यह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है, ज्ञानी के लिए यह प्रश्न उठता ही नहीं।

ज्ञानी व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि वह किसी को अज्ञानी नहीं मानता। उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर करता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञान दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाशमय और शुद्ध ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोप को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है।

दो मित्र पास-पास सो गए। उनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वे दोनों लंबी यात्रा पर निकले हैं और दोनों को विचित्र अनुभव हुए हैं। जगने पर उसने इन घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है? दूसरे ने उसका उपहास करते हुए कहा, वह स्वप्न केवल उसी का था, जो दूसरे किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरों पर आरोपित करता है।

रमण महर्षि

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

स्वस्थ पर्यावरण ही समृद्ध भविष्य की नींव है। हमें टिकाऊ जीवन, प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित दुनिया के निर्माण की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करना चाहिए।

यह आग तंत्र की विफलता का प्रमाण

दिल्ली एक बार फिर आग की एक भयावह त्रासदी का गवाह बनी है। 3 जून, 2026 को मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। कई लोग घायल हुए। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि तंत्र की असफलता का प्रमाण है। यह बताता है कि नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जिस भवन को केवल छह कमरों की अनुमति मिली थी, उसमें 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं था। यह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ था। सवाल यह है कि यह सब इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा? क्या किसी विभाग ने कभी निरीक्षण नहीं किया? सच यह है कि ऐसे मामले केवल व्यक्तिगत लालच का परिणाम नहीं होते, बल्कि इनके पीछे प्रशासनिक ढिलाई और जवाबदेही का अभाव भी होता है। जब नियमों को कागज तक सीमित कर दिया जाता है, तब दुर्घटनाएं त्रासदी बन जाती हैं। दिल्ली में अनियोजित शहरीकरण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। जब एक भवन अपनी क्षमता से कई गुना अधिक लोगों को समायोजित करता है, तब खतरा बढ़ जाता है। इसमें केवल सरकार से उम्मीद करना पर्याप्त नहीं होगा। समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। नागरिकों को होटल, मॉल या किसी सार्वजनिक भवन में जाते समय सुरक्षा-व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। यदि इस बार भी हम नहीं चेते, तो अगली त्रासदी बस समय का इंतजार कर रही है।

पुनीत उपाध्याय, टिप्पणीकार

देश भर में ग्रीष्मकाल में होटलों व पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बढ़ना नई बात नहीं है। ऐसे में, मालवीय नगर का होटल विगत 3 जून को जानलेवा अग्निकुंड में तब्दील हो गया। होटल की खामियां अग्निशमन विभाग और प्रशासन को उस समय नजर आई, जब अग्निकांड हो चुका। संज्ञान में आया कि होटल मे प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही दरवाजा था, होटल के पास अनिवार्य अनुमति और अग्निशमन विभाग की ओर से फायर एनओसी नहीं थी। व्यावहारिक रूप से देश के महानगरों में छोटी-छोटी जगहों में बने बहुमंजिले होटलों का यदि सर्वेक्षण किया जाए, तो अधिकांश होटलों की यही स्थिति है। समझ में नहीं आता कि हमारा प्रशासन समय रहते होटलों में अग्निशमन हेतु मूलभूत उपकरणों की समुचित जांच क्यों नहीं करता?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

अग्निकांड

जवाबदेही और सुधार से बचेगी जिंदगी

मालवीय नगर की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। घटना के दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह उस व्यवस्था की विफलता का भयावह प्रमाण थी, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे देश की जो आर्थिक-सामाजिक स्थिति है, उसमें इन्हीं आधे-अधूरे संसाधनों से काम चलाना हमारी मजबूरी है। इसलिए जरूरी है कि जो हमारे पास है, उसी को व्यवस्थित कर चौकस तरीके से काम लिया जाए।

देश में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। दिल्ली की घटना के एक दिन बाद ही बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें कई मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद गाजियाबाद में एक पीजी सह रेस्तरां में आग लगी। असल में, ये घटनाएं हमारे सामाजिक और राजनीतिक तंत्र के उन गहरे संरचनात्मक दोषों की ओर संकेत करती है।

भारत के अधिकांश महानगर आज अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। संकरी गलियां, अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक भीड़, पार्किंग की अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगभग हर शहर में सामान्य दृश्य बन चुके हैं। ऐसे में, प्रशासन, समाज और तमाम व्यावसायिक समूहों को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए काम करना चाहिए। हमारे लोग उन्नत और सुविधा वाली व्यवस्था में जाने की स्थिति में नहीं हैं। अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो व्यवसायी अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि उनके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या ही नहीं बचेगी। तब तो जो सुविधाएं कम खर्च करके लोग उठा रहे हैं, वे भी नदारद हो जाएंगी और समाज में और हाहाकार मच जाएगा।

विभा चौधरी, गृहिणी

आरबीआई ने कहा, कमजोर मानसून, अल नीनो और महंगी चीजों का दिखेगा असर

आसार: इस वर्ष महंगाई सताएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मलहोत्रा ने इस साल खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है। उन्होंने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया। इसके अलावा उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। वहीं, वास्तविक आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल की खुदरा कीमतों में मई से अब तक कुल 7.4 प्रतिशत और डीजल में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी का कुल महंगाई पर करीब 0.36 प्रतिशत का सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ दूसरे दौर के प्रभाव आने वाले महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में दिखाई देंगे।

वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का असर वाणिज्यिक एलपीजी, औद्योगिक कच्चे माल, रसायन, रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों जैसे अन्य कच्चे माल पर भी दिख रहा है। साथ ही, कच्चे माल की लागत बढ़ने के दूसरे चरण के प्रभाव आगे चलकर महंगाई पर दबाव डाल सकते हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के सामने रुपये की कमजोरी के कारण जरूरी सामानों के आयात पर असर महंगाई को बढ़ाने में मदद करेगी।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी और मानसून की अनिश्चितता की वजह से दाल, सब्जियों जैसी खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। अल नीनो की वजह से कृषि पैदावार पर भी असर हो सकता है।

इस वित्तीय वर्ष महंगाई का अनुमान

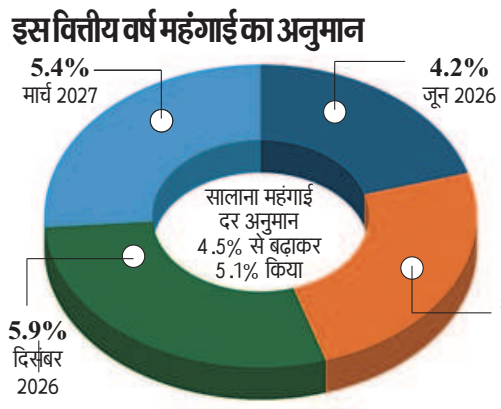

सालाना आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान

■ 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया

जून 2026 तिमाही 6.8% से घटाकर 6.6%	**दिसंबर 2026 तिमाही** 7.0 से घटाकर 6.5%
सितंबर 2026 तिमाही 6.7% से घटाकर 6.3%	**मार्च 2027 तिमाही** 7.2% से घटाकर 6.8%

मौद्रिक नीति में पांच प्रमुख ऐलान

1 महंगाई का अनुमान बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया, जो पहले 4.6 प्रतिशत था।

2 रेपो रेट स्थिर रखी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि आपके मासिक किस्त बढ़ने का फिलहाल कोई आसार नहीं है।

3 जीडीपी का अनुमान घटाया वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले आरबीआई ने 6.9 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान जताया था।

4 मानसून और अलनीनो का जोखिम आरबीआई ने कहा कि खाद्य महंगाई अब भी चिंता का एक प्रमुख विषय बनी हुई है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, आने वाले महीनों में मानसून की स्थिति कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों के रुझान को प्रभावित कर सकती है।

5 प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई देश में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अभी विचार के स्तर पर है। और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।

फैसला

रुपया संभालने के लिए विदेशी निवेशकों को छूट

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक निकाल लिए हैं जो पूरे 2025 के कुल बाहरी निवेश से भी ज्यादा है।

1. विदेशी निवेशकों को अधिक निवेश अवसर
पूर्ण सुलभ मार्ग से निवेश योग्य प्रतिभूतियों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसमें 15, 30 और 40 वर्ष की अवधि वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाएगा। अबतक 10 साल की अवधि शामिल थी।

2. एनआरआई-ओसीआई की निवेश सीमा बढ़ी
गैर-निवासी भारतीयों और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारतीय शेयरों और अन्य वित्तीय साधनों में अधिक निवेश की अनुमति दी गई है। यही सुविधा विदेश में रहने वाले सभी व्यक्तिगत निवेशकों को भी प्रदान की जाएगी।

3. विदेशी मुद्रा जमा प्रोत्साहन
बैंकों को विदेशी मुद्रा में एनआरआई जमा जुटाने के लिए हेजिंग लागत पर विशेष सुविधा दी जाएगी, जिससे डॉलर जमा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

4. मुद्रा अदलाबदली की छूट
विदेशी मुद्रा जुटाने वाली कंपनियों और बैंकों के लिए रियायती विदेशी मुद्रा अदलाबदली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डॉलर फंडिंग सस्ती होगी।

5. निर्यात आय अवधि बढ़ी
निर्यातकों के लिए निर्यात आय को भारत लाने की समयसीमा फिर से नौ महीने की गई है। आरबीआई के इस फैसले से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

6. सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स छूट
सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये विदेशी फंडों के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और ब्याज से आय पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स, दोनों खत्म कर दिए हैं। अगर कोई विदेशी निवेशक भारत के सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स			निफ्टी		
74,243 -116.67			23,366 -49.85		
टॉप गेनर			**टॉप गेनर**		
कंपनी	बंद भाव	बदलाव%	कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
हिंदुस्तान यूनि.	2121.80	2.10	अदाणी ईएनटी	3043.00	2.36
अदाणी पोर्ट्स	1823.10	1.82	हिंदुस्तान यूनि.	2121.20	2.01
टॉप लूजर			**टॉप लूजर**		
ट्रेंट	2774.65	-2.21	विप्रो	198.05	-3.07
टीसीएस	2198.25	-1.85	हिंडाल्को	1092.00	-2.99

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,59,900	-400
चांदी	2,60,700	-5,000

करेंसी
डॉलर/रुपया
95.18 +0.56

ई85 ईंधन पेश, पेट्रोल से ₹20 सस्ता

नई दिल्ली। सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए तैयार उच्च-एथनॉल मिश्रण वाले ईंधन ई85 को सामान्य पेट्रोल की तुलना में 20 रुपये प्रति लीटर की छूट पर शुक्रवार को पेश किया। यह ईंधन शुरू में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा और इसका उपयोग केवल फ्लेक्स-फ्यूल इंजन से लैस वाहनों में ही किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहां इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर ई85 ईंधन का अनावरण किया।

विदेशी मुद्रा भंडार 93.8 करोड़ डॉलर बढ़ा

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 मई को समाप्त सप्ताह में 93.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 682.32 अरब डॉलर हो गया। इसके एक सप्ताह पहले यह भंडार 7.51 अरब डॉलर घटकर 681.38 अरब डॉलर रह गया था। इस वर्ष 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

रुपया 56 पैसे उछलकर 95.18 प्रति डॉलर पर

मुंबई। रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी पूंजी प्रवाह को समर्थन देने और विदेशी मुद्रा तरलता मजबूत करने के उपायों की घोषणा के बाद शुक्रवार को रुपया 56 पैसे मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 95.18 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से निपटने के लिए काफी है। रुपया गुरुवार को दो पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

एक चौथाई परिवार इंटरनेट सुविधा से वंचित

नई दिल्ली। देश में मोबाइल फोन की उपलब्धता लगभग हर परिवार तक होने के बावजूद बड़ी संख्या में परिवार अब भी इंटरनेट से दूर हैं। एनसीईएआर की रिपोर्ट के मुताबिक, 95.1% परिवारों के पास मोबाइल फोन है, लेकिन 27.5% परिवार अब भी डिजिटल दुनिया से नहीं जुड़ पाए हैं। यह स्थिति देश में डिजिटल असमानता को उजागर करती है।

आरबीआई ने केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने केनरा बैंक पर 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) समेत कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर 41.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 31 मार्च, 2025 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निगरानी मूल्यांकन में यह पाया कि केनरा बैंक ने तय समय-सीमा के भीतर कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं किए थे।

विशेषज्ञ बोले, आगे चलकर बढ़ सकती हैं ब्याज की दरें

प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्याज दरों पर यथास्थिति रखने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को विशेषज्ञों ने संतुलित कदम बताया।

उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि 5.25 फीसदी पर रेपो दर को यथावत रखना कारोबारी धारणा को मजबूती देगा और आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि मजबूत बने रहने की उम्मीद है। यह निर्णय महंगाई को लक्षित दायरे में रखते हुए आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के बीच संतुलन को दर्शाता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि महंगाई अनुमान में बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि आने वाले समय में एक से दो बार ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। मानसून और वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विदेशी पूंजी प्रवाह (एफपीआई), बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और एनआरआई जमा पर उठाए गए कदम रुपये को मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक पहल है।

सेवा-कारखाना क्षेत्र ने संभाली वृद्धि की रफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। कारखाना और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने जीडीपी को सहारा दिया। इसी के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है।

शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान 7.3% था। इससे पहले तीसरी तिमाही की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर 8% दर्ज की गई थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7 फीसदी रही, जबकि फरवरी में इसका अनुमान 7.6% लगाया गया था। पिछले वित्त वर्ष में यह 7.1 फीसदी थी। मजबूत मांग और उत्पादन से अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी।

ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। सरकार के अनुसार, आधार वर्ष को अपडेट करने के साथ आंकड़ों के स्रोतों का भी विस्तार किया गया है।

सेवा और उत्पादन का दम : आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-मार्च तिमाही में सकल मूल्य वर्धन 7.9 प्रतिशत बढ़ा, जो यह दर्शाता है कि वृद्धि केवल मांग पर आधारित नहीं थी, बल्कि उत्पादन में मजबूती भी रही। उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन ने जीडीपी को सहारा दिया। हालांकि, इस तिमाही के अंतिम महीने मार्च में ही पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष का असर नजर आया, लेकिन यह तनाव जारी रहने से कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और आपूर्ति में पैदा हुए गतिरोध का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा।

7.7% रही देश की आर्थिक वृद्धि दर बीते वर्ष

7.8% रही बीते साल की अंतिम तिमाही में दर

आधार वर्ष बदला
जीडीपी को नए आधार वर्ष 2022-23 के पैमाने पर नई श्रृंखला के तहत जारी किया गया है। आर्थिक अनुमानों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए जीएसटी नेटवर्क, ई-वाहन डेटाबेस और कुक, ड्राइवर और की सेवाओं से जुड़ा डेटा भी शामिल किया गया है।

लोगों पर असर
नए आधार वर्ष का आम लोगों की जेब पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे सरकार, निवेशकों और अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया बदल सकता है। सही आंकड़ों से सरकार बेहतर नीतियां बना सकेगी। सही जगह पैसा लगेगा और विदेशी निवेश भी बढ़ेगा।

स्थिर दर से आवास क्षेत्र में मांग बढ़ेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने से आवास मांग बढ़ने की उम्मीद है। रियल एस्टेट कंपनियों के निकाय क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि आरबीआई ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला सोच-समझकर लिया है। ऐसे माहौल में रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिरता बनी रहने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दरों में कोई बदलाव न होने से आवास ऋण लेने वालों को राहत मिलेगी और उनकी ईएमआई पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि ब्याज दर को यथावत रखने का निर्णय अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सकारात्मक है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह कदम बाजार में स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करने में सहायक होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ब्याज दरों में स्थिरता मांग बढ़ाने वाला एक अहम कदम है, क्योंकि यह सीधे तौर पर घर खरीदने वालों की सोच, खरीदने की क्षमता और लंबे समय के निवेश की योजना पर असर डालती है।

इमामी रियल्टी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नितेश कुमार ने कहा कि आरबीआई का रेपो दर को यथावत रखने का निर्णय एक संतुलित और दूरदर्शी कदम है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए एक संतुलित और सोच-समझकर लिया गया फैसला है।

■ आवास ऋण लेने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा
■ रियल एस्टेट के लिए सकारात्मक निर्णय

अतिरिक्त ब्याज से जमा जुटाना गलत

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पहले से घोषित दर से अधिक ब्याज देकर जमा आकर्षित करना केंद्रीय बैंक को स्वीकार्य नहीं है।

हालांकि आरबीआई के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है और जमा की अवधि के आधार पर दरें अलग हो सकती हैं।

उन्होंने हालांकि एचडीएफसी बैंक से जुड़े मामले पर विशिष्ट रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि बैंक ने बड़ी राशि जुटाने के लिए अतिरिक्त भुगतान किया एवं उसे विपणन खर्च के रूप में दिखाया।

मत्स्य निर्यात 30 अरब डॉलर पहुंचेगा : गोयल

विशाखापत्तनम, विशेष संवाददाता। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने बीते साढ़े तीन वर्षों में नौ देशों के साथ सात मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं।

इन समझौतों से 38 विकसित और विकासशील देशों के बाजार भारत के लिए खुल गए हैं। ऐसे में भारत को अगले पांच वर्षों में मत्स्य उत्पाद (सीफूड) का निर्यात बढ़ाकर 30 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य हासिल करने का पर्याप्त अवसर है। इन देशों के साथ सभी एफटीए में मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के विशेष प्रावधान हैं।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि वैश्विक मत्स्य निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 से अधिक करने की दिशा में काम कर रही है। अधिक कार्गो हवाई अड्डे विकसित करने की भी योजना है।

गुणवत्ता से ना करें समझौता : चिराग

केंदीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन मौजूदा समय में उत्पादकता बढ़ाने के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने उत्पादकों व निर्यात को से आवाहन किया कि मुनाफा भले ही दो प्रतिशत कम कर ले लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। अगर हम उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करते हैं तो उनकी वैश्विक बाजार में मांग अधिक होगी।

अमेरिका से वार्ता तेजी से आगे बढ़ी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले महीने के मध्य तक व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दो से चार जून तक व्यापार समझौते को लेकर नई दिल्ली आयोजित बैठकों में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल साथ विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई।

भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका में बनाईं यूनिकॉर्न

उपलब्धि

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में 96 यूनिकॉर्न कंपनियां बनाने में भारतीय प्रवासियों का बड़ा योगदान रहा है। यह जानकारी एक अध्ययन में सामने आई है। अप्रैल 2026 तक अमेरिका की सभी 775 यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापकों के मूल देशों की जांच की गई। इसमें भारत 96 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर रहा।

नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अध्ययन में कहा गया कि भारतीय मूल के उद्यमियों ने या तो 96 अमेरिकी यूनिकॉर्न की स्थापना की है, या उनमें सह-संस्थापक रहे हैं। इनमें एआई आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल है। इसकी सह-स्थापना अरविंद श्रीनिवास ने की है। कंपनी का मूल्यांकन 20 अरब अमेरिकी डॉलर है और यह सूची में 12वें स्थान पर है।

अध्ययन के अनुसार, अमेरिका के यूनिकॉर्न स्टार्टअप के प्रवासी संस्थापकों के मूल देशों की सूची में भारत 96 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद इजराइल (60), ब्रिटेन (47), चीन (41), कनाडा (30), रूस (23), फ्रांस (21), जर्मनी (18), यूक्रेन (16), ऑस्ट्रेलिया (14), पाकिस्तान (10) और रोमानिया (10) का स्थान है।

अध्ययन के लेखक स्टुअर्ट एंडरसन के अनुसार, अमेरिका के निजी क्षेत्र में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों में 59 प्रतिशत (775 में से 455) की स्थापना या सह-स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की है।

रिपोर्ट में कहा गया कि प्रवासी संस्थापकों वाली इन कंपनियों ने औसतन प्रति कंपनी 833 रोजगार सृजित किए हैं।

वहीं, करीब 80 प्रतिशत यूनिकॉर्न में या तो प्रवासी संस्थापक हैं या फिर सीईओ अथवा इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष जैसे प्रमुख नेतृत्व पदों पर प्रवासी शामिल हैं। भारतीय मूल के छह संस्थापक मोहित अरोड़ा, ज्योति बंसल, आशुतोष गर्ग, अरविंद जैन, सचिन नायर और अजीत सिंह भी इस सूची में शामिल हैं।

■ नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अध्ययन में दावा
■ इजराइल 60 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे नंबर पर रहा

'सुधार एक्सप्रेस' को लेकर प्रतिबद्ध

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच सकारात्मक आर्थिक गति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीतारमण ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच सकारात्मक आर्थिक गति बनाए रखने के लिए निर्णायक नीतिगत उपायों के साथ 'सुधार एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री का यह बयान देश की जीडीपी के आंकड़े अनुमान से बेहतर आने पर आया है।

एलआईसी के भी तीन सौ करोड़ फंसे

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने का कारोबार करने वाली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स पर सेबी की कार्रवाई के बाद एलआईसी को सबसे बड़ा झटका लगा है। सेबी का आरोप है कि इस कंपनी ने फर्जी तरीके से 15.15 लाख करोड़ रुपये का राजस्व दिखाया है।

इस खबर के बाद से लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में गिरावट आ रही है। इस कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम के करीब तीन सौ करोड़ रुपये फंसे हैं।

सेबी की अंतरिम जांच में कथित तौर पर करीब ₹15.15 लाख करोड़ के राजस्व संबंधी अंतर और गलत प्रस्तुति की बात सामने आई है। हालांकि, कंपनी ने बीएसई पर जानकारी देकर अपना पक्ष रखा। कंपनी ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसकी सभी वित्तीय जानकारियां सही हैं। कंपनी ने आगे कहा कि सेबी के अंतरिम आदेश में किसी भी तरह की कोई अनियमितता की रिपोर्ट नहीं दी गई और सेबी ने कंपनी के खिलाफ कोई जुर्माना या कार्रवाई की घोषणा नहीं की।

राजेश एक्सपोर्ट्स में बीमा कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी

राजेश एक्सपोर्ट्स में भारतीय जीवन बीमा निगम की बड़ी हिस्सेदारी है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी के पास कुल 10.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। राजेश एक्सपोर्ट्स का शुक्रवार को बाजार पूंजीकरण करीब तीन हजार करोड़ रहा। ऐसे में एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 10.80 फीसदी के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपये फंस गए हैं। वहीं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के पास 14.19 प्रतिशत, रिटेल निवेशक के पास 14.55 प्रतिशत, एनआरआई और अन्य निवेशक के पास 4.81 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। बाकी 54.55 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी के मालिकों के पास है।

जरूर जानें एटीएम ऑपरेटरों को मार्च में उनकी जरूरत का सिर्फ 64% और अप्रैल में 57% ही नगद मिला, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक एक साल पहले की तुलना में 12% अधिक नगदी की बात कह रहा

नोट कम नहीं, एटीएम तक नगदी पहुंचाने के संकट से जूझ रहे हैं ऑपरेटर

■ कीर्ति झा

नई दिल्ली। एटीएम ऑपरेटर नगदी संकट की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। आरबीआई के अनुसार, 22 मई तक चलन में मौजूद नोटों का कुल मूल्य रिकॉर्ड ₹42.54 लाख करोड़ था, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 12% ज़्यादा हैं। फिर भी एटीएम ऑपरेटर चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ मशीनों में नगदी की कमी हो सकती है।

एटीएम ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था 'कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएस इंडस्ट्री' ने नगदी में भारी कमी की ओर इशारा किया है। 'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेटरों को मार्च में उनकी नगदी की ज़रूरत का सिर्फ 64% और अप्रैल में 57% ही कैश मिला। ऑपरेटरों को मार्च और अप्रैल में नोट भरने के लिए लगभग ₹94,000 करोड़ की जरूरत थी। मार्च में सिर्फ ₹61,000 करोड़ और अप्रैल में ₹54,000 करोड़ नगद ही उपलब्ध हो पाया। डेटा से पता चलता है कि एटीएम लेनदेन में घटकर 446.5 मिलियन रह गए, जो एक साल पहले 498.4 मिलियन थे।

बैंकिंग प्रणाली में नगदी की कमी नहीं

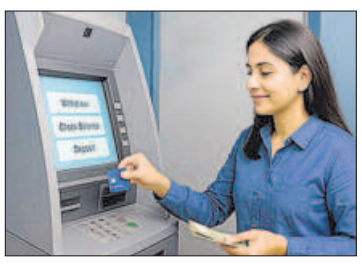

विशेषज्ञों के मुताबिक एटीएम में नकदी की कमी का मतलब यह नहीं है कि बैंकों के पास धन की कमी हो गई है। देश की बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी और तरलता मौजूद है। समस्या मुख्य रूप से एटीएम तक नगदी पहुंचाने और उन्हें समय पर भरने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। बैंकों में ग्राहकों के जमा धन पर किसी तरह का खतरा नहीं है और बैंक सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में एटीएम में दिखाई देने वाली अस्थायी कमी को बैंकिंग संकट के रूप में नहीं देखना चाहिए।

नगदी आपूर्ति, रीफिलिंग में दिक्कतें आ रहीं

संगठनों का कहना है कि नकदी प्रबंधन कंपनियों को एटीएम में समय पर नोट भरने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम तक नकदी पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में बैंक, करेंसी चेस्ट और कैश लॉजिस्टिक्स कंपनियां शामिल होती हैं। यदि किसी स्तर पर नगदी उपलब्ध कराने या उसके परिवहन में देरी होती है तो एटीएम खाली हो सकते हैं। इसके अलावा ईंधन, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स लागत में बढ़ोतरी ने भी एटीएम संचालन की लागत को प्रभावित किया है।

डिजिटल भुगतान ने घटाई नगदी पर निर्भरता

पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इससे रोजमर्रा के लेनदेन के लिए नगदी पर निर्भरता कम हुई है। यही कारण है कि एटीएम में अस्थायी नगदी कमी का असर पहले की तुलना में सीमित रहता है। अधिकांश उपभोक्ता डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में नकदी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

सावधानी बरतें ग्राहक

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ग्राहकों को घबराकर बड़ी मात्रा में नगदी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों को कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए।

- यूपीआई, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें।
- जरूरत पड़ने पर दूसरे बैंक के एटीएम का भी इस्तेमाल करें।
- आपात स्थिति के लिए सीमित मात्रा में नगदी अपने पास रखें।
- अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें।
- घबराने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत

mint

वीगन खाद्य उत्पादों पर लोगो अनिवार्य

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक जुलाई 2027 से वीगन खाद्य उत्पादों के पैकेट पर वीगन लोगो अनिवार्य कर दिया है। कंपनियों को लोगो का आकार, रंग और पैकेज पर उसकी जगह निर्धारित मानकों के अनुसार रखना होगा।

यह प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक (वीगन फूड्स) संशोधन विनियम 2026 के तहत लागू किया गया है। वीगन खाद्य वह उत्पाद हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की पशु-उत्पत्ति वाली सामग्री या अन्य प्रसंस्करण का उपयोग नहीं किया गया हो। ये पूरी तरह से पौधों (अनाज, फल, सब्जियां, नट्स) और खनिजों से बने होते हैं।